

प्रधान कार्यालय
अस्पताल रोड, आगरा-३

शाखाएँ
खजुरी बाजार, इन्दौर ● चौडा रास्ता, जयपुर

प्रथम सम्करण 1965
द्वितीय सम्करण 1966

मूल्य दो रुपये

भूमिका

यह पुस्तक बॉम्बे ऑफ मेमण्टरी एड्यूकेशन राजस्थान के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार नागरिक धान्य के अध्या 9 तथा 10 के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। यह प्रमाण दिया गया है कि विषय-नामकी मूल्य तथा अधिकतम में उद्योगों की सहायता में उन प्रसार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने कि वे समुदाय में रहें और अपने नागरिक व्यवहार अपने देश की सेवा में रहें हों।

यह अपने प्रमाण में नहीं तक मूल्य तथा है इनका निर्माण व्यवहारों को मूल पाठ्यक्रम पर ही है।

किसी उन मूल्य विद्यार्थियों का आसानी है जिसमें चिन्तन में इनके इन पुस्तक के लिखने में सहायता मिली है।

नेता

Syllabus of Civics

CLASSES IX & X

There shall be one paper of 2½ hours duration carrying 90 marks. It shall have two sections

Section B — Indian Administration and Citizenship

1. Introduction—An outline, study of the constitution of India—Birth of Indian National Congress—A brief history of the National Movement from 1920—1947.
2. Administrative set-up of Rajasthan down to the village.
3. Local Self Government in Rajasthan—Municipalities, Village Panchayats, Panchayat Samities and Zila Parishads—their composition and functions
4. Development Blocks in Rural Areas—their machinery and functions, Popular participation and growth of Co-operative Movement
5. Factors leading to the National Integration of India.
6. An outline study of the Third Five Year Plan in Rajasthan.

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ

भाग 1

राष्ट्रीय आन्दोलन एवं एकीकरण की समस्या

1—राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास	3
2—नवतन्त्र भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या	26

भाग 2

हमारे संविधान की सामान्य विशेषता

3—भारतीय संविधान के मुख्य-पक्ष	35
4—केन्द्रीय सरकार	46
5—राज्यों की सरकार	73

भाग 3

राजस्थान तथा उसका प्रशासन

6—राजस्थान का परिचय	93
7—राज्य का राज्य की कार्यपालिका	105
8—राज्य न्यायिक प्रशासन	111
9—क्षेत्र न्यायिक प्रशासन	122
10—न्यायिक प्रशासन	126
11—न्यायिक प्रशासन	136

भाग 4

राजस्थान में विद्योत्ति विभाग

12—राजस्थान में विद्योत्ति	145
13—राजस्थान में विद्योत्ति की समस्या, समस्या का समाधान	159

भाग I

राष्ट्रीय आन्दोलन एवं एकीकरण की समस्या

,

-

अतीत ने भारतीयों को हमेशा उठने के लिए ही प्रेरित किया। यद्यपि भारत अंग्रेजों के अधीन था परन्तु भारतीयों को सदा ही अपने उन्नतिशील अतीत से प्रेरणा मिलती रही जिससे पुन वे उन्हीं आदर्शों तक पहुँच सके। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, शांतिदूत बुद्ध तथा महान् राजनीति के ज्ञाता कौटिल्य के देश में यह सम्भव नहीं था कि अंग्रेज राष्ट्रीयता की भावना को समाप्त कर देते। अतः यह उदय हुई और अंग्रेजों के नष्ट करने पर, इसका और विकास हुआ।

(2) सामाजिक और धार्मिक पुनरुद्धार—19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक पुनरुद्धार हुआ उससे भी राष्ट्रीय चेतना के विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिला। राजा राममोहन राय ने समाज-सुधार आन्दोलन किया और भारतीयों को अन्वविश्वास छोड़ने के लिए सचेत किया। स्वामी दयानन्द ने भारतीयों को यह बताया कि 'भारत भारतीयों के लिए है, भारत माता को स्वतन्त्र करना भारतीयों का धर्म है। इस प्रकार स्वतन्त्र चिंतन की भावना का उदय हुआ, और लोगों ने उस समय प्रचलित दोषों को समझा और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करने लगे। शिक्षा का प्रचार करना, स्त्रियों की दशा में सुधार करना, बाल-विवाह का बहिष्कार करना, विधवा विवाह का प्रचार करना आदि राष्ट्रीय आन्दोलन के परिणाम थे। धार्मिक सहिष्णुता ने सब धर्मों के अनुयायियों को एक सूत्र में बाँधा और उस प्रकार सबके हृदय में देश-प्रेम की भावना जाग्रत हुई।

(3) समाचार-पत्र तथा साहित्य—प्रत्येक देश के वानावरण को बनाने में समाचार-पत्रों और साहित्य का बड़ा हाथ रहता है। भारतीय समाचार-पत्र तथा साहित्य भी उस वान में पीढ़े नहीं गये। अंग्रेजी पत्रों की तरह भारतीय भाषाओं में भी समाचार-पत्र उभरने लगे। उन पत्रों में प्रथम तो देश के कोने-कोने में राष्ट्रीय नेताओं के भाषण पहुँचें और उनमें राष्ट्रीयता का प्रचार हुआ। द्वितीय, उन पत्रों ने अंग्रेजों के शासनमोहिनी की कड़ी आलोचना करते-करते उनमें भारतीयों की जगमगातार आया। उस प्रकार ने इन

पक्षों ने भागीदारी में निर्भोक्ता पैदा की और राष्ट्रीय चेतना को जागा करने का योग प्रदान किया।

(4) आन्तरिक शांति—जब अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, इन समय अनेक छोटे-छोटे राजाओं और नवाबों में फूट रहती थी, परन्तु जब अंग्रेजी साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ तो आन्तरिक शांति और राष्ट्रीय राष्ट्रमन में सुस्था के कारण देश में ऐसा वातावरण पैदा हुआ जिसने लोगों का ध्यान समा-सुधार और राष्ट्रीयता की भावनाओं की ओर गया।

(5) बाह्य सम्पर्क व वातावरण के साधन—भारत का सम्पर्क दुनिया में विदेशों में रहा है। चीन से मुद्रा आपूर्ति भण्डों के कारण यह सम्पर्क कम हो गया था। परन्तु जब भारत में अंग्रेजी या साम्राज्य स्थापित हुआ तो फिर भारतीयों का सम्पर्क विदेशों में स्थापित हो गया। वातावरण के साधन भी बढ़े जब यह सम्पर्क और भी बढ़ा और वातावरण अन्य देशों में चल रहे ऐसे भी भारत के आन्तर्धान हो गए। इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना के उदय में सहायक मिली।

(6) सनसत भारत में शासन की एकरा—अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद सनसत भारत में पानी पान-परम्परा हो गई। इन सनसत भारत में सामंतीति समाप्त हुई। इन प्रकार भारतीयों के एक प्रकार के सामन में अनेक के सामन सामन का उदय हुआ जिसने राष्ट्रीय चेतना को जगाया।

(7) सम्पूर्ण देश की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रचलन—ब्रिटिश शासन की भाषा को सम्प्रदाय हो गई। यह क्षेत्रों के भाषा के दक्षिण सम्प्रदाय में इसे नीचा किया और भारत में स्थापित विचारों का सफल प्रसार होने लगा। इसका एक कारण यह कि इन के किसी भी क्षेत्र में यह राष्ट्रीयता की एक दृष्टि का एक सम्पूर्ण देश में फैल गई।

(8) पश्चिमी शिक्षा—अंग्रेजी शासन के सम्प्रदाय अंग्रेजी भाषा

भारत में आई जिसमें भारतीय पश्चिमी साहित्य और सभ्यता के सम्पर्क में आने लगे, और भारतवासियों का स्वातन्त्र्य-प्रेम और देश-प्रेम जाग्रत हुआ, जो राष्ट्रीयता के उदय में सहायक हुआ ।

(9) श्राथिक शोषण—भारत सोने की चिड़िया कहलाता था । अंग्रेज व्यवसायी बनकर उसी को लूटने आये और उन्होंने भारतीयों का शोषण किया । अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर लेने की और अपने देश के बने माल को अधिक दामों में बेचने की नीति अपनाई । परिणामस्वरूप भारतीयों का व्यवसाय नष्ट होने लगा और अंग्रेजों का व्यवसाय उन्नति करने लगा । इस प्रकार व्यवसायी, किसान आदि बहुत दुखी हुये । पढ़ा-लिखा समाज भी कम दुखी न था क्योंकि उनके लिए बड़ी नौकरियों के द्वार खुल गये । इस प्रकार की व्यवस्था से भारतीयों का जीवन दूभर हो गया था और उस अवस्था के विरोध की सृष्टि के साथ राष्ट्रीयता का उदय हुआ ।

(10) जातीय भेदभाव—सन् 1857 के बाद अंग्रेजों और भागीदारों में जातीय भेदभाव उत्पन्न हो गया जिसका राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारणों में मुख्य स्थान है । विद्रोह में पहले भारतीयों का अंग्रेजों में अच्छा सम्बन्ध था । अब अंग्रेजों की यह धारणा बन गई थी कि एक अंग्रेज का जीवन कई भागीदारों के बराबर है, अतः मनमाने ढंग में उस पर शासन किया जा सकता है । बड़े में बड़ा भागीदार छोटे में छोटे माहुर द्वारा अपमानित किया जाता था । ललनाजी का मनीष नष्ट हुआ था । उन्हीं मन्त्र परिणामों में भागीदारों का राष्ट्र भङ्ग और उन्हीं में राष्ट्रीय चेतना के विकास में बहुत प्रोत्साहन मिला ।

(11) नॉर्ड लिटन की साम्राज्यवादी नीति—नाट लिटन की नीति में भी राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन मिला । सन् 1877 में नाट लिटन द्वारा मराठानी विद्यापिठा के शासकी होने पर दिल्ली में पैसा पानी की तरह बहाया गया, जब कि दक्षिणी भारत में भीषण अन्धकार

कार्यक्रम निश्चित कर सके। नवम्बर, सन् 1885 में श्री ह्यूम इंग्लैण्ड में वापस आये और बहुमत से नवीन सम्मेलन का नाम 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' रखा गया।

कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य

कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे

(1) साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में देश के हित के लिए जो लगन में काम करते हैं उनके पारस्परिक सम्बन्धों को बढ़ाना।

(2) समस्त देश-प्रेमियों के सम्पर्क में विभिन्न जाति, वर्ग और प्रान्तगत विचारों को समाप्त करना।

(3) जो महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न हैं उन पर शिक्षित लोगों की अच्छी प्रकार राय लेकर उनका समग्रह करना, तथा

(4) उन ढंगों के विषय में निर्णय करना जिनमें भारतीय राजनीतिज्ञ देश के हित के लिए काम कर सकें।

उन प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय चेतना के उदय के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ।

(2)

राष्ट्रीय आन्दोलन का उदारवादी युग (1885-1905 ई० तक)

राष्ट्रीय आन्दोलन का पहला चरण जो कि 1885 में 1905 ई० तक माना जाता है, राष्ट्रीय आन्दोलन का उदार युग कहलाता है। उस युग में भारतीयों के विचार अंग्रेजों के प्रति उदार थे। उनका यह विश्वास था कि अंग्रेज न्याय-प्रेमी हैं। अगर उनसे प्राश्नाया द्वारा अपना अधिकांश मांगा जायगा तो वे उसे जरूर देंगे। उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन प्रमुखतः कांग्रेस ही कर रही थी।

उस युग में भारतीय नेता अंग्रेजी शिक्षा में पढ़े होने के कारण अंग्रेजों से प्रभावित थे और जो अंग्रेजों ने भारत में किया था उससे निरा

काल के नेताओं का अपमान करना है। वस्तुतः जिस समय यह आन्दोलन चला उस समय की स्थिति को ध्यान में रखकर उसकी ऐसी आलोचना करना उचित नहीं है। वैधानिक उपायों से भी कांग्रेस सफलता की ओर ही अग्रसर हुई। उदार राष्ट्रीयता-काल में भी कांग्रेस समय तथा परिस्थितियों के अनुसार अपनी शक्ति भर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्य करती रही और देशवासियों में वह उस भावना को भरने में सफल हुई जो स्वतन्त्रता के पथ पर आगे बढ़ सकने के लिये आवश्यक थी।

(3)

राष्ट्रीय आन्दोलन के उग्र तथा क्रान्तिकारी युग का संक्षेप

(सन् 1906 से 1920 तक)

जब प्राथमिक-पथों की नीति सफल नहीं हुई और अंग्रेजी सरकार भारतीयों के विस्तृत मनमाने कार्य करती ही गई तो वैधानिक उपायों में से भारतीयों का विश्वास उठने लगा। तिलक जैसे विचारकों ने कहा कि जिस प्रकार गंदी मांगने में नहीं मिलती उसी प्रकार स्वतन्त्रता भी नहीं मिल सकती। अब अब स्वतन्त्रता दबाव में लेनी पड़ेगी। वीरन्द्र घोष जैसे विचारकों ने तो कहा तक कहा कि हमें हिंसात्मक उपायों में स्वतन्त्रता लेनी चाहिए। उस प्रकार से ही विचारधारा का जन्म हुआ। पहले, वे जो उस नीति का मानते थे जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा राष्ट्रीय शान्त की व्यवस्था आदि। हमारे, वे जो क्रान्तिकारी तरीकों को अपनाते थे, जैसे दम, पिनाच द्वारा जानक फैलाना। उग्र तथा क्रान्तिकारी विचारधाराओं के उदय के मुख्य-मुख्य कारण निम्नलिखित थे

(1) अंग्रेजी सरकार के मनमाने और अनैतिकपूर्ण कार्य—उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन नीति की पारदर्शिता पर पड़ने वाला दा।

का प्रादुर्भाव हुआ और अंग्रेजों से जल्दी छुटकारा पाने के लिए उन्होंने उग्र और क्रान्तिकारी साधनों को अपनाया ।

(5) प्रकृति का प्रकोप—सन् 1896-97 में दक्षिण में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख मनुष्य पीड़ित हुए । सरकार ने इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया । भारतीय मसखियों की भाँति मरे । सरकार फीजी आक्रमण में लगी रही । सन् 1898 में महामारी के प्रकोप में 17 लाख 30 हजार व्यक्ति मरे । पूना में बीमारी का उपचार फीजी सिपाहियों को सौंपा गया । उन्होंने घरों में जाकर स्त्रियों की जाँच की । यह भारतीयों को पसन्द नहीं था । अतः असन्तोष फैला, और भारतीय उग्र तथा क्रान्तिकारी पथ पर चल पड़े ।

(6) बाहरी घटनाओं का प्रभाव—इटली अवीमीनिया में पराजित हुआ और जापान ने रूस को हराया । उस पर भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेजी फाँज अजेय नहीं है । अब देश-प्रेम और बलिदान के लिए भारतीय वमर बाँधकर तैयार हो गये । मध्य यूरोप और मध्य पूर्व देशों में जो जनप्रिय शासन के लिए आन्दोलन हुए उनका भी प्रभाव भारतीयों पर पड़ा । फक्त भाग्यवासी भी उन्हीं की भाँति उग्र और क्रान्तिकारी पथ पर बढ़े ।

(7) उदारवादी नीति की असफलता—जब उदारवादी असफल रहे तो उग्रवादियों का रोष बढ़ा । उन्होंने सोचा कि अब तक कांग्रेस जिस मार्ग पर चल रही है उसमें राष्ट्रीयता की भावना नाट हो जायगी । अब उन्होंने निश्चय लिया कि यदि सफलता प्राप्त करनी है तो उग्र और क्रान्तिकारी मार्ग का अपनाना आवश्यक है ।

उदारवादी तथा क्रान्तिकारी राष्ट्रीयता के उदय के कारणों को जानने के लिये यह जानना भी जरूरी है कि उग्रवादी आन्दोलन की प्रगति कैसे हुई ? सबसे पहले महागांधी महाराज गंगाधर तिलक ने महाड़ी पत्र 'केतकी' और अंग्रेजों पर 'महत्ता' लिखना जिसमें एक नवीन राष्ट्रीय

दागता के प्रति घृणा का संचार करते थे। इस प्रकार हमने देखा कि क्रान्तिकारियों ने आतंकपूर्ण ढंग से राष्ट्रीय आन्दोलन में योग दिया।

साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों का सूत्रपात व मुस्लिम लीग का जन्म

इस प्रकार के उग्र और क्रान्तिकारी आन्दोलनों को बढ़ता हुआ देखकर अँग्रेजों ने सोचा कि अब हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाय। अतः उन्होंने विभाजन और शासन की नीति अपनाई जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम लीग का जन्म हुआ।

मुसलमानों की इस समस्या का जन्म 30 मितम्बर, 1906 ई० को हुआ जिसका नाम 'अखिल भारतीय मुस्लिम लीग' रखा गया। पर अपने इस रूप में लीग को अभी पट्टे-लिखे मुसलमानों का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। श्री मोहम्मदअली जिन्ना, नैयद मोहम्मद, मोहम्मदअली आदि ने इसका विरोध भी किया और 'कामरेड', 'हमदर्द' आदि पत्रों में उन्होंने इस समस्या की जागृचना भी की। प्रगतिशील नेताओं ने लीग को कांग्रेस के साथ मिलाने की इच्छा में उसके विधान में परिवर्तन किया। कुछ परिवर्तन हो जाने में लीग कांग्रेस के समीप आने लगी। जब प्रथम महाभूट में मंत्र राजनीतिक दलों ने सरकार की सहायता का निश्चय किया तो मई 1916 में कांग्रेस तथा लीग ने भी एक शासन-सुधार की संयुक्त योजना बनाई। अब लीग और कांग्रेस में एक समझौता हुआ। जो कांग्रेस अभी तक पृथक् निर्गन्धन का विरोध कर रही थी उसने लीग की यह मांग स्वीकार कर ली। कांग्रेस की यह एक ऐसी भूल थी जिसका फायदा उसे देव के विभाजन के रूप में देना पड़ा।

युद्धकालीन राष्ट्रवाद

जून 1912 में कुछ मुसलमान नवयुवकों के हृदय में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने अब मुसलमानों को राष्ट्रीयता की ओर खींचा। इन नेताओं ने लीग के स्वरूप को बदला। यह समस्या

मुसलमानों का हित करती थी, परन्तु स्वराज्य के समबन्ध में उसने कांग्रेस की ओर भी ध्यान दिया। मुसलमानों में इस राष्ट्रीयता के उदय का पहला कारण प्रथम महायुद्ध के शुरू होने पर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति थी। इङ्ग्लैण्ड और रूस की नीति टर्की के विरुद्ध थी जिसका मुसलमानों पर खराब असर पड़ा और भारतीय मुसलमान इङ्ग्लैण्ड के विरुद्ध हो गये। यह विरोध टर्की के इङ्ग्लैण्ड पर आक्रमण करने में और बढ़ा। मन् 1911-13 के बाल्कन युद्ध के कारण टर्की में सभी सहानुभूति दिखाने लगे थे। इङ्ग्लैण्ड इस्लाम का शत्रु बन गया। अब भारत पर इङ्ग्लैण्ड का अधिकार राष्ट्रवादी मुसलमानों को खनने लगा। बंगाल का विभाजन करते समय अँग्रेजों ने मुसलमानों की राय न ली, इसने मुसलमानों को और भी राष्ट्रवादी बना दिया। 'अलहिनाल' नामक पत्र से आजाद ने मुसलमानों को निराशा के गर्त से निकाला। मोहम्मदअली ने भी 'हमदर्द' और 'कामरेड' से राष्ट्रीयता का प्रचार किया। अली को बंगाल के विभाजन के बाद अँग्रेजों में घृणा हो गई। जिन्ना ने लीग और कांग्रेस को बाँधने और मुसलमानों में राष्ट्रीयता का प्रचार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मन् 1915 ई० में आगा खाँ ने लीग का सभापतित्व छोड़ा जिसे जिन्ना ने ग्रहण किया। भविष्य के लिये यह तय हुआ कि कांग्रेस और लीग साथ-साथ काम करेगी। जिन्ना के सभापति होने में इनके कार्य में और अधिक सरलता हुई। लीग के अविवेचन में कांग्रेस नेताओं ने भी भाग लिया। कांग्रेस के सहयोग में भारत के लिये राजनीतिक मुद्दों की एक नई योजना बनाई गई।

लखनऊ पैक्ट

कांग्रेस और लीग के सहयोग से मन् 1916 में लखनऊ पैक्ट नामक समझौता हुआ जिसका समर्थन दोनों ने किया। इस पैक्ट द्वारा एकता पर बल दिया गया और स्वराज्य प्राप्ति की योजना बनी। दोनों समूहों ने एक होकर भारत के मुक्त होने की राई की।

गृह-शासन आन्दोलन

जब उग्र और द्राष्टिकारी रूपों के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन ने गृह-शासन (Home Rule) आन्दोलन का रूप धारण किया, सन् 1914 में जेल से आकर तिलक ने 'होम रूल लीग' की स्थापना की। ऐनी बेसेन्ट ने भी मद्रास में सन् 1916 में 'होम रूल लीग' स्थापित की। दोनों ने बड़े सहयोग से काम किया। कांग्रेस और लीग के मेल होने से दिसम्बर 1916 ई० में कांग्रेस तथा लीग ने सुधारों की एक सामान्य योजना को स्वीकार किया और कांग्रेस ने होम रूल लीगों द्वारा उस योजना का प्रचार करने का निश्चय किया।

होम रूल आन्दोलन एक वैधानिक आन्दोलन था। पर इसके कार्यकर्ता उदारवादियों की तरह याचना नहीं करते थे बल्कि उनकी मांग अधिकारपूर्ण होती थी। इनके अनुसार स्वशासन भारत का अधिकार था। बड़े ही उत्साह में इनके संचालकों ने उसमें कार्य किया। 1917 ई० में आन्दोलन उच्च शिखर पर पहुँच गया था। सरकार इसे सहन नहीं कर सकी, और सरकार ने दमन-चक्र चलाया। सरकार ने तिलक से जमानत माँगी, परन्तु हाईकोर्ट ने उस आज्ञा का समाप्त कर दिया। आन्दोलन बढ़ा और सरकार ने यह आज्ञा दी कि विद्यार्थी आन्दोलन में अलग रहें। नेताओं को नजरबन्द किया गया। उसमें देश में रोष बढ़ा। वे राष्ट्रवादी नेता जा अब तक अलग थे, उसी में मिल गये।

उसी बीच में युद्ध की स्थिति सम्भीत हो गई और उद्भव के बाद को जब भारत की सहायता की जम्हूरि हुई तो उसने भारत का स्वराज्य प्रदान करने का आश्वासन दिया। भारत-मन्त्री ने कहा कि परामर्श और जांच के बिना नुस्खे ही एक मिशन भारत लायगा। नरम दम के राष्ट्रवादी प्रसन्न हुए और उन्होंने नजरबन्द नेताओं का छुटने की मांग की और यह निश्चय किया कि भारत-मन्त्री जब भारत

आये तो उनके साथ सहयोग किया जाय । परन्तु उग्र दल के लोगो ने कहा कि यह सब अँग्रेजो की कूटनीति है, और इसलिये आन्दोलन जारी रखा जाना चाहिये ।

मॉन्टेग्यू मिशन भारत आया और उसने मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट भारत के शासन सुधार के सम्बन्ध में दी । इसी के आधार पर 1919 ई० का भारतीय शासन का अधिनियम बना । उग्रवादियो ने यह योजना अस्वीकार की । उनका सरकारी विरोध चलता रहा जिसने आगे चलकर असहयोग आन्दोलन का रूप धारण किया ।

(4)

राष्ट्रीय आन्दोलन का असहयोग युग (1920 से 1926 ई० तक)

युद्ध में भारत से सहायता पाने के लिये अँग्रेजी सरकार ने जो आश्वासन दिये थे उन्ही के आधार पर भारत ने धन-जन से उसकी सहायता की थी । परन्तु मॉन्टफोर्ड के सुधारों के रूप में भारत को जो मिला उससे भारतीय सन्तुष्ट नहीं हुए । युद्ध के बाद भारत की आर्थिक दशा और खराब हो गई थी । महामारी व अकाल से जन-जन की अपार हानि हुई ।

1915 ई० में गोखले और फिरोजशाह मेहता की मृत्यु हो गई । तिलक की मृत्यु के बाद 1920 में राष्ट्रीय आन्दोलन की वागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आई । वे जन-आन्दोलन की कला अच्छी प्रकार जानते थे । अतः उनके नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन सफल हुआ । युद्ध के समय महात्मा गांधी ने देखा था कि अँग्रेज न्याय से नहीं बरन् शक्ति के आधार पर मनमानी करते हैं । अतः उन्होंने यह घोषणा की कि भारतीयों के विरोध के बावजूद भी रॉलिट विवेक पास होने पर वे सत्याग्रह करेंगे । 30 अप्रैल, 1919 ई० को सत्याग्रह दिवस मनाने का निश्चय हुआ । सब जगह वह शान्तिपूर्वक मनाया गया, परन्तु दिल्ली व अमृतसर में दंगे हुए ।

इस समय दिल्ली में जो आतंक फैला उसे शान्त करने के लिये गांधीजी दिल्ली जाने लगे, तो उन्हें गिरफ्तार करके वापस भेज दिया गया, इसमें अमृतसर में आतंक फैला। वहाँ दो अंग्रेजों को मार डाला गया। सरकार की आज्ञा से डा० किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेजा गया और मीटिंगों की मनाही कर दी गई। परन्तु इसकी आज्ञा ठीक से जनता तक नहीं पहुँची और जलियावाला बाग में ब्रह्मास्त्री त्योहार के सम्बन्ध में मीटिंग हुई। उसे भग्न करने के लिए गोली चलाई गई, जिसमें 879 व्यक्ति मरे और 1200 घायल हुए।

गांधीजी इससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने वाइसराय की वापसी की मांग की। गांधीजी ने कहा कि जिन्होंने यह किया है उन्हें उचित दण्ड मिलना चाहिए। परन्तु ये कार्य उचित ठहराये गये, जिसमें विरोध की लहर दौड़ी और असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ।

युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता दी थी कि वे टर्की को कोई हानि नहीं पहुँचायेंगे। परन्तु युद्ध के बाद अंग्रेज अपने कहने पर न रहे और टर्की के विभाजन की योजना बनाने लगे। मुसलमानों ने टर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आन्दोलन चलाया। खिलाफत कमिटी ने असहयोग आन्दोलन में मिलने का निश्चय किया और उसे देश में फैलाने में सहायता की।

असहयोग आन्दोलन को गांधीजी ने 1 अगस्त, 1920 ई० को प्रारम्भ किया। यह तीव्रता से फैलने लगा। भारतीय जनता ने बड़े उत्साह में उसमें भाग लिया। मंत्रियों मजिस्ट्रेटों ने त्यागपत्र दिये, बकीला ने अदालत छोड़ी, विद्यार्थियों ने शिक्षा-संस्थान छोड़े। गांधीजी ने और मोतिलाल ने जेलों में सख्त जगह दाग दिया और सबका बड़ा स्वागत किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और मद्य-निषेध किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापित किया गया। सरकार उसे छोटी बात समझती थी, परन्तु जोर से उसने भरपूर रूप धारण कर लिया। उसने पन्द्रहवाँ नवंबर को अपना दमनक चलाया जिसमें कई

हिंसात्मक घटनाएँ हुई । 1921 ई० में दमन अधिक बढ़ा और भारतीय जेलों में ठूस दिये गये ।

8 जुलाई, 1921 ई० में कराँची में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने सेना की भरती का बहिष्कार करने का निश्चय किया और सरकार को यह धमकी दी कि वह गणतन्त्र स्थापित करेंगे और सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलायेंगे । इसी बीच मोपला में, जहाँ खिलाफत आन्दोलन जोरो पर था, उत्पात हो गया । सरकार ने अली भाइयों को गिरफ्तार करके 2 वर्ष की सजा देदी । इससे देश में हलचल और बढ़ी ।

17 नवम्बर को जब युवराज वेल्म के बम्बई आने पर दगा हुआ तो गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन को रोक दिया । गांधीजी ने 9 फरवरी, 1922 ई० को वाइसराय को एक पत्र लिखा कि अगर सरकार 7 दिन में अपनी नीति नहीं बदलती तो वे सविनय अवज्ञा वारदोली नामक स्थान में प्रारम्भ करेंगे । परन्तु इस पत्र के जाते ही चौरा-चौरी में हिंसा-काट हुआ जिसमें 22 पुलिस के सिपाही मारे गये । गांधीजी इसमें दुःखित हुए और उन्होंने 11 फरवरी, 1922 ई० को वारदोली की कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस आन्दोलन को रोकने का प्रस्ताव रखा । कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा को भी रोक दिया । गांधीजी ने सम्पूर्ण देश में अहिंसात्मक वातावरण उत्पन्न करने की प्रार्थना की । इस प्रकार असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया ।

असहयोग आन्दोलन 2 वर्ष में बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति किये ही समाप्त हो गया क्योंकि इस आन्दोलन के लिए जिस त्याग और समय की जरूरत थी, वह भारतीयों में न था । परन्तु इससे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में इस आन्दोलन का कोई स्थान नहीं । असहयोग आन्दोलन ने अंग्रेजों को यह दिखाया कि भारतीय भी अपने देश के लिए वलिदान करना जानते हैं । इस आन्दोलन ने भारतीयों को अहिंसा का एक ऐसा अस्त्र दिया जिससे आगे स्वतन्त्रता मिलने में बहुत सहायता मिली । यद्यपि इतने से काल में असहयोग

इस समय दिल्ली में जो आतंक फैला उसे शान्त करने के लिये गांधीजी दिल्ली जाने लगे, तो उन्हें गिरफ्तार करके वापस भेज दिया गया, इसमें अमृतसर में आतंक फैला। वहाँ दो अंग्रेजों को मार डाला गया। सरकार की आज्ञा में डा० किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करके अज्ञात स्थान पर भेजा गया और मीटिंगों की मनाही कर दी गई। परन्तु इसकी आज्ञा ठीक से जनता तक नहीं पहुँची और जलियावाला बाग में वसूखी त्यौहार के सम्बन्ध में मीटिंग हुई। उसे भंग करने के लिए गोली चलाई गई, जिसमें 879 व्यक्ति मरे और 1200 घायल हुए।

गांधीजी इसमें बहुत दुखी हुए और उन्होंने वाइसराय की वापसी की माँग की। गांधीजी ने कहा कि जिन्होंने यह किया है उन्हें उचित दण्ड मिलना चाहिए। परन्तु ये कार्य उचित ठहराये गये, जिसमें विरोध की लहर दौड़ी और असहयोग आन्दोलन शुरू हुआ।

युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की थी कि वे टर्कों को कोई हानि नहीं पहुँचायेंगे। परन्तु युद्ध के बाद अंग्रेज अपने कहने पर न रहे और टर्कों के विभाजन की योजना बनाने लगे। मुसलमानों ने टर्कों के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आन्दोलन चलाया। खिलाफत कमेटी ने असहयोग आन्दोलन में मिलने का निश्चय किया और इसे देश में फैलाने में सहायता की।

असहयोग आन्दोलन को गांधीजी ने 1 अगस्त, 1920 ई० को प्रारम्भ किया। यह तीव्रता से फैलने लगा। भारतीय जनता ने बड़े उत्साह में इसमें भाग लिया। सैकड़ों मजिस्ट्रेटों ने त्यागपत्र दिये, वकीलों ने अदालत छोड़ी, विद्यार्थियों ने शिक्षा-संस्थान छोड़े। गांधीजी ने और मानाना शक्ति अली ने सब जगह दौड़ा किया और सबत्र उनका वडा स्वागत किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सद्य-निषेध किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापित किया गया। सरकार इसे छोटी बात समझ रही थी, परन्तु जोश ही इसने भयंकर रूप धारण कर लिया। इसके पदस्वन्य सरकार ने अपना दमनचक्र चलाया जिसमें कई

हिंसात्मक घटनाएँ हुई । 1921 ई० में दमन अधिक बढ़ा और भारतीय जेलों में ठूस दिये गये ।

8 जुलाई, 1921 ई० में कराँची में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने सेना की भरती का बहिष्कार करने का निश्चय किया और सरकार को यह धमकी दी कि वह गणतन्त्र स्थापित करेंगे और सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलायेंगे । इसी बीच मोपला में, जहाँ खिलाफत आन्दोलन जोरो पर था, उत्पात हो गया । सरकार ने अली भाइयों को गिरफ्तार करके 2 वर्ष की सजा दे दी । इसमें देश में हलचल और बढ़ी ।

17 नवम्बर को जब युवराज वेल्स के बम्बई आने पर दगा हुआ तो गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन को रोक दिया । गांधीजी ने 9 फरवरी, 1922 ई० को वाडमराय को एक पत्र लिखा कि अगर सरकार 7 दिन में अपनी नीति नहीं बदलती तो वे सविनय अवज्ञा वार्दोली नामक स्थान में प्रारम्भ करेंगे । परन्तु इस पत्र के जाते ही चौरा-चौरी में हिंसा-कांड हुआ जिसमें 22 पुलिस के सिपाही मारे गये । गांधीजी इसमें दुःखित हुए और उन्होंने 11 फरवरी, 1922 ई० को वार्दोली की कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में इस आन्दोलन को रोकने का प्रस्ताव रखा । कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा को भी रोक दिया । गांधीजी ने सम्पूर्ण देश में अहिंसात्मक वातावरण उत्पन्न करने की प्रार्थना की । इस प्रकार असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया ।

असहयोग आन्दोलन 2 वर्ष में बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति किये ही समाप्त हो गया क्योंकि इस आन्दोलन के लिए जिस त्याग और समय की जरूरत थी, वह भारतीयों में न था । परन्तु इससे यह कभी नहीं मोचना चाहिए कि राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में इस आन्दोलन का कोई स्थान नहीं । असहयोग आन्दोलन ने अँग्रेजों को यह दिखाया कि भारतीय भी अपने देश के लिए बलिदान करना जानते हैं । इस आन्दोलन ने भारतीयों को अहिंसा का एक ऐसा अस्त्र दिया जिससे आगे स्वतन्त्रता मिलने में बहुत सहायता मिली । यद्यपि इतने से काल में असहयोग

आन्दोलन भारत को स्वतन्त्र न कर सका परन्तु इससे ऐसी जनशक्ति का प्रादुर्भाव अवश्य हुआ जिसकी प्रत्येक आन्दोलन के लिये आवश्यकता होती है ।

सन् 1922 में जब गांधीजी जेल चले गये तो भी असहयोग आन्दोलन का कार्य तीन माह तक चलता रहा । फिर एक सत्याग्रह समिति नियुक्त की गई । उसने अनेक सिफारिशों की जिसमें यह सिफारिश भी की गई कि सामूहिक सत्याग्रह बढ़े । छोटे रूप में सत्याग्रह किया जाय तथा काउन्सिल में प्रवेश किया जाय । काउन्सिल प्रवेश के प्रश्न पर कांग्रेस से अलग एक स्वराज्य दल की स्थापना हुई । सन् 1923 में इलाहाबाद में प्रथम स्वराज्य दलीय सम्मेलन हुआ । स्वराज्य दल का काम था कि वह सरकार को यह जता दे कि उसकी मांगें अस्वीकृत होने पर वह अड़गा नीति अपनायेगा । सन् 1924 में मोतीलाल नेहरू ने 1919 ई० के एक्ट में सशोधन की मांग की । 1925 में देशबन्धु की मृत्यु के बाद स्वराज्य दल का भार मोतीलाल पर आ गया । सन् 1926 में महात्मा गांधी ने सावरमती पैकट द्वारा फिर कांग्रेस व स्वराज्य दल में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया ।

(5)

राष्ट्रीय आन्दोलन का पूर्ण स्वतन्त्रता का युग (1926 से 1947 ई० तक)

महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप देश में दिन प्रतिदिन राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी । स्वराज्यवादी दल के कार्य ने यह बता दिया था कि मॉन्टफोर्ट जैसी योजनाओं से भारतीय सतुष्ट नहीं हो सकते । इंग्लैण्ड की सरकार ने इस कारण साइमन कमीशन की नियुक्ति की कि वह देखे कि किम प्रकार भारतीयों को स्वराज्य दिया जाय । परन्तु भारतीयों ने इसका विरोध किया । अंग्रेजों ने यह कहा कि भारतीय सम्मिलित रूप में अपना मविधान नहीं बना सकते । इसके उत्तर में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मे-

लन हुआ, जिसमे यह तय हुआ कि औपनिवेशिक स्वराज्य के आवार पर भारत का सविधान बनाया जाय । लीग के सिवा सवने इमे स्वीकार किया । कांग्रेस ने सम्मेलन की रिपोर्ट इस शर्त पर मानी कि 31 दिसम्बर 1931 ई० तक अँग्रेजी ससद उसे कानून का रूप दे दे, नही तो सरकार के साथ असहयोग किया जायेगा । परन्तु इन सब बातों से कुछ लाभ न होने पर स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए अग्रलिखित कदम उठाये गये ।

पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग

सन् 1929 की लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की । कांग्रेस के आदेश से 26 जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया । फरवरी, 1930 मे गांधीजी ने पुन सविनय अवज्ञा आन्दोलन का निश्चय किया और 12 मार्च, 1930 ई० को अपने 79 समर्थकों के साथ वे सौ मील की यात्रा के बाद डाडी पहुँचे । वहाँ उन्होंने नमक कानून तोड़ा । कांग्रेस समिति ने यह कहा कि सब देशवासी नमक बनायें, नशे की दुकानों पर धरना दें और सरकारी स्कूलों से त्यागपत्र दे । गांधीजी जेल चले गये ।

12 नवम्बर, 1930 ई० को प्रथम गोलमेज परिषद् इंग्लैण्ड मे बुलाई गई जिसमे यह कहा गया कि भारत मे (एक) सघीय योजना को लागू किया जायगा जिसके अन्तर्गत प्रान्तों मे उत्तरदायी सरकार तथा केन्द्र मे आणिक उत्तरदायी सरकार और गवर्नरों को विशेष अधिकार दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी । परन्तु कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वराज्य था । अतः उसने इस घोषणा को स्वीकार नही किया । इस पर बिना शर्त के गांधीजी जेल से छोड़ दिये गये और गांधी-इरविन समझौता हुआ । एक वर्ष के लिये सविनय अवज्ञा आन्दोलन रुका रहा । परन्तु जब द्वितीय गोलमेज परिषद् के लिये गांधीजी इंग्लैण्ड जाने लगे तो उसी समय समझौते से हुए सद्भाव समाप्त हो गये और गांधीजी वहाँ यह कहकर वापिस आये कि 'अब हमे अलग-अलग रास्तों पर चलना होगा ।'

गांधीजी के इंग्लैण्ड से वापिस आने पर स्थिति और गम्भीर हो गई । गांधीजी ने इस सम्बन्ध मे वाड्सराय से मिलना चाहा, परन्तु वाड्सराय

ने मिलने से इनकार कर दिया। गांधीजी और पटेल गिरफ्तार हुए। आन्दोलन पुनः जोर पकड़ने लगा। इसी बीच अंग्रेजी सरकार ने अछूतों को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया। इसका अर्थ हिन्दू समाज में साम्प्रदायिकता की जड़ जमाना था। इस पर गांधीजी ने आमरण अनशन किया जिसके कारण पूना में अछूतों व सर्वार्थ हिन्दुओं का पूना पैक्ट नामक समझौता हुआ। कांग्रेस ने यह स्वीकार किया कि अछूतों को 10 वर्षों के लिए विशेष संरक्षण प्रदान किया जाय, पृथक् निर्वाचन नहीं। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया तथा गांधीजी का उपवास टूटा। नवम्बर 1932 में तीसरी गोलमेज परिषद् में 1935 के अधिनियम के द्वारा की जाने वाली व्यवस्था स्वीकार हुई। सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त हो गया। कांग्रेस छोड़कर गांधीजी ने हरिजन उद्धार का कार्य अपनाया।

1935 का भारत सरकार अधिनियम

सन् 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट पास हुआ जिसके अन्तर्गत हुए चुनावों में बंगाल और पंजाब के अलावा सभी प्रान्तों में कांग्रेस जीती। जुलाई, 1937 ई० में कांग्रेस ने नवीन विधान के अन्तर्गत 8 प्रान्तों में अपने मन्त्रिमण्डल बनाये। 3 सितम्बर, 1939 ई० को जर्मनी के विरोध में इंग्लैण्ड ने युद्ध की घोषणा की। वाइसराय ने भारत में सहायता मांगी और इसके बदले में यह कहा कि '1935 ई० के एक्ट में ऐसे सुधार किये जायेंगे जो भारत के लिए उपयुक्त होंगे।' उन्ही समय कुछ करने की बात कहने पर वाइसराय ने टालमटोल की। इस पर कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने त्याग-पत्र दे दिया। इसी बीच 1940 ई० में लाहौर के अधिवेशन में लीग की ओर में पाकिस्तान की मांग की गई। सितम्बर 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने का निश्चय किया। गांधीजी ने उसका नेतृत्व किया जिसके परिणाम-स्वरूप वे जेल गये।

क्रिप्स मिशन

जून, 1941 ई० को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया। अप्रैल, 1942 ई० में क्रिप्स मिशन भारत आया और उसने भारतीय नेताओं की सलाह से एक योजना बनाई। योजना की शर्तें सभी दलों ने अस्वीकृत की और 11 अप्रैल, 1942 ई० को योजना वापस ले ली गई। अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा की कि अब भारत को युद्ध का आधार बनाया जायेगा। इस पर गांधीजी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। अनेक नेता गिरफ्तार हुए। सारे देश में कर मिटो या मर मिटो का आह्वान किया गया। यद्यपि आन्दोलन अहिंसा पर आधारित था परन्तु कई जगह हिंसा भी हुई। 2 वर्ष तक आन्दोलन चला। अनेक लोगों ने गुप्त रूप से रेलवे स्टेशन, डाकघर, पुलिस स्टेशन आदि जलाकर आन्दोलन में भाग लिया। इस पर जनता का दमन किया गया। इसी समय बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। युद्ध के समय भारत को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। सब नेताओं और गांधीजी को जेल में डाल दिया गया। 1944-45 में वे सब छोड़ दिये गये।

वैवल योजना व शिमला सम्मेलन

14 जून, 1945 ई० को लार्ड वैवल के कहने पर इंग्लैण्ड सरकार ने भारत के लिए एक योजना बनायी। जिसके अनुसार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य भारतीय होने थे। पर हिन्दू व मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के कारण शिमला सम्मेलन में वह योजना नेताओं द्वारा अस्वीकृत कर दी गई।

कैबिनिट मिशन योजना

जुलाई, सन् 1945 ई० में इंग्लैण्ड में मजदूर दल की सरकार आई। सन् 1947 में नौ-सेना के विद्रोह से अंग्रेजों को यह विश्वास हो गया कि अब भारतीय मेना पर बहुत दिनों तक विश्वास नहीं किया जा सकता। मजदूर दल ने 19 फरवरी, 1946 ई० को एक कैबिनिट मिशन भारत भेजा, जिसका काम भारत के शासन के आगामी

स्वरूप की योजना बनाना था । इस मिशन ने पहले भारत आकर यह कोशिश की कि कांग्रेस और लीग के समझौते के आधार पर योजना बनाई जाय, परन्तु सफलता न मिलने पर उसने स्वयं एक योजना बनाई । यह योजना सभी दलों को अस्वीकार्य रही, यद्यपि कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार अवश्य बनाई । इसके बाद इङ्ग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री ने कांग्रेस और लीग के नेताओं को बुलाकर किसी समझौते पर पहुँचने की कोशिश की परन्तु उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली ।

सत्ता हस्तान्तरण व विभाजन

लीग और कांग्रेस के आपसी मतभेद के कारण अब तक सभी योजनायें बेकार सिद्ध हुई थी । पर अब अन्तर्राष्ट्रीय व भारतीय परिस्थितियों के कारण इङ्ग्लैण्ड की सरकार को सत्ता का हस्तान्तरण करना पड़ा । मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँग कर रही थी । कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी । अतः 20 फरवरी, सन् 1947 को इङ्ग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री श्री ऐटली ने घोषणा की कि जून 48 तक भारत को सत्ता का हस्तान्तरण कर दिया जायेगा । योजना को कार्यान्वित करने के लिये लार्ड माउण्टबैटन को वायसराय नियुक्त किया गया । उन्होंने भारतीय नेताओं से मलाह करके निश्चय किया कि कैबिनेट मिशन की योजना को लागू न किया जाय तथा देश को साम्प्रदायिकता से बचाने के लिए उसका विभाजन कर दिया जाय । मुस्लिम लीग की तो यह इच्छा थी ही कि विभाजन हो । कांग्रेस ने भी परिस्थितियों से बाध्य होकर विभाजन स्वीकार कर लिया । 15 अगस्त, 1947 ई० को स्वतन्त्रता सन्ध्या के परिणामस्वरूप भारत में अंग्रेजी राज्य समाप्त हो गया, तथा भारत और पाकिस्तान के निर्माण के साथ-साथ भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई ।

(6)

महात्मा गांधी की देन

जिन समय भारत को स्वतन्त्रता मिली उस समय गांधीजी यद्यपि

कांग्रेस के प्रारम्भिक सदस्य भी नहीं थे, फिर भी इसमें सदेह नहीं कि भारत की स्वतन्त्रता महात्मा गांधी के प्रयत्नों का ही फल थी। महात्मा गांधी स्वतन्त्रता संग्राम के ऐसे मचालक थे जिन्होंने जनता की भाँति ही अपने को बना लिया था। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतन्त्रता के लिए ही आन्दोलन नहीं किया, बल्कि उनका लक्ष्य यह भी था कि भारतीय आन्तरिक दृष्टि से ही सबल बनें और समार के राष्ट्रों के बीच भारत को उचित सम्मान प्राप्त हो। कांग्रेस के सम्पर्क में आने से लेकर अन्त समय तक वे उसके मचालन का काम करते रहे। जब अन्तिम समय वे उससे अलग भी हो गये तो भी उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन का पथ-प्रदर्शन किया। वे राष्ट्रीय एकता के पुजारी थे। हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया और अन्त में इसी कारण उन्हें गोली का शिकार होना पड़ा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. राष्ट्रीय चेतना के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करिये।
2. कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
3. राष्ट्रीय आन्दोलन में उदारवादी युग के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिये।
4. राष्ट्रीय आन्दोलन में उग्रवादी तथा क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उसके कारणों पर प्रकाश डालिये।
5. मुस्लिम लीग पर एक छोटी-सी टिप्पणी लिखिये।
6. युद्धकालीन राष्ट्रवाद क्या है? संक्षेप में लिखो।
7. गृह-शासन आन्दोलन के प्रारम्भ होने के क्या कारण थे? इसकी कार्य-प्रणाली और प्रगति के सम्बन्ध में संक्षेप में लिखिए।
8. असहयोग आन्दोलन को किसे प्रारम्भ किया? वह कहाँ तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सका?
9. हमें स्वतन्त्रता किन-किन कठिनाइयों तथा प्रयत्नों के बाद प्राप्त हुई? संक्षेप में वर्णन करिए।
10. स्वतन्त्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने क्या योगदान दिया?

अध्याय 2

स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या

राजनैतिक भारत की सीमा समय-समय पर बदलती रही है। आज का भारत वह नहीं है जो कि अशोक के समय में या मुगल साम्राज्य के काल में था या जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के काल में था। वैसे भौगोलिक दृष्टि से तो यह सारा क्षेत्र एक कहा जा सकता है, पर राजनैतिक दृष्टि से यह बहुत कम समय पर एक रहा है। शक्तिशाली सम्राट और सेनापति उत्तर भारत से साम्राज्य विस्तार की इच्छा लेकर विजय यात्रा के लिये जाते थे और अपनी विजय का डंका बजाते हुए फिर वापस आ जाते थे। समुद्रगुप्त के काल में यही हुआ, अकबर ने यही किया, औरंगजेब ने यही करना चाहा, अलाउद्दीन के वीर सेनापति मलिक काफूर ने भी यही किया। पर ये विजय यात्रायें दीर्घजीवी नहीं होती थीं। सेनापतियों के पीठ फेरते ही ये सामन्त पुनः स्वतन्त्र हो जाते थे। यदि दुर्भाग्यवश केन्द्र में कोई कमजोर शासक हुआ, तो इन सामन्तों की शक्ति और भी बढ़ जाती थी।

ऐसा कहा जाता है कि कई बार अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने यह मित्र करने की चेष्टा की है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। यह साबित करने की चेष्टा करना कि अकबर के काल में भारत एक राष्ट्र था या समुद्रगुप्त के काल में भारत एक राष्ट्र था, व्यर्थ है, क्योंकि राष्ट्र का जो मतलब आज हमारे सामने है, वह उस काल में नहीं था। राष्ट्र की आधुनिक कल्पना तो 19वीं सदी में उत्पन्न हुई है और हमने उसके बाद जो पकड़ा है। उसके पहले राज्य होते थे या साम्राज्य होते थे

और इन राज्यों या साम्राज्यों की सीमाये सैनिकों, सेनापतियों और सम्राटों के बाहुबल के अनुसार बढ़ती या सिमटती रहती थी । एक साम्राज्य के अग होने के नाते हम में एकात्मकता की कुछ भावना उत्पन्न भले ही हो जाय, पर साम्राज्य की तुलना राष्ट्र से करना न्यायोचित नहीं दीख पड़ता ।

भारत के वर्तमान स्वरूप के निर्माण में अँग्रेजों का काफी हाथ रहा है । अँग्रेजों के आने के पहले न तो आवागमन के माधन इतने विकसित थे और न भाषा की एकता थी । इसलिए विचारों का आदान-प्रदान सुविधापूर्वक नहीं हो सकता था । यह तो नहीं कहा जा सकता कि यदि अँग्रेज भारत में न होते, तो रेल, तार या वायु-यातायान की सुविधाओं का विकास हुआ ही न होता, पर एक ऐसी भाषा जिससे कि मारे भारतीय एक-दूसरे से विचारों का आदान-प्रदान कर सकें शायद सम्भव न होती । आज अँग्रेजी के माध्यम से हम उत्तर, दक्षिण और पूर्व व पश्चिम सभी ओर के लोगों के विचारों से अवगत हो सकते हैं और उन्हें अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं ।

भारत में अनेक धर्मों के अनुयायी रहते हैं, अनेक भाषाएँ बोलने वाले लोग रहते हैं, उनकी विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है । इन सबों को एक सूत्र में बाँधने का श्रेय अँग्रेजी भाषा को है ।

भौगोलिक दृष्टि से भारत एक इकाई कहा जा सकता है । भौगोलिक एकता सदैव ही राजनैतिक एकता का प्रतीक नहीं होती । यद्यपि भौगोलिक एकता राजनैतिक एकता को लाने में सहायक हो सकती है, परन्तु भौगोलिक एकता को राजनैतिक एकता का टकसाली प्रमाण नहीं माना जा सकता । ब्रिटिश शासन काल में वर्तमान सीलोन, वर्मा, पाकिस्तान आदि सभी एक ही शासन में थे । पहले लका, अलग किया गया, बाद में वर्मा अलग किया गया और फिर पाकिस्तान का निर्माण हुआ । दार्शनिक दृष्टि से भारत एक रहा है । हिन्दुओं के तीर्थ स्थान भारत के चारों कोनों में हैं । वद्रीनाथ, रामेश्वरम्, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी

भारत के चारो कोनो मे है । धार्मिक मत्रो मे उत्तर भारत की नदियो के साथ दक्षिण भारत की नदियो का भी नाम लिया जाता है । भगवान बुद्ध के उपदेश अथवा शकराचार्य के वेदान्त-उपदेश देश के चारो कोनो मे ही फैले हुए हैं ।

परन्तु धार्मिक एकता राजनैतिक एकता का प्रतीक नहीं होती । अधिकांश यूरोपियन क्रिश्चियन धर्मानुयायी हैं, पर सारा यूरोप एक राष्ट्र नहीं है । नैपाल के निवासी भी हिन्दू हैं, परन्तु नैपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र है । पाकिस्तान के अलावा और भी दूसरे मुस्लिम देश हैं, पर वे सब मिलकर एक राष्ट्र नहीं हो सकते ।

राष्ट्रीय एकीकरण

इन सब उपरोक्त कारणों के कारण भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना उम सीमा तक विकसित नहीं हुई है जिसे सीमा तक योरोपीय देशों में यह पाई जाती है । प्रायः ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज शासकों की 'विभाजन कर शासन करने की नीति' के कारण भारत में राष्ट्रीय एकता का विकास नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेज शासक सदैव ही पृथक्करण के तत्वों को महत्त्व देते रहे । इन बातों में विश्वास करना हमारी देश-भक्ति का प्रमाण हो सकता है, पर इसे इतिहास की दृष्टि से प्रमाणित करना शायद सदैव सम्भव नहीं है । आज स्वतन्त्रता के सोलह वर्षों के बाद भी राष्ट्रीय एकीकरण के प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ी है । चीनी हमले ने हमें जर्मन एकता के सूत्र में बाँधा, पर उस खतरे के हटने के बाद फिर हम पुगनी रफ्तार में चलने लगे हैं । आज भी दक्षिण में द्रविड मुन्नेत्र कट्टम स्वतन्त्र दक्षिणावृत्त (द्रविडिस्तान) के लिये प्रयत्नशील हैं । भाषावाद के दगे, पंजाबी सूबे का आन्दोलन, साम्प्रदायिक दगे आदि इस बात के प्रमाण हैं कि हममें राष्ट्रीयता की भावना की कमी है । तत्कालीन शासकों की नीति चाहे जो रही हो, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शासकों की नीति तो बदनी है, परन्तु फिर भी जब ये

पृथक्करण की नीतियाँ सिर उठाती हैं तो इसके लिए केवल अंग्रेज-शासकों को ही दोषी ठहराना उचित नहीं कहा जा सकता ।

राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व

राष्ट्रीय एकता में निम्नलिखित तत्व बाधा डालते हैं —

(1) साम्प्रदायिकता—भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं । यदि धर्म केवल व्यक्तिगत विषय हो और लोग केवल अपनी मानसिक शान्ति के लिए धर्म का पालन करें तो अच्छी ही बात है, परन्तु धर्म यदि आपस में फूट पैदा करे और विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में एक-दूसरे से वैर रखें तो यह अनुचित है । आमतौर से इस प्रकार की शिकायतें होती ही रहती हैं कि हिन्दू अधिकारी हिन्दू-वर्मावलम्बियों के साथ पक्षपात करते हैं । इसी प्रकार मुस्लिम अधिकारी अपने धर्मावलम्बियों के साथ पक्षपात करते हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है । परन्तु सविधान की इस घोषणा का कोई खास मतलब नहीं निकल सकता, जब तक कि लोगों में भी धर्म-निरपेक्षता की भावना का प्रचार नहीं होता । कोई भी कानून, सविधान या साधारण विधेयक निरर्थक है, यदि लोग उसका सही ढंग से पालन न करें ।

(2) जातिवाद—दूसरी कठिनाई जातिवाद की है । जाति भारतीय समाज की एक विशेषता है । अन्य देशों में यह इस रूप में नहीं है । आज भी हमारे देश में मत जाति के आधार पर ही दिये जाते हैं । सभी दलों के प्रचारक, चाहे वे जातिवाद को कितना भी गलत बतलावे, अपने दल के उम्मीदवारों के लिए जातिवाद का उपयोग करने में नहीं हिचकते । अभी भी अधिकारियों में यह प्रवृत्ति देखने में आती है कि वे अपनी जाति वालों को प्राथमिकता देते हैं ।

(3) प्रान्तीयतावाद—आज भारत में लोग अपने को भारतीय नागरिक न समझ कर बंगाली, बिहारी, गुजराती, मद्रासी, राजस्थानी, पंजाबी आदि समझते हैं । यद्यपि सविधान में एक नागरिकता की घोषणा की गई है, परन्तु फिर भी प्रान्तीयता की भावना ने लोगों पर इस तरह

कब्जा जमा रखा है कि वे प्रान्त के सकुचित हितों के लिये राष्ट्रीय भावना को पीछे धकेल देते हैं ।

(4) भाषावाद—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भाषावाद के आधार पर हमारे देश का पुनर्गठन किया गया । इस पुनर्गठन के बाद देश में इस कदर दगे हुए कि उनके कारण हमारा सर शर्म के मारे नीचे झुक जाता है । बम्बई में गुजराती-मराठी दगे हुये, जिनमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गये । तेलगू भाषा-भाषी क्षेत्र के लिये श्री रामालू ने उपवास किया, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और आन्ध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा । मास्टर तारासिंह ने पंजाबी-भाषी क्षेत्र के लिए आन्दोलन किया और उन्होंने भी उपवास किया । राष्ट्र भाषा के प्रश्न को लेकर अभी हाल में मद्रास में जो उपद्रव हुये हैं, उनसे यही प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि में हम अब भी बहुत पीछड़े हुए हैं ।

(5) नैतिकता का अभाव—नैतिकता की कमी के कारण भी राष्ट्रीय एकता में बाधा आ पड़ती है, क्योंकि नैतिकता की कमी होने के कारण लोग अपने सकुचित स्वार्थों के लिये धर्म, जाति, प्रान्त, भाषा आदि का सहारा लेने लगते हैं । यह नैतिकता के अभाव का ही परिणाम है कि व्यक्ति किसी अधिकारी से यह सिफारिश करता है कि वह उसी के धर्म का अनुयायी है, उसी के प्रान्त का है, उसी की जाति का है या उसी की भाषा बोलता है और इसलिए उसे इस आधार पर कुछ मुवित्राएँ या प्राथमिकता मिलनी चाहिए ।

राष्ट्रीय एकता लाने के उपाय

(1) शिक्षा—आज अनपठ और पढ़े-लिखे दोनों ही व्यक्तिवाद, प्रान्तीयतावाद के शिकार हो रहे हैं । अतः यह कहा जा सकता है कि हमारी शिक्षा राष्ट्रीय एकता लाने के लिए सक्षम नहीं है । राष्ट्रीय एकता लाने के लिए शिक्षा-व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करना होगा, जिसमें शिक्षित व्यक्ति जो आगे चल कर समाज का नेतृत्व करेंगे अपने

को हिन्दू या मुसलमान, राजस्थानी या गुजराती अनुमूचिन या सर्वार्थ हिन्दू न समझ कर अपने को भारतीय समझें ।

(2) राष्ट्रीय जनमत का निर्माण—आज देश में यह भावना ही नहीं है कि सकुचित स्वार्थों की दृष्टि में कार्य करना राष्ट्रीयता के प्रति अपराध है, बल्कि ऐसा करने वाले को लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं । यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति के लोगों को नौकरी में मुविद्या देता है तो जाति या जनमत उमका बहिष्कार करने के बदले उसको आदर की दृष्टि से देखता है । उसके विषय में कहा जाता है कि वह बड़ा आदमी है जो विरादरी का ख्याल रखता है । जब तक हम इस भावना से परे नहीं उठ जाते, तब तक राष्ट्रीय एकता स्वप्न मात्र ही है ।

(3) स्वस्थ राजनैतिक वातावरण का निर्माण—राजनैतिक दलों को इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिये जिसमें पृथक्ता के तत्वों को कोई सहारा मिले । उन्हें अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जाति, प्रान्तीयता, धर्म, भाषा आदि के आधार पर अपील नहीं करनी चाहिए, चाहे उनके दल का उम्मीदवार चुनाव में हार जाय या जीत जाय ।

(4) गरीबी और बेकारी की समाप्ति—हमारे देश में गरीबी और बेकारी का प्रकोप है । एक गरीब और बेकार आदमी, जिसके लिए यह समस्या है कि आज रोटी मिलेगी या नहीं, अथवा बीमार पत्नी और बच्चे के लिए दवा कैसे आवेगी, जातिवाद, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता किसी भी तत्व के नाम पर अपना काम बनाने की चेष्टा करेगा और यह उसके लिये स्वाभाविक भी है । कोई भी व्यक्ति ऐसे समय में नैतिकता की दुहाई देकर हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता ।

श्रम्यासार्थ प्रश्न

- 1 भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पर एक छोटा निबन्ध लिखिए ।



भाग 2

हमारे संविधान की सामान्य रूपरेखा

भारतीय संविधान के मुख्य पक्ष

(1)

सविधाननेत्री सभा तथा संविधान का निर्माण

गाँधीजी के नेतृत्व में भारत का राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता गया और 15 अगस्त, 1947 को हमारा देश पूर्णतः स्वतन्त्र हो गया। स्वतन्त्रता प्राप्त करने का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ध्येय यह भी था कि भारतवासियों को अपने ऊपर न केवल शासन करने का अधिकार हो अपितु उन्हें उस शासन की रूपरेखा तथा उसकी प्रणाली निर्धारित करने का भी अधिकार प्राप्त हो। शासन की रूपरेखा एवं प्रणाली देश के सविधान में वर्णित की जाती है। अतः देश के सविधान का निर्माण स्वयं देश के निवासी ही करें, यह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक विशेष सिद्धान्त था। वास्तव में स्वतन्त्रता मिलने में कुछ पहले ही 9 नवम्बर, 1946 ई० को सविधान निर्माण करने हेतु एक सविधान सभा का गठन किया जा चुका था। सविधान सभा में उस समय के भारतीय राज्यों (प्रान्तों) की विधान सभाओं ने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा था जिन्होंने 26 नवम्बर, 1949 ई० को भारत के लिए नया सविधान प्रस्तुत किया। 26 जनवरी, 1950 ई० को भारत इसी सविधान के अन्तर्गत लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। इस सविधान का भली प्रकार अध्ययन करना स्वतन्त्र भारत के नागरिक की हैमियत से हर विद्यार्थी का कर्तव्य है ताकि वह प्रशासन की उस रूपरेखा एवं प्रणाली से परिचित हो सके जिसके

अन्तर्गत उसके देश की सरकार चलाई जाती है। सविधान का अध्ययन सुचारु रूप से करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि पहले हम उसके मुख्य लक्षणों की ओर ध्यान दें। भारतीय सविधान के मुख्य लक्षणों अथवा विशेषताओं का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं।

(2)

सविधान की प्रमुख विशेषताएँ

सविधान की विशेषताओं का उल्लेख निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत करना अधिक सरल एवं उपादेय रहेगा —

- (1) सविधान एक प्रलेख के रूप में।
- (2) सघीय सविधान।
- (3) लचीले एवं अपरिवर्तनशील सविधानों का समन्वय।
- (4) न्यायालय की स्वतन्त्रता।
- (5) मौलिक अधिकारों का उल्लेख।
- (6) राज्य की नीतियों का निर्देशन।

1 सविधान एक प्रलेख के रूप में

(अ) लिखित सविधान—भारत का सविधान लिखित है। इसका निर्माण एक विशेष रूप से गठित सविधान सभा द्वारा हुआ है। सविधान निर्माताओं ने विश्व के अन्य सविधानों का गहन अध्ययन करके प्रत्येक की अच्छी बातों का भारतीय सविधान में समावेश करने का सफल प्रयत्न किया है। स्वभावतः ही सविधान का आकार इस कारण बड़ा हो गया है। इसीलिए इसको विश्व के सबसे अधिक विस्तृत सविधान की सजा दी गई है।

(ब) राज्य के रूप की व्याख्या—हमारे सविधान में केवल सरकार के गठन और उसके अधिकारों एवं कार्य-क्षेत्रों का वर्णन ही नहीं है बल्कि इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि भारत में स्थापित राज्य का

स्वरूप क्या होगा ? सविधान के अनुसार भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की सरकार भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी होगी और उसी के द्वारा चुनी जायेगी । सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न राज्य का अर्थ यह है कि सविधान के अनुसार भारत अपनी नीति निर्धारित करने में किसी बाहरी शक्ति की राय से बाध्य नहीं होगा । अपनी नीतियों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा । गणराज्य का अर्थ यह है कि भारत का अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति वंशगत न होकर चुना हुआ होगा । लोकतन्त्रात्मक राज्य से यह मतलब निकलता है कि भारतीय जनता स्वयं अपनी शासक है । भारतीय सरकार का निर्माण स्वयं जनता करती है जिसके लिए उसे मत देने का अधिकार मिला हुआ है । प्रत्येक पाँच वर्ष बाद भारत में चुनाव करके जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं । बहुमत पाने वाले राजनैतिक दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मन्त्री नियुक्त किया जाता है जो कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में से अपने मन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है । स्वयं राष्ट्रपति जैसा कि पहले बताया जा चुका है, चुना जाता है । उसके चुनाव की प्रणाली का अध्ययन अन्य अध्याय में किया जायेगा । कहने का तात्पर्य यह है कि सविधान की यह एक विशेषता अथवा मुख्य लक्षण है कि इसमें भारत में स्थापित राज्य के स्वरूप का वर्णन किया गया है । इस स्वरूप का सविधान में उल्लेख किया जाना एक विशेष महत्त्व रखता है । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में इस बात पर बल दिया गया था कि भारतवासियों को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार है । इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें जनता जनार्दन के हाथों में अथवा उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता हो, लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था कहलाती है, और वह राज्य जहाँ का उच्चतम अधिकारी वंशगत अथवा स्वयं-निर्मित अधिनायक न होकर निर्वाचित किया गया हो गणतन्त्र कहलाता है । भारतीय सविधान में यह दोनों मुख्य लक्षण विद्यमान हैं ।

2 सघीय सविधान

भारतीय सविधान के अन्तर्गत एक सघ की स्थापना की गई है। भारत 16 राज्यों का एक सघ है। सविधान में केन्द्र और राज्यों के कार्य-क्षेत्रों और उनके अधिकारों की सीमाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। सविधान में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जो केन्द्रीय सरकार के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। राज्यों की सरकारों के अन्तर्गत आने वाले विषयों का उल्लेख एक अलग सूची में किया गया है। एक तीसरी सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर केन्द्र और राज्य दोनों की सरकारें कानून बना सकती हैं। इस प्रकार सविधान में केन्द्र और राज्य की सरकारों के कानून बनाने के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। यद्यपि सविधान के अनुसार राज्यों को उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य की सूची में दिए गये हैं फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से केन्द्र की सरकार को अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। केन्द्रीय सरकार के पास राज्य की सरकारों से अधिक शक्ति है और इसीलिए कुछ आलोचकों के अनुसार भारत में सघीय प्रणाली वास्तव में सघीय प्रणाली नहीं है। राज्यों को सघ से सम्बन्ध-विच्छेद करने का अधिकार नहीं है।

3 लचीलेपन एवं अपरिवर्तनशीलता में समन्वय

भारतीय सविधान की एक मुख्य विशेषता यह है लिखित होते हुए भी इसमें परिवर्तन आसानी से किये जा सकते हैं। लिखित और विस्तृत होने के फलस्वरूप इसमें उतना लचीलापन नहीं है जितना कि ग्रेट ब्रिटेन के सविधान में पाया जाता है। फिर भी हमारा सविधान इतना अपरिवर्तनशील भी नहीं है कि समय आने पर इसमें मशौघन करना मुश्किल हो जाये। हमारे सविधान में लचीले एवं अपरिवर्तनशील सविधानों की विशेषताओं का सुन्दर सम्मिश्रण है।

4 न्यायालय की स्वतन्त्रता

लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की विशेषता यह भी है कि उसमें

न्यायालय स्वतन्त्रतापूर्वक काम करे। विशेषकर सघीय सविधानो मे न्यायालय का कार्य और बढ जाता है। केन्द्र और राज्यो के कार्य-क्षेत्रो का एक दूसरे द्वारा उल्लघन यदि हो जाय तो भगडे का निवटारा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। सघीय सविधानो मे सविधान ही सर्वोच्च माना जाता है और सविधान की प्रतिष्ठा कायम रखने तथा सरकार द्वारा उसके उल्लघन के प्रति सजग रहते हुए सविधान की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। इसीलिए सघीय प्रणाली मे न्यायालय की स्वतन्त्रता पर इतना बल दिया जाता है। भारतीय सविधान मे भारतीयो को इसीलिए ऊँचा स्थान प्रदान किया गया है।

5. मौलिक अधिकारो का उल्लेख

न्यायालयो की सर्वोच्चता और स्वतन्त्रता का महत्त्व भारतीय सविधान मे इसलिए और भी बढ गया है क्योकि इसमे नागरिको को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिनकी रक्षा का उत्तरदायित्व भी न्यायालयो पर है। मौलिक अधिकारो का उल्लेख स्वय ही भारतीय सविधान की विशेषता है। यह अधिकार भारत के नागरिक को क्या प्रदान करते हैं, यह हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ यह लिखना ही पर्याप्त होगा कि भारतीय सविधान मे मौलिक अधिकारो का उल्लेख उसका एक मुख्य लक्षण है।

6 राज्य के नीति-निर्देशक तत्व

भारतीय सविधान मे केवल नागरिको के मौलिको अधिकारो का ही वर्णन नहीं है बल्कि इसमे राज्य के लिए कुछ नीति सम्बन्धी निर्देशन भी दिये गये हैं। दूसरे शब्दो मे हम कह सकते हैं कि हमारे सविधान मे नागरिको के अधिकार के साथ-साथ राज्य के कर्तव्यो का भी उल्लेख किया गया है। यह नीति-निर्देशक तत्व क्या हैं, इसका वर्णन आगे किया जायेगा। नीति-निर्देशक तत्वो के अन्तर्गत सविधान ने राज्य और राज्य की सरकार के सम्मुख कुछ ध्येय रखे हैं जिनको प्राप्त करना राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यतः सविधान ने राज्य का यह कर्तव्य बताया

है कि वह जनता की भलाई के लिए एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करे ।

7 धर्म निरपेक्ष राज्य

हमारे सविधान की एक विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत एक ऐसे राज्य की स्थापना की गई है, जो किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है । इसमें सभी धर्मों को समान स्थान और आदर प्रदान किया गया है । धर्म को राजनीति से अलग रखकर सविधान ने एक ऐसे राज्य की स्थापना का उल्लेख किया है जो धर्म निरपेक्ष हो ।

(3)

मूल अधिकार

सविधान की विशेषताओं का उल्लेख करने के पश्चात् उन मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन करना अत्यन्त आवश्यक है जिनकी प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता आवश्यक होती है और जो हमारे सविधान के अन्तर्गत हमें मिले हैं । अधिकारों के प्रति पूर्ण सचेत रहना इसलिए और भी आवश्यक है कि इनकी जानकारी हमें उस सविधान की रक्षा करने के हमारे कर्तव्य के प्रति हमें जागरूक करती है, जिसके अन्तर्गत हमें यह अधिकार मिले हैं । अधिकार की रक्षा सविधान की रक्षा में ही निहित है । तो वे अधिकार क्या हैं ?

1 समता का अधिकार

सविधान के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक समान है । न कोई बड़ा है और न कोई छोटा । कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं । सबको बराबर अवसर प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है । जाति भेद, लिंग भेद, धर्म भेद अथवा अन्य किसी अन्तर के फलस्वरूप भारतवासियों के बीच भेदभाव का वर्तन नहीं किया जा सकता । इस अधिकार का उल्लंघन चाहे वह राज्य की ओर से हो अथवा किसी व्यक्ति अथवा समुदाय की ओर से, सविधान के अनुसार ऐसा गैर-कानूनी होगा ।

2. स्वतन्त्रता का अधिकार

स्वतन्त्रता का अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विदेशी शासन से स्वतन्त्र हो जाना ही काफी नहीं है। इस स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए नागरिक को अन्य स्वतन्त्रताओं की आवश्यकता होती है जिसे प्राप्त करना एक स्वतन्त्र नागरिक का अधिकार है। सविधान के अन्तर्गत भारतीय नागरिक को विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता, भाषण की स्वतन्त्रता, संगठन करने की स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतन्त्रता, सम्पूर्ण देश में बिना रोक-टोक आने-जाने की स्वतन्त्रता आदि कई स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं।

3 शोपण के विरुद्ध अधिकार

सविधान के अन्तर्गत व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोपण को अवैध ठहराया गया है। नागरिक को अधिकार है कि वह शोपण का विरोध करे और बिना उचित पारिश्रमिक के काम करने में इनकार कर दे।

4 धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार

सविधान के अन्तर्गत धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को यह अधिकार प्राप्त है। राज्य किसी धर्म विशेष का संरक्षण नहीं करेगा।

5 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार

भारत में विभिन्न भाषा-भाषी लोग बसते हैं। यहाँ केवल भाषाएँ ही अलग-अलग नहीं हैं बल्कि भारत के निवासी विभिन्न संस्कृतियों के अनुयायी हैं। सविधान ने सबको यह अधिकार दिया है कि वे अपनी भाषा, संस्कृति एवं लिपि का संरक्षण करे और उसे बढ़ावा दे।

6 सम्पत्ति का अधिकार

प्रत्येक भारतवासी को सम्पत्ति रखने का अधिकार है। राज्य बिना

उचित मुआवजे के किसी व्यक्ति अथवा सस्था की सम्पत्ति पर अधिकार नहीं कर सकता ।

7 मौलिक अधिकारो की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारो के प्रयोग का अधिकार

यदि मौलिक अधिकारो पर राज्य अथवा राज्य का कोई कर्मचारी अथवा अन्य कोई व्यक्ति या सस्था कुठाराघात करता है, तो वह व्यक्ति अथवा सस्था जिसके अधिकार छिन रहे हो, संविधान द्वारा दिये गये उपचारो का प्रयोग कर सकते है । यह उपचार 5 प्रकार के होते है जो कि विभिन्न परिस्थितियों मे इस्तेमाल किये जा सकते है । उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नजरबन्द कर दिया गया हो, तो वह व्यक्ति न्यायालय मे बन्दी प्रत्यक्षीकरण के उपचार की माँग कर सकता है । यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सम्पत्ति पर अधिकार जमा रहा हो तो न्यायालय द्वारा संवैधानिक उपचारो के अन्तर्गत ऐसा करने से रोका जा सकता है ।

मौलिक अधिकारो का उपरोक्त वर्णन यह स्पष्ट करता है कि संविधान ने हमे व्यापक अधिकार प्रदान किये है । इन अधिकारो के सदुपयोग मे ही इनकी उपयोगिता और सकलता निहित है ।

(4)

राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व

मौलिक अधिकारो के पश्चात् राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वो का उल्लेख किया जाये । जैसा कि बताया जा चुका है, संविधान मे इन तत्त्वो का वर्णन है । संविधान के प्राक्कथन मे कुछ उद्देश्यो का जिक्र किया गया है जिनके अनुसार नागरिको के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन मे न्याय प्राप्त करने के लक्ष्य को अपनाया गया है । वह लक्ष्य तभी प्राप्त किये जा सकते है जबकि राज्य एक निर्धारित नीति पर चले । इस नीति का वर्णन राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वो मे किया गया है । इन तत्त्वो के अन्तर्गत राज्य का समस्त कार्य-क्षेत्र आ जाता

हैं। सविधान ने राज्य के सम्मुख कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य रख दिये हैं जिनको प्राप्त करना राज्य का कर्तव्य है। सविधान ने राज्य के लिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति अनिवार्य नहीं ठहराई है, परन्तु ऐसी आशा की जाती है कि राज्य इन उद्देश्यों के महत्व को समझकर इनको कार्यान्वित करने की भरमक कोशिश करेगा। उद्देश्यों की पूर्ति राज्य तभी कर सकता है जब देश की जनता इनके प्रति मजग हो। अतः इन तत्वों के विषय में जानकारी प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक है। यह तत्व निम्न-लिखित हैं —

1 आर्थिक न्याय सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व

सविधान ने राज्य के सम्मुख यह उद्देश्य रखा है कि वह ऐसे कानून बनाये एवं कार्य करे जिसके फलस्वरूप धनवान और निर्धन के बीच का अन्तर कम हो और आर्थिक दृष्टिकोण में कोई भी अन्याय का भागी न बने। स्त्री और पुरुष को समान काम के लिये समान वेतन मिले, और उत्पादन के साधनों का ऐसा बन्दोबस्त हो जिससे उनका प्रयोग जन-हित में हो सके और उनके द्वारा अर्जित धन किसी एक की तिजोरी में भरकर समस्त जनता के लिये कल्याणकारी हो सके। राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे सबको आराम मिल सके और जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति शिष्ट जीवन व्यतीत कर सके।

2 सामाजिक हित सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व

समाज के कल्याण के लिये सविधान ने राज्य के सम्मुख महत्वपूर्ण कार्य प्रस्तुत किये हैं। राज्य को मादक वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये ताकि समाज में प्रचलित दोषों का निराकरण हो सके। बुराई में पेशन की व्यवस्था, पशुपालन में उन्नति के साधनों की उपलब्धि आदि कई उद्देश्य राज्य के सम्मुख रखे गये हैं।

3 न्याय, शिक्षा और जनतन्त्र सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व

भारत में उचित और आमान न्याय व्यवस्था स्थापित करना, शिक्षा के प्रसार के लिये उचित कदम उठाना और जनतन्त्र के विकास के लिये

पचायत राज को प्रोत्साहन देना भी राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत आता है। राज्य को यह आदेश दिया गया है कि सविधान के लागू होने के दस वर्ष के अन्दर-अन्दर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

4 प्राचीन इमारतों की रक्षा सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व

सविधान ने राज्य के सम्मुख प्राचीन इमारतों की रक्षा करने का उद्देश्य रखा है। इसके अनुसार कलात्मक प्राचीन इमारतों की कुरूपता और नष्ट होने से बचाने के लिये राज्य सक्षम कदम उठायेगा।

5 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी नीति-निर्देशक तत्व

सविधान ने केवल आन्तरिक विषयों से सम्बन्धित नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख ही नहीं किया है अपितु उसके अनुसार भारत की सरकार को विदेश-नीति में भी कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कदम उठाने होंगे। भारत का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी विदेशी नीति अपनाये जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का विकास हो तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और आदरणीय सम्बन्ध स्थापित हो। राष्ट्रों के बीच झगड़े शांतिपूर्ण बात-चीत द्वारा सुलझाये जायें।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि हमारा सविधान केवल राज्य की रूपरेखा और सरकार के ढाँचे के वर्णन तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह राज्य का उसके कार्यों में पथ-प्रदर्शन भी करता है। ऐसा विस्तृत तथा सम्पूर्ण सविधान अन्य देशों में नहीं मिलता। यह भारत के सविधान की मुख्य विशेषता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- 1 सविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ ? संक्षेप में लिखिये।
- 2 सविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए।

3. मूल अधिकार किसे कहते हैं ? वे कितने प्रकार के होते हैं ? संक्षेप में वर्णन करें ।
4. राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के बारे में आप क्या जानते हैं ?
5. राज्य के नीति-निर्देशक तत्व कितने प्रकार के होते हैं ? लिखिए ।

केन्द्रीय सरकार

जैसा पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भारत में सघीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में ससदीय सरकार की स्थापना की गई है। ससदीय सरकार का अर्थ है कि यहाँ वास्तविक सत्ता ससद के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल के हाथ में होती है। राष्ट्रपति अथवा राज्य का अध्यक्ष केवल वैधानिक कार्यपालिका होता है। इस अध्याय में हम बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार का संगठन किस प्रकार होता है और उसके क्या अधिकार हैं ?

(1)

राष्ट्रपति (वैधानिक कार्यपालिका)

भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है जिसके नाम से केन्द्रीय सरकार के सारे काम किये जाते हैं। राष्ट्रपति के पद के लिये वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएँ हो —

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) उसकी आयु 35 वर्ष अथवा उससे ऊपर हो।

(3) वह उन सभी योग्यताओं से परिपूर्ण हो जो कि ससद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है।

(4) वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो।

अब प्रश्न यह उठता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ? राष्ट्रपति को चुनाव में जनता स्वयं मतदान नहीं करती है बल्कि उसके द्वारा चुने गये प्रतिनिधि इस कार्य को सम्पन्न करते हैं।

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मण्डल होता है जिसमें केन्द्रीय समद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से मतदान करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल-मक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि ससद के सदस्य और विधान सभा के सदस्य के मतों की संख्या में मतुलन स्थापित हो। इसके लिए एक विशेष प्रकार की मतदान संख्या स्थापित करने की प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य का मत राष्ट्रपति के चुनाव में कितने मतों के बराबर होगा, यह पता चलाने के लिए राज्य की जनसंख्या को विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है और इस प्रकार जो भजनफल आता है उसे 1000 से पुन विभाजित करते हैं। इस तरह जो भजनफल निकलता है वह उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों के मत की संख्या के बराबर समझा जाता है, अथवा प्रत्येक सदस्य का एक मत उस संख्या के बराबर होता है। इस तरह प्रत्येक राज्य में विधान सभा के सदस्यों के मतों का हिसाब लगाया जाता है।

समद के सदस्यों के मतों की संख्या निकालने के लिए पहले तो समस्त राज्य की विधान सभाओं के सारे निर्वाचित सदस्यों की कुल मत-संख्या उपरोक्त विधि से निर्धारित कर ली जाती है। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसमें समद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दे दिया जाता है और इसके फलस्वरूप जो भजनफल निकलता है वही समद के प्रत्येक सदस्य की मत-संख्या के बराबर होता है।

राष्ट्रपति का कार्य-काल

राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रथा यह है कि एक व्यक्ति दो बार में अधिक राष्ट्रपति न चुना जाये। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर

राजेन्द्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति चुने गये थे। सविधान में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति दो बार से अधिक चुनाव न लड़ सके। राष्ट्रपति यदि चाहे तो अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पद से त्यागपत्र दे सकता है। वह महाभियोग के द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव रखने का अधिकार सदन के दोनों सदनों को प्राप्त है। प्रस्ताव रखने से पूर्व दो शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिए। प्रथम तो यह कि इस प्रकार का प्रस्ताव रखने की सूचना सदन को 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए और उस प्रस्ताव पर लोक सभा अथवा राज्य सभा (जिसमें भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाने वाला हो) की कुल सदस्य सख्या के एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह प्रस्ताव बहस के पश्चात् कम से कम कुल सदस्य सख्या के दो-तिहाई मनो से स्वीकृत होना आवश्यक है। इस प्रस्ताव को फिर दूसरे सदन में विचार के लिए भेजा जाता है। वहाँ भी उसे स्वीकृति के लिए $\frac{2}{3}$ मत प्राप्त होना आवश्यक है।

राष्ट्रपति को 10,000 रु० मासिक वेतन मिलता है जिस पर कोई आय कर नहीं लगता। इसके अतिरिक्त रहने के लिए मुफ्त मकान तथा अन्य भत्ते आदि मिलते हैं।

राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य

सविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियाँ मिली हुई हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग मन्त्रियों की सलाह से करता है। हम राष्ट्रपति के अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं —

राष्ट्रपति के अधिकारों को हम मोटे रूप से दो भागों में बाँट सकते हैं।

- (1) साधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार, और
- (2) असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार।

(1) साधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति के अधिकार

साधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति के अनेक अधिकार होते हैं। उनमें मुख्य रूप से राष्ट्रपति के अधिकार निम्न प्रकार में दर्शाये जा सकते हैं —

(अ) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार—सम्पूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है। राष्ट्रपति का सम्पूर्ण राज्यों के राज्यपालों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को तथा राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और आडीटर जनरल आदि की नियुक्ति करने का अधिकार है। राष्ट्रपति पहले सदन के बहुमत दल वाले नेता को प्रधान मन्त्री चुनता है। फिर प्रधान मन्त्री की सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है। वह सम्पूर्ण देश की सेना का प्रधान है। यदि सदन की स्वीकृति हो जाय तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह युद्ध की घोषणा कर दे या सन्धि कर ले। राष्ट्रपति सेना के कार्यों को अच्छी प्रकार चलाने के लिये नियम बनाता है। अर्थ समिति की नियुक्ति भी वही करता है।

(ब) विधि निर्माण सम्बन्धी अधिकार—राष्ट्रपति को कानून बनाने में बहुत से अधिकार प्राप्त हैं। वह सदन की बैठकों को बुलाता है तथा उन्हें स्थगित भी करता है। वह लोक सभा को भंग भी कर सकता है। वह सदन की बैठकों में भाषण देने तथा अपना मन्देश भेजने का भी अधिकारी है। कोई भी बिल तब तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। वह स्वीकार करने, अस्वीकार करने तथा परिवर्तित करने का भी अधिकारी है। वह अर्थ विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है। इसके साथ ही यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकार कर देता है परन्तु सदन उसे पुनः पास करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि सदन के अधिवेशन

होने के समय आवश्यकता हो जाय तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर दे। ये अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है उन्हें ससद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इन अध्यादेशों की अवधि 6 सप्ताह तक होती है। परन्तु इसके बीच में भी ससद को यह अधिकार है कि वह इन अध्यादेशों को रद्द कर दे।

(स) वित्त सम्बन्धी अधिकार—राष्ट्रपति वर्ष के आरम्भ में आने वाले वर्ष के लिये अनुमानित आय-व्यय का व्यौरा तैयार करवाता है। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं हो जाती तब तक कोई भी वित्त-विधेयक ससद के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

(द) न्याय सम्बन्धी अधिकार—राष्ट्रपति को न्याय के सम्बन्ध में विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये हैं। वह किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है या उसके दंड में कमी कर सकता है। यदि दंड ऐसे अपराध के लिये दिया गया हो जो सघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आता हो। उसे फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार प्राप्त है।

(2) असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति के अधिकार

सकटकालीन परिस्थिति में राष्ट्रपति जिन अधिकारों का उपयोग करता है वे असाधारण स्थिति के अधिकार कहलाते हैं। अचानक ही किसी भी आपतकालीन परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने पर उस स्थिति की देख-रेख करने के लिये नियम बनाने के पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किये गये हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन्हें हम सकटकालीन परिस्थितियाँ कह सकते हैं। सकटकालीन परिस्थितियाँ मुख्य रूप से तीन प्रकार की मानी गई हैं जो निम्नलिखित हैं —

(अ) युद्ध, आक्रमण अथवा आन्तरिक अशांति से उत्पन्न सकटकालीन परिस्थिति—सकटकालीन परिस्थिति आन्तरिक अव्यवस्था, अशांति और युद्ध या युद्ध की भावना में भी उत्पन्न हो सकती है।

ऐसी स्थिति में हमारा मघात्मक मविधान एकात्मक मविधान के रूप में बदल जायगा । राष्ट्रपति राज्यों को यह आदेश दे सकता है कि वे किस प्रकार से अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करें । ससद को यह अधिकार है कि ऐसे समय में वह राज्य की सूची में दिये गये किसी भी विषय पर कानून बनाये । ऐसी स्थिति में नागरिकों के स्वतन्त्रता सम्बन्धी मूलाधिकार स्थगित माने जाते हैं और किसी भी नागरिक को उन अधिकारों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं रहता । वह केन्द्र और राज्य के बीच की आय के वितरण में परिवर्तन करने का भी अधिकारी है ।

(व) राज्यों में वैधानिक तकरार से उत्पन्न सकटकालीन परिस्थिति— यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की सूचना पर या और तरह से यह यकीन हो जाय कि किसी राज्य में सकटकालीन स्थिति पैदा हो गई है और वहाँ का शासन सुचारु रूप में चलाना असम्भव है तो वह उस राज्य के सम्बन्ध में सकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकता है । ऐसी स्थिति में उस राज्य का शासन-प्रबन्ध राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है । राष्ट्रपति इस बात की भी घोषणा कर सकता है कि विधान-मण्डल की शक्तियों का भोग या तो ससद करेगी या ससद के अधीन रहकर किया जायेगा । परन्तु वह उच्च न्यायालय को अपने अधीन लेने का अधिकारी नहीं है ।

(स) आर्थिक सकटकालीन अवस्था— आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी सकटकालीन परिस्थिति की घोषणा की जा सकती है । ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति राज्यों को उनकी कार्यपालिका-शक्ति के उपभोग के सम्बन्ध में आदेश दे सकता है । साथ ही ऐसी परिस्थिति में राज्य और सघ के कर्मचारियों के वेतन में भी कमी की जा सकती है ।

उपर्युक्त तीनों प्रकार की परिस्थितियों की घोषणा लगभग 2 माह तक लागू रहती है, परन्तु यदि आवश्यक हो तो इस समय ससद की स्वीकृति से इसका नमय और अधिक बढ़ाया जा सकता है ।

इन समस्त अधिकारों को जान लेने के बाद यह जानना भी जरूरी है कि सकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति जो भी राज्य सम्बन्धी और शासन सम्बन्धी कार्य करेगा उसके लिये वह न्यायालय के सामने किसी भी तरह का उत्तरदायी नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का स्थान पद, शक्ति और सम्मान तीनों से ही विभूषित है।

उप-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का निर्वाचन, अधिकार और कर्तव्य जान लेने के बाद यह जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति की गैरहाजिरी में उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति के समस्त कार्यों का उपयोग करेगा। उप-राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल-सङ्गमणीय मत के गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जायगा। उप-राष्ट्रपति राज्य परिषद् का सभापति होता है। यह 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर या पदच्युत किये जाने पर उपराष्ट्रपति उसके सब कार्यों की देखभाल करेगा। राष्ट्रपति को सम्बोधित कर के उप-राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र को लिख सकता है। राज्य परिषद् के अविश्वास का प्रस्ताव पास करने पर उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। परन्तु राज्य परिषद् ऐसा लोक सभा की स्वीकृति पर ही कर सकती है। पद छोड़ने के 6 माह तक दूसरे उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन जरूरी है।

(2)

प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिमण्डल

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भारत में मसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। मसदीय प्रणाली की विशेषता यह है कि उसमें मन्त्रिमण्डल मसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमण्डल ही वास्तविक कार्यपालिका है। स्वतन्त्र भारत के नागरिकों की हैमियत से हमें यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि इस मन्त्रिमण्डल का संगठन किस प्रकार होता है और इसके क्या-क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं।

सगठन

आम चुनावों के पश्चात् मसद के निम्न सदन लोक-सभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है और फिर उसकी राय से मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि मन्त्रिमण्डल में कितने मन्त्री होंगे। मन्त्रियों की संख्या प्रधान मन्त्री की इच्छा पर निर्भर है। यद्यपि राष्ट्रपति ही अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है तथापि उसे प्रधान मन्त्री द्वारा बताये गये व्यक्ति को ही मन्त्री-पद की शपथ दिलानी पड़ती है मन्त्रियों की नियुक्ति में इस प्रकार राष्ट्रपति स्वतन्त्र नहीं। उसे प्रधान मन्त्री भी बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही बनाना पड़ता है। इस प्रकार कौन प्रधान मन्त्री होगा अथवा किस दल की सरकार मत्तारूढ़ होगी इसका निश्चय मतदान द्वारा होता है, अथवा नागरिक स्वयं तय कर देते हैं। राष्ट्रपति केवल जनता के निश्चय को वैधानिक रूप देकर कार्यान्वित कर देता है।

मन्त्री बनने के लिये यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति मसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य अवश्य हो। यदि कोई मन्त्री पद ग्रहण करने समय सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद संभालने के पश्चात् छ माह के अन्दर-अन्दर लोक सभा अथवा राज्य सभा का सदस्य होना चाहिये। और यदि वह इनमें असमर्थ रहता है तो उसे मन्त्रि-पद से त्यागपत्र देना होगा। मन्त्रिमण्डल के कुछ मन्त्री कैबिनेट (मन्त्रि-परिषद्) के सदस्य होते हैं। मन्त्रि-परिषद् वास्तव में मन्त्रिमण्डल की नीति निर्माण करने की संस्था होती है। प्रत्येक मन्त्री के अन्तर्गत एक अथवा एक से अधिक विभाग होते हैं। मन्त्री को उसके विभाग के नाम से ही जाना जाना है जैसे शिक्षा विभाग का मन्त्री शिक्षा मन्त्री कहलाना है।

सामूहिक उत्तरदायित्व

प्रत्येक मन्त्री व्यक्तिगत रूप से प्रधान मन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि वैधानिक रूप से प्रत्येक मन्त्री के अपने-अपने क्षेत्र में समान

अधिकार है। मन्त्रियों का राष्ट्रपति से सम्बन्ध प्रधान मन्त्री द्वारा ही होता है। प्रधान मन्त्री ही राष्ट्रपति का मुख्य परामर्शदाता है। सरकार की मुख्य नीतियों का निर्देशन प्रधान मन्त्री ही करता है। मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व सामूहिक है। सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल संयुक्त रूप से सरकार की नीतियों के लिये जिम्मेदार है। “सब प्रत्येक के लिये और प्रत्येक सब के लिए” की नीति का पालन करते हुए मन्त्रिमण्डल सम्पूर्ण लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। लोक सभा किस प्रकार इस उत्तरदायित्व का पालन मन्त्रिमण्डल से कराती है, उसका वर्णन सदन की व्याख्या के अन्तर्गत किया जायेगा। यहाँ यह कहना ही पर्याप्त होगा कि मन्त्रिमण्डल का अस्तित्व लोक सभा के उसके प्रति विश्वास पर निर्भर है।

कार्य-काल, वेतन आदि

मन्त्रिमण्डल का कार्य-काल जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है लोक सभा के विश्वास पर निर्भर है, फिर भी यह कहना उचित होगा कि मन्त्रिमण्डल लोक सभा में बहुमत दल द्वारा बनाया जाता है और जब तक यह बहुमत कायम है मन्त्रिमण्डल पर आँच नहीं आ सकती। इसलिये मन्त्रिमण्डल का कार्यकाल अनिश्चित होते हुए भी स्थाई है। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव में प्राप्त बहुमत के बल पर मन्त्रिमण्डल का स्थायित्व निर्भर है। अन्यथा कार्य-काल वही होता है जो कि लोक सभा का, यानी 5 वर्ष। मन्त्रियों के वेतन सदन निर्धारित करती है।

वैठके

मन्त्रिमण्डल की बैठकें प्रधान मन्त्री बुलाता है और उनमें अध्यक्षता करता है। इन बैठकों में सरकार की नीतियाँ निर्वाचित की जाती हैं। मन्त्रिमण्डल की बैठकों की सभी बातें गुप्त रखी जाती हैं। इन बैठकों में विचार-विमर्श के पश्चात् निर्धारित नीतियों से सम्बन्धित विधेयक सरकार सदन के समक्ष पेश करती है। विचार-विमर्श के समय प्रत्येक

मन्त्री को अधिकार है कि वह उन नीतियों को माने अथवा न माने । परन्तु मन्त्रिमण्डल में तय की गई नीतियों को तमाम मन्त्रियों को मानना आवश्यक होता है ।

अधिकार और कर्त्तव्य

मन्त्रिमण्डल को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श दे । सविधान के अनुसार मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति का परामर्शदाता है । परन्तु वास्तव में वह उन सभी अधिकारों का प्रयोग करता है जो राष्ट्रपति में निहित हैं । राष्ट्रपति के अधिकारों का वास्तविक भोगी मन्त्रिमण्डल है । इसका यह अर्थ हुआ कि व्यावहारिक रूप में मन्त्रिमण्डल वह सारे कार्य करता है जो राष्ट्रपति के हैं, यद्यपि सारे काम उसी के नाम से किये जाते हैं । सविधान के अनुसार मन्त्रिमण्डल केवल राष्ट्रपति को परामर्श देता है, उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है । परन्तु परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह मानने में इन्कार नहीं कर सकता । अतः मन्त्रिमण्डल ही वास्तविक कार्यपालिका है । सारे शासन की वागडोर ही उसी के हाथ में है ।

अब हम यह देखेंगे कि मन्त्रिमण्डल के क्या-क्या कार्य हैं ।

नीति-निर्माण

सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए नीति निर्धारित करना मन्त्रिमण्डल का मुख्य कार्य एवं कर्त्तव्य है । देश की उन्नति, आन्तरिक सुरक्षा तथा अन्य देशों के साथ सम्बन्धों के विषय में नीति मन्त्रिमण्डल ही बनाता है । युद्ध की घोषणा और उसमें सन्धि करना, दूसरे देशों से राजनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना, योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना, यह सब मन्त्रिमण्डल के ही कार्य हैं । सकटकालीन अवस्था में समस्त अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से मन्त्रिमण्डल ही करता है ।

विधि निर्माण

मन्त्रिमण्डल के मुख्य कार्यों में विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य विशेष महत्व रखते हैं। ससद में कौन से विधेयक प्रस्तुत किये जाते हैं, इसका निश्चय मन्त्रिमण्डल ही करता है। मुख्य सरकारी विधेयक मन्त्रियों द्वारा ससद में पेश किये जाते हैं।

बजट का निर्माण

देश की आर्थिक अथवा वित्तीय नीति का निश्चय करना भी मन्त्रिमण्डल का काम है। सरकार का बजट सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल मिलकर बनाता है। सरकार के सारे विभाग अपनी आर्थिक माँगों को वित्त मंत्रालय में भेजते हैं। तत्पश्चात् वित्त मंत्री बजट बनाकर ससद में पेश करता है।

उपरोक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि मन्त्रिमण्डल शासन का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। सम्पूर्ण शासन का उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल पर ही है।

मन्त्रिमण्डल में प्रधान मन्त्री का स्थान

प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष होता है। मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपति के बीच सम्बन्ध प्रधान मन्त्री द्वारा ही स्थापित किया जाता है। वह मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। मन्त्रिमण्डल के निर्माण में प्रधान मन्त्री मुख्य भूमिका अदा करता है। राष्ट्रपति को अन्य कार्यों में सलाह देना प्रधान मन्त्री का मुख्य उत्तरदायित्व है। प्रधान मन्त्री का यह कर्तव्य है कि वह शासन और व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में राष्ट्रपति को सलाह दे। प्रधान मन्त्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। उसे अपने दल का बहुमत प्राप्त होता है और इसलिए वह एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है। प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल की बैठकों में सभापति होता है। राष्ट्र की नीति निर्वाचित करने में उसका महत्वपूर्ण हाथ है। प्रधान मन्त्री ही मन्त्रिमण्डल द्वारा लिए गये निर्णयों को राष्ट्रपति तक पहुँचाता है। राष्ट्रपति, उच्च अधिकारियों राजदूतों

आदि की नियुक्ति करने में प्रधान मन्त्री की सलाह में काम करता है। प्रधान मन्त्री, मन्त्रिमण्डल का नेता है और इसलिए समस्त शासन व्यवस्था पर उसका व्यापक प्रभाव है। सरकार की ओर से मुख्य बात पर प्रधान मन्त्री ही वक्तव्य इत्यादि देता है। वास्तव में सरकार का कार्यकुशलता और सफलता प्रधान मन्त्री की योग्यता पर निर्भर है।

मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रपति

जैसा बताया जा चुका है कि मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति के अधीन एक संस्था है। यह राष्ट्रपति के ऊपर है कि वह मन्त्रिमण्डल की राय माने अथवा न माने, परन्तु समदात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति का मन्त्रिमण्डल के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। मन्त्रिमण्डल लोक सभा में बहुमत दल का होता है, अतः राष्ट्रपति उसका सलाह को मानने के लिए व्यावहारिक रूप में बाध्य है। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की नीतियों को प्रभावित अवश्य कर सकता है।

मन्त्रिमण्डल और समद

मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप में समद के प्रति उत्तरदायी होता है। मन्त्रिमण्डल द्वारा प्रस्तावित कोई विधेयक उस समय तक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जा सकता जब तक उसे समद स्वीकार न कर ले। समद मन्त्रिमण्डल पर प्रश्न पूछ कर, वित्तीय मांगों में कटौत करने और अविश्वास का प्रस्ताव लाकर, नियन्त्रण रखती है। मन्त्रिमण्डल का अस्तित्व लोक सभा के विश्वास पर निर्भर है। परन्तु व्यावहारिक रूप में यदि देखा जाय तो समद में मन्त्रिमण्डल के दल का बहुमत होने के फलस्वरूप समद को मन्त्रिमण्डल की नीतियों को स्वीकार करना पड़ता है। यदि मन्त्रिमण्डल लोक सभा में बहुमत खो बैठे तो उसे त्यागपत्र देना होता है।

मन्त्रिमण्डल वास्तव में उन सूर्य के समान है जिसके चारों ओर समस्त शासन-यन्त्र चक्कर लगाने हैं। वही प्रशासन की आत्मा है।

(3)

संसद

हमारा संविधान प्रजातन्त्रीय है यही उसकी मुख्य विशेषता है। जिसमें प्रजा राजसत्ताधारी होती है और जनता के ही प्रतिनिधि उसमें काम करते हैं। इस प्रकार स्वयं जनता ही अपने भाग्य का निर्माण करती है। हमारे संविधान द्वारा केन्द्र में एक व्यवस्थापिका सभा (कानून बनाने वाली) का निर्माण किया गया है जिससे प्रजातन्त्र को क्रियात्मक रूप प्राप्त होता है। इसी व्यवस्थापिका सभा का नाम संसद है क्योंकि यह जनता के प्रतिनिधियों की सभा होती है अतः यह जनता के राज सत्ताधारी होने का चिह्न भी है। यह जनता के हितों की वृद्धि करती है और उनका संरक्षण भी करती है। जनता के हितों की वृद्धि हो और उनका भली प्रकार संरक्षण हो सके इसके लिए संसद राष्ट्र-कल्याण सम्बन्धी विधि निर्माण करती है। भली प्रकार राष्ट्र का कल्याण हो मके इसलिए यह मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण भी रखती है ताकि लगन से राष्ट्र की सेवा सम्भव हो सके।

केन्द्र में व्यवस्थापिका सभा के दो मदन होते हैं। पहला लोक सभा और दूसरा राज्य परिषद्। इन्हीं दोनों सभाओं को सामूहिक रूप से संसद के नाम से पुकारा जाता है। राष्ट्रपति संविधान का आवश्यक अंग है ऐसा संविधान में लिखा गया है। संसद की बैठकों को बुलाना, विसर्जित करना और लोक सभा को भंग करना आदि सभी कार्य राष्ट्रपति करता है। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुए कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। अतः यदि हम बिना राष्ट्रपति के संसद की कल्पना करें तो वह निरर्थक प्रतीत होती है। हम अब अलग-अलग लोक सभा और राज्य परिषद् का अध्ययन करेंगे।

लोक सभा

लोक सभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 522 हो सकती

है। अधिकतर इस सभा के लोग राज्यों की जनता द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है फिर वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप में प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा 20 प्रतिनिधि सत्रीय प्रदेशों से नियम के अनुसार चुने जाते हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का विचार है कि एंग्लो-इण्डियन उचित मात्रा में लोक सभा में नहीं आ सके हैं तो उसे यह अधिकार है कि वह दो सदस्य एंग्लो-इण्डियन के लोक सभा में भेजे। परन्तु सविधान में यह लिखा है कि उपर्युक्त समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए ससद को यह अधिकार है कि वह प्रतिनिधित्व प्रणाली को निश्चित करने के लिए कानून का निर्माण करे। वर्तमान लोक सभा में राज्यों और मधीय प्रदेशों से 500 सदस्य हैं जिनकी तालिका निम्न प्रकार दी जा सकती है

राज्य अथवा प्रदेश का नाम

सदस्यों की संख्या

1.	आंध्र	(राज्य)	43
2.	आमाम	(")	12
3	बिहार	(")	53
4	गुजरात	(")	22
5	केरल	(")	18
6.	मध्य प्रदेश	(")	36
7	मद्रास	(")	41
8.	महाराष्ट्र	(")	44
9	मैसूर	(")	26
10	उड़ीसा	(")	20
11	पंजाब	(")	22
12	राजस्थान	(")	22
13	उत्तर प्रदेश	(")	86

14	पश्चिमी बंगाल	(राज्य)	36
15	जम्मू तथा काश्मीर	(,)	6
16	दिल्ली	(प्रदेश)	5
17	हिमाचल प्रदेश	(")	4
18	मनीपुर	(")	2
19	त्रिपुरा	(")	2
			<hr/> 500

इसके अलावा 5 सदस्य गण्टपति द्वारा नामजद किये गये हैं। जिनमे 2 आंग्ल-भारतीय जाति के हैं। 3 मे से असम जन-जातियो व अडमान निकोवार, लकाद्वीप, मिनिकाय और अमिनद्वीप से लिये गये है। इस प्रकार लोक सभा के समस्त सदस्यो की सख्या 505 है।

मतदाताओ की योग्यताएँ

यह ऊपर कहा जा चुका है कि लोक सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जायगा। वही व्यक्ति लोक सभा के सदस्यो को चुन सकते हैं जिनकी निम्नलिखित योग्यताएँ हो

(1) उनकी आयु 21 वर्ष से कम न हो।

(2) जो पागल, कोढ़ी, दिवालिया न हो तथा जिसने कोई अपराध न किया हो।

लोक सभा के सदस्यो की योग्यताएँ तथा उनकी कार्याविधि

लोक सभा के पद पर खडे होने के लिए निम्न योग्यताएँ जरूरी हैं

(1) व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) उसकी आयु 25 वर्ष मे कम नही होनी चाहिए

(3) उसके पास उन समस्त योग्यताओ का होना जरूरी है जो मसद नियम के अनुसार जारी करे।

(4) उसके लिये यह जरूरी है वह न कि तो सघीय सरकार में कोई लाभ का पद धारण किये हो और न राज्य की सरकार में ।

(5) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित न कर दिया गया हो ।

(6) वह दिवालिया न हो ।

लोक सभा का कार्य-काल 5 वर्ष तक होता है परन्तु इसके बीच में भी राष्ट्रपति के कहने पर इसे भंग किया जा सकता है । आपत काल में ससद एक वर्ष के लिये उसका समय बढ़ा सकती है परन्तु जब सकट-कालीन परिस्थिति समाप्त हो जाती है तो वह समय 6 माह से अधिक बढ़ा हुआ नहीं रह सकता ।

लोक सभा के अधिवेशन तथा उसके अधिकारी

राष्ट्रपति लोक सभा की बैठको को बुलवाता है तथा विमर्जित करता है । बैठको की पहली तथा दूसरी सभा में 6 माह से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए । प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले अधिवेशन में राष्ट्रपति को भाषण देना होता है ।

लोक सभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जो लोक सभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं । इनका कार्य-काल भी 5 वर्ष होता है परन्तु बीच में भी वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं । यदि वे निष्पक्ष होकर अपना काम नहीं करते या सविधान की अवहेलना करते हैं तो लोक सभा के सदस्य बहुमत में उन्हें पदच्युत कर सकते हैं । परन्तु पदच्युत करने के लिए 14 दिनों का नोटिस जरूरी है ।

लोक सभा के पदाधिकारियों के अधिकार

लोक सभा के सदस्यों को सविधान द्वारा अग्रलिखित अधिकार प्रदान किये गये हैं

(1) लोक सभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सभा में शान्ति और सुव्यवस्था रखे तथा उस पर अनुशासन भी करे ।

(2) अध्यक्ष सभा के सदस्यों के नियमों का संरक्षण करता है और

इस बात की ताकीद रखता है कि कोई उन नियमों का उल्लंघन न करे ।

(3) अध्यक्ष लोक सभा के क्या और कैसे नियम हैं उन पर व्याख्यान भी देता है । यदि अध्यक्ष को यह शका हो जाय कि अमुक विषय के सम्बन्ध में नियम क्या है तो वह नियम की व्याख्या कर सकता है या अमुक विषय के सम्बन्ध में अमुक नियम अनिश्चित है तो ऐसी स्थिति में वह नियम का निर्माण कर सकता है । नियमों के सम्बन्ध में वह जो घोषणा करता है उसे सभी सदस्यों को मानना पड़ता है ।

(4) लोक सभा का अध्यक्ष ही यह निश्चित करता है कि कौन सदस्य किस समय किस विषय पर बोलेगा ।

(5) वही किसी विषय की मत-गणना करवाता है और उसका परिणाम भी वही घोषित करता है ।

(6) कोई भी विधेयक अर्थ विधेयक है या नहीं इसका निश्चय अध्यक्ष ही करता है ।

ऊपर लिखे अधिकारों से हमें यह मालूम होता है कि लोक सभा में अध्यक्ष का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण है । जब अध्यक्ष सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसका सारा कार्यभार उपाध्यक्ष ही संभालता है और उसके वे सभी अधिकार होते हैं जो कि अध्यक्ष के होते हैं ।

राज्य परिषद्

मसद का द्वितीय मदन राज्य परिषद् है जिसका वर्णन हम निम्न प्रकार में कर सकते हैं —

राज्य परिषद् का संगठन

राज्य परिषद् के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 होगी । जिनमें से 238 निर्वाचित सदस्य होंगे और 12 मनोनीत किये हुए होंगे । 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे । उनमें वही सदस्य होंगे जो साहित्य, कला और विज्ञान का अच्छा अनुभव रखते हों और ज्ञाता भी

हों। शेष 238 सदस्य राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप में चुनेंगे। एकल-सक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा इनका चुनाव किया जायेगा। अभी तक राज्य परिषद् में 220 सदस्य हैं, जिनकी तालिका निम्न प्रकार में दी जा सकती है —

राज्य अथवा प्रदेश का नाम	सदस्यों की संख्या
1 असम (राज्य)	7
2 उड़ीसा („)	10
3 पंजाब („)	11
4 पश्चिमी बंगाल („)	16
5 बिहार („)	22
6 मद्रास („)	17
7. मध्य प्रदेश („)	16
8 महाराष्ट्र व गुजरात („)	27
9 उत्तर प्रदेश („)	34
10 आन्ध्र („)	18
11 केरल („)	9
12 मैसूर („)	12
13 राजस्थान („)	10
14 जम्मू तथा कश्मीर („)	4
15 हिमाचल प्रदेश (प्रदेश)	2
16 दिल्ली („)	3
17 मनीपुर („)	1
18 त्रिपुरा („)	1
<hr/>	
220	
<hr/>	

उपर्युक्त राज्यों व प्रदेशों में कुल 220 सदस्य हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये गये हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर राज्य परिषद् में 232 सदस्य हैं।

राज्य-परिषद् के सदस्यों की योग्यताएँ तथा उनका कार्य-काल

राज्य-परिषद् के सदस्यों की वही सब योग्यताएँ होनी जरूरी है जो कि लोक सभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं। परन्तु राज्य परिषद् का सदस्य 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति ही हो सकता है। कोई व्यक्ति लोक सभा और राज्य परिषद् दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता।

राज्य-परिषद् एक स्थाई संस्था है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल 6 वर्ष होता है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्यों को अपना पद छोड़ना पड़ता है।

राज्य-परिषद् के अधिवेशन तथा उसके अधिकारी

राष्ट्रपति ही लोक सभा की भाँति राज्य परिषद् के अधिवेशन बुलाता है, व उन्हें विमर्जित करता है।

राज्य परिषद् में सभापति और उप-सभापति दो अधिकारी होते हैं। उप-राष्ट्रपति राज्य परिषद् का सभापति होता है और उप-सभापति स्वयं परिषद् के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। उप-सभापति सभापति की अनुपस्थिति में या सभापति के पद ग्रहण करने से पूर्व उसका कार्य-भार संभालता है। राज्य परिषद् के सभापति के वही कार्य होते हैं जो लोक सभा के अध्यक्ष के होते हैं। परन्तु अन्तर यह है कि लोक सभा के अध्यक्ष की भाँति राज्य परिषद् का सभापति यह निश्चित नहीं करता कि कौनसा विवेक अर्थ विवेक है।

संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार

संसद के सदस्यों को स्वतन्त्रतापूर्वक और प्रभावपूर्वक अपने कतव्यों का संचालन करने के लिए संविधान ने कुछ विशेष अधिकार प्रदान किये

है। समद के सदस्यों को मसद में भाषण देने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। जो भाषण सदस्य देते हैं उसके लिए उन सदस्यों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उनके वक्तव्य पर जो दया जाता है उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा मसद के और भी कार्य हैं जिनका वर्णन हम निम्न प्रकार करेंगे —

मसद के कार्य

(1) विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य—प्रारम्भिक रूप से मसद कानून बनाने वाली मन्था है। राष्ट्र की उन्नति के लिए विधि का निर्माण करना मसद का मुख्य ध्येय है। अर्थात् विधेयको को छोड़कर कोई भी सदस्य किसी भी भवन में विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु व्यावहारिक रूप में महत्वपूर्ण विधेयक मन्त्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किये जाते हैं जो मसद विधेयको को स्वीकार तथा अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा और राज्य परिषद् में कोई मतभेद पैदा हो जाय तो दोनों मदनो की एक सामूहिक बैठक बुलाई जाती है।

(2) अर्थ सम्बन्धी कार्य—वजट पार करना मसद का मुख्य कार्य है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति की आज्ञा में करो के आय-व्यय का व्यौरा लोक सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। लोक सभा धन की मांगों को कम कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है परन्तु बढ़ा नहीं सकती। जब यह व्यौरा लोक सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर इसे वजट कहते हैं और फिर यह राज्य परिषद् के विचार के लिये भेजा जाता है। राज्य परिषद् 14 दिन में वजट पर अपनी सिफारिश भेज देती है। लोक सभा इन सिफारिशों को मंजूर भी कर सकती है और नामंजूर भी।

(3) सविधान में सशोधन सम्बन्धी अधिकार—मसद सविधान में सशोधन कर सकती है कोई भी भवन सशोधन के प्रस्ताव को रख

सकता है। जब तक सदस्यों का दो-तिहाई मत सशोधन को स्वीकार नहीं करता तब तक वह सशोधन प्रस्तुत नहीं हो सकता।

(4) प्रशासन सम्बन्धी अधिकार—संसद को प्रशासन सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं। मन्त्रिमण्डल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक सभा को यह अधिकार है कि यदि मन्त्रिमण्डल उचित रूप से कार्य को न सँभाले तो वह उसे पद से हटा दे। संसद मन्त्रिमण्डल से प्रश्न पूछकर नीतियों की व्याख्या करती है और उसकी नीति की आलोचना भी करती है। उसे स्वीकार और अस्वीकार भी कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाये, सचियों पर स्वीकृति दे तथा राष्ट्रपति की सलाह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा भी सकती है।

उपर्युक्त विवेचन से हमें यह भली-भाँति प्रतीत होता है कि लोक सभा का स्थान राज्य परिषद् से अधिक महत्व का है। अर्थ विधेयक तो केवल लोक सभा में ही प्रस्तुत होते हैं। किसी भी विधेयक पर 14 दिन में अपनी अनुमति राज्य परिषद् को देनी होती है। लोक सभा किसी विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है। यदि 6 माह में ज्यादा समय लगता है तो राष्ट्रपति दोनों भवनों की सामूहिक बैठक बुलाता है जिसमें लोक सभा का ही मत मान्य होता है क्योंकि राज्य परिषद् के सदस्य लोक सभा के आगे भी नहीं होते। कहने का अर्थ यह है कि सब तरह से लोक सभा राज्य परिषद् से ऊँची है। संसद के अधिकारों को जानने के बाद यह जरूरी है कि विधेयक पारित करने की प्रक्रिया को समझे। इस प्रक्रिया का हम आगे वर्णन करते हैं।

विधि निर्माण करने की प्रक्रिया

विधेयक वह मसविदा है जिसमें कानून की रूपरेखा है तथा जिसे संसद के विचार करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है। संसद और राष्ट्रपति द्वारा मसविदे के पारित होने पर इसे कानूनी रूप प्रदान कर दिया

जाता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं। प्रथम साधारण विधेयक और द्वितीय अर्थ विधेयक।

साधारण विधेयक निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया—साधारण विधेयक किसी भी मदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। परन्तु जिन विधेयकों का महत्त्व ज्यादा है उन्हें मन्त्री ही प्रस्तुत करते हैं। पहले भवन का सदस्य विधेयक प्रस्तुत करता है। फिर इसके तीन वाचन होते हैं। प्रथम वाचन में विधेयक का शीर्षक पढ़ा जाता है और भवन में उसके प्रकाशन की स्वीकृति दी जाती है। फिर निश्चित दिन द्वितीय वाचन होता है। इस समय विधेयक के आधारभूत सिद्धान्त पढ़े जाते हैं। जब वे सिद्धान्त स्वीकृत हो जाते हैं तो फिर विधेयक को किसी समिति में भेजा जाता है। समिति उसकी प्रत्येक धारा और स्वरूप पर विचार करती है और यह चेष्टा करती है कि उसका स्वरूप अति उत्तम हो। इसीलिए समितियाँ विधेयक में परिवर्तन भी करती हैं। समिति से वापस फिर भवन में ही विधेयक आता है। परन्तु भवन को उन परिवर्तनों को मानने या न मानने की स्वतन्त्रता होती है। इसके बाद तृतीय वाचन होता है जिसमें भवन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करता है। उपर्युक्त क्रिया के एक भवन में समाप्त होने पर फिर विधेयक दूसरे भवन में जाता है। दूसरा मदन अगर इसे पास नहीं करता या इसमें बड़ा परिवर्तन करता है या 6 माह तक इसे पास नहीं करता तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है और इस बैठक में पास हुआ विधेयक दोनों सदनों में पास माना जाता है।

दोनों सदनों में पास होकर बिल को तब तक कानून नहीं कहते जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे। राष्ट्रपति बिल को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या पुनः मशोधन के लिए वापस कर सकता है। परन्तु यदि मसद दूसरी बार भी उसे पास कर देती है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि

विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है परन्तु उसे समाप्त नहीं कर सकता ।

अर्थ विधेयको के निर्माण की प्रक्रिया—अर्थ विधेयक भी साधारण विधेयको की प्रक्रिया से ही पास होते हैं परन्तु इसमें कुछ विशेष अन्तर होता है जो कि निम्नलिखित है —

(1) पहला अन्तर यह है कि अर्थ विधेयक लोक सभा में ही प्रस्तुत होते हैं राज्य परिषद् में नहीं । परन्तु राज्य परिषद् में विचार के लिये इन्हें भेजा जाता है ।

(2) दूसरे अर्थ विधेयक में अनुदान की मांगें बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के नहीं रखी जा सकती ।

(4)

उच्चतम न्यायालय

हमारे देश में न्याय-व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय का विशेष स्थान है । राज्यों के उच्च न्यायालय तथा दूसरे न्यायालय इसी के अधीन होते हैं । अपने देश की न्याय-व्यवस्था की उपमा हम एक पर्वत से यदि दें तो उच्चतम न्यायालय को हम पर्वत का उच्च शिखर कह सकते हैं । उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालयों की अपीलें ही नहीं सुनता बल्कि उसका स्वयं प्रारम्भिक कार्य-क्षेत्र भी है, अर्थात् पहले भी मुकदमा उसमें शुरू किया जा सकता है । वह सविधान का संरक्षण भी करता है और मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है । सन् 1950 से लेकर अब तक थोड़े-से ही समय में उच्चतम न्यायालय ने उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया है ।

उच्चतम न्यायालय का संगठन तथा न्यायाधीशों की योग्यताएँ

सविधान में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 14 अन्य न्यायाधीश होते हैं । राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है फिर मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों

की नियुक्ति करना है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को —

(1) भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।

(3) भारत के किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो, अथवा

(4) राष्ट्रपति की निगाह में वह उच्चकोटि के कानून का जानने वाला हो।

न्यायाधीशों की कार्यविधि, वेतन तथा भत्ते

65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर रह सकना है परन्तु बीच में भी यदि वह चाहे तो राष्ट्रपति को सम्बोधित करके लिखित पत्र देकर वह अपने पद को छोड़ सकता है। इसके अलावा यदि ससद के दोनों भवनो को समस्त बहुमत में न्यायाधीश को अयोग्य और दुर्गचारी गिद्ध कर दे तो ऐसी दशा में वह राष्ट्रपति से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि वे इस न्यायाधीश को पद से हटा दें।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 5000 रु० और अन्य न्यायाधीशों को 4000 रु० मासिक वेतन दिया जायगा। समय-समय पर ससद उनके वेतन, कार्य-काल और अधिकारों में कमी कर सकती है।

उच्चतम न्यायालय के अधिकार और कर्तव्य

उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे ऊँचा न्यायालय है। इसके फैसले देश की सभी अदालतों को मान्य होते हैं। इसके अधिकारों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं।

(1) प्राग्भिक क्षेत्राधिकार—प्रथम बार ही उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये मुकदमे इस अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। इनके सम्बन्ध

विवेक को राष्ट्रपति रोक सकता है परन्तु उसे समाप्त नहीं कर सकता ।

अर्थ विवेक के निर्माण की प्रक्रिया—अर्थ विवेक भी साधारण विवेक की प्रक्रिया से ही पास होते हैं परन्तु इसमें कुछ विशेष अन्तर होता है जो कि निम्नलिखित है —

(1) पहला अन्तर यह है कि अर्थ विवेक लोक सभा में ही प्रस्तुत होते हैं राज्य परिषद् में नहीं । परन्तु राज्य परिषद् में विचार के लिये इन्हें भेजा जाता है ।

(2) दूसरे अर्थ विवेक में अनुदान की मांगें बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के नहीं रखी जा सकती ।

(4)

उच्चतम न्यायालय

हमारे देश में न्याय-व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय का विशेष स्थान है । राज्यों के उच्च न्यायालय तथा दूसरे न्यायालय इसी के अधीन होते हैं । अपने देश की न्याय-व्यवस्था की उपमा हम एक पर्वत से यदि दें तो उच्चतम न्यायालय को हम पर्वत का उच्च शिखर कह सकते हैं । उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालयों की अपीलें ही नहीं सुनता वरन् उसका स्वयं प्रारम्भिक कार्य-क्षेत्र भी है, अर्थात् पहले भी मुकदमा उसमें शुरू किया जा सकता है । वह मविधान का संरक्षण भी करता है और मूल अधिकारों की रक्षा भी करता है । सन् 1950 से लेकर अब तक थोड़े-से ही समय में उच्चतम न्यायालय ने उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया है ।

उच्चतम न्यायालय का संगठन तथा न्यायाधीशों की योग्यताएँ

मविधान में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 14 अन्य न्यायाधीश होते हैं । राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है फिर मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों

की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को —

(1) भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) भारत के किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।

(3) भारत के किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत की हो, अथवा

(4) राष्ट्रपति की निगाह में वह उच्चकोर्ट के कानून का जानने वाला हो।

न्यायाधीशों की कार्यविधि, वेतन तथा भत्ते

65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है परन्तु बीच में भी यदि वह चाहे तो राष्ट्रपति को सम्बोधित करके लिखित पत्र देकर वह अपने पद को छोड़ सकता है। इसके अलावा यदि ससद के दोनो भवनों को समस्त बहुमत में न्यायाधीश को 'अयोग्य और दुर्गचारी' गिद्ध कर दे तो ऐसी दशा में वह राष्ट्रपति से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि वे इस न्यायाधीश को पद से हटा दें।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 5000 रु० और अन्य न्यायाधीशों को 4000 रु० मासिक वेतन दिया जायगा। समय-समय पर मसद उनके वेतन, कार्य-काल और अविकारों में कमी कर सकती है।

उच्चतम न्यायालय के अधिकार और कर्तव्य

उच्चतम न्यायालय भारत का सबसे ऊँचा न्यायालय है। इसके फैसले देश की सभी अदालतों को मान्य होते हैं। इसके अधिकारों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं।

(1) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार—प्रथम बार ही उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये मुकदमे इस अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। इसके सम्बन्ध

के मुकदमे किसी अन्य न्यायालय में नहीं सुने जा सकते । इस अधिकार-क्षेत्र में दो प्रकार के मुकदमे आते हैं । यदि सवीय और राज्य की सरकार में सवैधानिक प्रश्न पर कोई मतभेद हो जाय इसके अलावा यदि सध में किन्हीं दो या दो से अधिक राज्यों में किसी वैधानिक प्रश्न पर कोई झगडा हो जाय । इस प्रकार के फैसले उच्चतम न्यायालय ही करता है । इन दोनों स्थितियों का मुकदमा कोई भी अन्य न्यायालय नहीं सुन सकता ।

(2) अपीलीय क्षेत्राधिकार—इसमें उच्चतम न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों के मुकदमों के फैसले की अपील सुनता है । इसके सामने सवैधानिक, फौजदारी, दीवानी तीन प्रकार के मुकदमों की अपील आ सकती है ।

(क) सवैधानिक अपीलें—उच्च न्यायालय यदि किसी मुकदमे के सम्बन्ध में यह कहे कि इसमें सविधान की किसी धारा के उच्च अर्थ के विषय में शका की गई है तो ऐसे मुकदमे के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील सुनी जा सकती है । उच्चतम न्यायालय स्वयं प्रार्थना-पत्र के आधार पर इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है । दोनों ही परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय सविधान की व्याख्या करता है ।

(ख) फौजदारी अपीलें—तीन प्रकार की परिस्थितियों में फौजदारी अपील सुनी जा सकती है—

(1) यदि किसी अपराधी के मुक्त करने के आदेश को कोई न्यायालय उसे मृत्यु-दण्ड में बदल दे तो इस सम्बन्ध की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है ।

(2) यदि कोई उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय में मुकदमा मंगाकर उसे मृत्यु-दण्ड में बदल दे तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है ।

(3) यदि उच्च न्यायालय किसी मुकदमे के बारे में यह मित्र कर

दे कि इसमें कोई महत्त्वपूर्ण कानूनी समस्या पेश की गई है त मुकदमे के निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती

(ग) दीवानी मुकदमे सम्बन्धी अपीलें—दीवानी मुकदमे सम्बन्ध में दो प्रकार की अपीले उच्चतम न्यायालय में की जा सकती हैं। यदि कोई उच्च न्यायालय यह सिद्ध कर दे कि अमुक मुकदमा राशि का मूल्य 10000 रु० से अधिक है तो ऐसी स्थिति की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय यह निर्णय करे कि अमुक मुकदमा बहुत महत्त्वपूर्ण है तो ऐसे मुकदमों की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी।

(3) मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार—मूल अधिकारों की रक्षा करना उच्चतम न्यायालय का मुख्य कर्तव्य है। यदि राज्य या केन्द्र की सरकार किसी नागरिक के मूल अधिकारों का अपमान करती है तो निर्देश लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय इसे पुनः स्थिर कर सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय यह तय करे कि स्वतन्त्र सम्बन्ध में राज्य द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध उचित हैं या नहीं। यह हर्ष की बात है कि अभी तक मूल अधिकारों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय ने बड़ी ही निष्पक्षता और निर्भीकता से कार्य किया है।

(4) परामर्श सम्बन्धी अधिकार—अतः उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति के किसी संवैधानिक मामले पर पूछने पर अपना मत दे परन्तु इसको मानना न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर है।

उपर्युक्त अधिकारों के विवेचन से हमें ज्ञात हुआ है कि उच्च न्यायालय का शासन पद्धति में उच्च स्थान है। यह देश का न्यायालय ही नहीं गांधी मविद्यान और मूल अधिकारों की रक्षा करता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. राष्ट्रपति की योग्यताएँ, कार्य-काल तथा निर्वाचन-प्रणाली समझाइये।

- 2 राष्ट्रपति के क्या-क्या अधिकार ओर कर्त्तव्य हे ?
- 3 राष्ट्रपति के सकटकालीन अधिकारो के सम्बन्ध मे आप क्या जानते हे ?
- 4 प्रधान मन्त्री का मन्त्रिमण्डल से सम्बन्ध दर्शाइए ।
- 5 मन्त्रिमण्डल के अधिकार ओर कर्त्तव्यो की विवेचना करिए ।
- 6 ससद किसे कहते हे ? उसके अधिकार ओर कर्त्तव्यो की विवेचना करिए ।
- 7 लोक सभा का सगठन कैसे होता हे ? इसके सदस्यो को चुनने और चुने जाने वाले सदस्यो की क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए ? उनका कार्य-काल कितना होता हे ?
- 8 राज्य परिषद् का सगठन कैसे होता हे ? उसके अधिकारियो के अधिकारो को लिखिए ।
- 9 कोई भी विधेयक कब कानून का रूप धारण करता हे ? पूर्ण पद्धति लिखिए । साधारण विधेयक ओर अर्थ विधेयक मे क्या अन्तर हे ?
- 10 उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए किन-किन योग्यताओ का होना जरूरी हे ? उनके कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते के बारे मे आप क्या जानते ह ?
- 11 उच्चतम न्यायालय के अधिकारो तथा कर्त्तव्यो की विवेचना करिए ।

केन्द्र की तरह राज्य की शासन-व्यवस्था का आवार समदीय है। अतः राज्यों की शासन-व्यवस्था समझने में पहले यह जानना जरूरी है कि समदीय शासन-व्यवस्था किसे कहते हैं? इस प्रकार की शासन-व्यवस्था में कार्यकारिणी व्यवस्थापिका से चुनी जाती है और सर्वदा उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यकारिणी नभी तक अपने पद पर काम कर सकती है जब तक व्यवस्थापिका का इसमें विश्वास हो। इसमें वैधानिक और वास्तविक दो प्रकार की भी कार्यपालिका होती है। वैधानिक कार्यपालिका केवल नाममात्र की होती है। सभी शक्तियाँ मन्त्रि-परिषद् में निहित होती हैं। अब हमारे सामने यह सवाल उठता है कि इस नाममात्र की वैधानिक कार्यपालिका की जरूरत ही क्यों पड़ती है। इसके कई कार्य हैं जैसे प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करना, उसे मन्त्रि-मण्डल बनाने का आदेश देना तथा व्यवस्थापिका सभा को आमन्त्रित करना, रोक्ना और उसे भंग करना। जब एक मन्त्रि-परिषद् अपने पद से त्यागपत्र दे देती है तो फिर वैधानिक कार्यपालिका को नवीन मन्त्रि-परिषद् का निर्माण करना पड़ता है। उस काल में यह वैधानिक कार्यपालिका शासन की सुरक्षा बन जाती है। उसी भूमिका के आधार पर ही हम राज्यपाल के पद को भलीभाँति समझ सकते हैं।

(1)

राज्यपाल

राज्यपाल कार्यपालिका का अध्यक्ष माना जाता है। जिस प्रकार सब में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल। राज्यपाल

मे सम्पूर्ण व्यवस्थापिका शक्ति निहित मानी जाती है। उसी के नाम से शासन चलता है। वह विधान-मण्डल का जरूरी अंग है। परन्तु जब हम व्यावहारिक रूप से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि उसका स्थान केवल वैधानिक अध्यक्ष-मात्र का ही होता है। मन्त्रि-परिषद् उसकी सब शक्तियों का भोग करती है। राज्यपाल वास्तव में केन्द्र और राज्य के शासन को जोड़ने वाली कड़ी है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया है। अब राज्यपाल वैधानिक या नाममात्र की कार्यकारिणी है और मन्त्रि-परिषद् वास्तविक है।

राज्यपाल की नियुक्ति तथा उसका कार्य-काल

राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहकर ही कार्य करता है। उसका कार्य-काल 5 वर्ष होता है परन्तु वह इस अवधि के पहले भी अपने स्थान से राष्ट्रपति को सम्बोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। 5 वर्ष का काल समाप्त हो जाने के बाद भी राज्यपाल अपने स्थान को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक उसका उत्तराधिकारी उस पद पर नहीं आ जाता। इस समय राजस्थान में राज्यपाल डा० सम्पूर्णानन्द हैं।

राज्यपाल होने की योग्यताएँ

राज्यपाल के पद पर सटे होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है —

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) उसकी आयु 35 साल तक हो।

(3) और जो न तो मन्त्रीय मन्द और न ही राज्य के विधान मण्डल का सदस्य हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विधान मण्डल या मन्द का सदस्य है और उसकी नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्त होने की तारीख में उस स्थान की सदस्यता को छोड़ देना होगा।

राज्यपाल का वेतन तथा अन्य भत्ते

राज्यपाल के वेतन में सम्बन्ध में जब तक मन्द निश्चित नहीं कर

देती उसे 5000 रु० वेतन तथा अन्य भत्ते दिये जायेंगे । साथ ही उसे रहने के लिए मकान भी दिया जायेगा । राज्यपाल का वेतन तथा उसके अन्य भत्ते उसके कार्य-काल में कम नहीं किये जा सकते ।

राज्यपाल के अधिकार और कर्तव्य

जब राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था उस समय तक 'क' श्रेणी के राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल और 'ख' श्रेणी के राज्य का अध्यक्ष राजप्रमुख कहलाता था । इन दोनों पदों के कार्यों और अधिकारों में कुछ भी अन्तर नहीं होता था । पुनर्गठन में अब राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया है । प्रारम्भिक रूप में राज्यों की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है । सब शासन उसी के नाम से चलाया जाता है । व्यवस्थापन और न्याय-क्षेत्र में भी राज्यपाल के कार्य विस्तृत हैं । इस प्रकार वह विधान मण्डल का जरूरी भाग माना गया है । जब तक राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता । उसे क्षमा करने का अन्तिम अधिकार प्राप्त है । केवल असम के राज्यपाल को अपने विवेक में काम करने का अधिकार है । परन्तु वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी अवश्य होता है । राज्यपाल को अपने अधिकारों के उपभोग की पूरी स्वतन्त्रता है । उसे अपने अधिकारों के उपयोग की पूरी स्वतन्त्रता है । वह अपने कार्यों के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता । राज्यपाल की महायता और परामर्श के लिए एक मन्त्रि-परिषद् का निर्माण किया गया है परन्तु यह राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है कि वह मन्त्रि-परिषद् की गयी माने या न माने । वैसे तो नैदान्तिक रूप में यह कहा जाता है कि मन्त्रि-परिषद् के परामर्श से राज्यपाल कार्य करेगा परन्तु व्यावहारिक रूप में ऐसा करने में राज्यपाल के अधिकार-कर्तव्य मन्त्रि-परिषद् के अधिकार-कर्तव्य हों जायेंगे । उपर्युक्त बातों के आधार पर हम राज्यपाल के कार्यों का विभाजन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं जिनके आधार पर उसकी स्थिति का हमें भली-भाँति पता चलता है ।

(1) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार—ऊपर भी कहा गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का अध्यक्ष है। अतः कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार उसी के हाथों में होते हैं जिनका भोग वह स्वयं करता है या उसके पदाधिकारी करते हैं। जिन विषयों में राज्य का विधान मण्डल कानून बनाता है उसकी कार्यपालिका शक्ति वही तक फैली हुई है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति करके उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, राज्यपाल केवल स्वीकार करता है। परन्तु जैसा ऊपर देखने में मालूम होता है कि राज्यपाल मुख्य मन्त्री की नियुक्ति में उतना स्वतन्त्र नहीं है क्योंकि जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उसी के नेता को उसे मुख्य मन्त्री बनाना होता है। इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति आ जाय जिसमें किसी दल का बहुमत न हो और कई व्यक्ति मुख्य मन्त्री का पद चाहते हों तो इस अवस्था में राज्यपाल की इच्छा से ही नियुक्ति की जायेगी। मुख्य मन्त्री की सलाह अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति में ली जाती है। यदि राज्यपाल उसे नहीं मानता तो मुख्य मन्त्री त्यागपत्र दे देता है। अतः राज्यपाल को इस स्थिति में सम्भव हो सकता है त्यागपत्र देना पड़े। राज्यपाल लोक-सेवा आयोग की भी नियुक्ति करता है। मन्त्रियों के कार्य का वटवारा करना तथा शासन संचालन के नियम बनाना आदि इसी का काम है।

(2) व्यवस्थापिका सम्बन्धी अधिकार—राज्यपाल विधान मण्डल का एक अंग है। उसे अधिकार है कि वह विधान मण्डल की बैठक बुलाये, उन्हें स्थगित करे, विघटित करे तथा विधान मण्डल में भाषण दे और सदन भेजे। विधान मण्डल में पास होकर बिल जब तक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत नहीं होता वह कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह बिल को अस्वीकार कर दे, समाप्त कर दे या राष्ट्रपति की सलाह के लिए रोकें रखे। यदि विधान मण्डल उसे पुनः उसी रूप में राज्यपाल के पास भेजता है तो उसे पास करना पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि राज्यपाल कानून समाप्त नहीं कर

सकता उसे रोके रख सकता है। राज्यपाल को उस समय जब कोई अधिवेशन न हो रहा हो अध्यादेश पास करने का अधिकार है। इन अध्यादेशों का वैसा ही प्रभाव होता है जैसा कि विधान मण्डल के कानून का होता है। परन्तु यह जरूरी है कि प्रत्येक अध्यादेश विधान मण्डल के आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत किए जायें। विधान मण्डल को उन अध्यादेशों के स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। यदि विधान मण्डल उन्हें पास कर देता है तो वे कानून बन सकते हैं। इन अध्यादेशों का समय 6 हफ्ते होता है। परन्तु विधान मण्डल मध्य में ही इन्हें समाप्त कर सकता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राज्यपाल का व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अधिक महत्वपूर्ण है।

(3) **आर्थिक अधिकार**—राज्यपाल को वजट से सम्बन्धित अधिकार भी होते हैं। प्रत्येक वर्ष का वजट विधान सभा में राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत होता है। इस वजट में उस वर्ष की आय का अनुमान में व्यौरा तैयार किया जाता है। बिना राज्यपाल की आज्ञा के किमी भी मद की मांग विधान मण्डल से नहीं की जा सकती। राज्यपाल बर्च हुए खर्च की मांगों को भी कारण बता कर प्रस्तुत कर सकता है। विधान मण्डल इन मांगों को कम कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है परन्तु बढ़ा नहीं सकती।

(4) **न्यायिक अधिकार**—विधान मण्डल द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार ही राज्यपाल दण्ड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है तथा उसे स्थगित भी कर सकता है।

राज्यपाल के अधिकारों को जान लेने के बाद यह कहना आवश्यक ही है कि राज्यपाल का स्थान प्रभाव और वैभव का है शक्ति का नहीं है। क्योंकि वह अपने बहुत से अधिकारों का भोग मन्त्रिमण्डल और विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होकर करता है। शासन पर उसका प्रभाव उसके व्यक्तिगत प्रभाव पर आधारित है। राज्यपाल के स्थान की महत्ता तो इसी से ज्ञात हो जाती है कि किमी भी न्यायालय में उसके कार्यों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती।

(2)

मन्त्रि-परिषद् तथा मुख्य मन्त्री

प्रत्येक राज्य में एक मन्त्रि-परिषद् होती है। वैसे तो राज्यपाल की सम्पूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित मानी गई है परन्तु व्यवहार में मन्त्रि-परिषद् ही इन अधिकारों का उपभोग करती है।

मन्त्रि-परिषद् का संगठन, अवधि तथा योग्यताएँ

संघीय शासन की ही भाँति राज्य में मन्त्रि-परिषद् का संगठन किया जाता है। मन्त्रि-परिषद् का नेता मुख्य मन्त्री होता है। राज्य की विधान सभा के बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्य मन्त्री बनाता है, और मुख्य मन्त्री की सलाह से अन्य मन्त्री चुनता है। मन्त्रियों की संख्या कितनी हो इस सम्बन्ध में संविधान कुछ नहीं कहता। यह संख्या मुख्य मन्त्री राज्य की आर्थिक स्थिति, सरकारी काम और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर करता है। इस समय राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल में कुल 18 सदस्य हैं। 8 कैबिनेट मन्त्री (जो प्रथम श्रेणी के मन्त्री होते हैं) और 10 उप-मन्त्री। इन मन्त्रियों का कार्य-काल मुख्य मन्त्री की इच्छा पर निर्भर है। वैसे व्यवहार में मन्त्रि-परिषद् तब तक अपने पद पर आसन्न रहती है जब तक विधान मण्डल का उसमें विश्वास हो। जब विधान मण्डल का विश्वास उन पर से उठ जाता है तो या तो स्वयं मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे देता है या राज्यपाल उन्हें उनके पद से हटा देता है।

मन्त्रिमण्डल का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को विधान मण्डल का सदस्य होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मन्त्रिमण्डल का सदस्य हो जाय और वह विधान मण्डल का सदस्य न हो तो उसे 6 माह के अन्दर ही उसका सदस्य बन जाना होगा। विधान मण्डल मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के वेतन को निर्दिष्ट करता है।

मन्त्रिमण्डल की कार्य-प्रणाली

मुख्य मन्त्री की सलाह से राज्यपाल मन्त्रियों के काम का बँटवारा करता है। एक मन्त्री एक या एक से अधिक विभागों का सदस्य हो सकता है। मन्त्रि-परिषद् सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सब मन्त्री मिलकर किसी एक नीति का समर्थन करते हैं।

मन्त्रि-परिषद् के अधिकार और कर्तव्य

यद्यपि राज्यपाल सम्पूर्ण कार्यकारिणी शक्ति का अधिकारी है परन्तु वह उसका प्रयोग मन्त्रि-परिषद् द्वारा करता है। मन्त्रि-परिषद् उसे उन मामलों में सलाह देती है जो कि विधान से अलग आते हैं। परन्तु व्यवहार में अगर देखा जाय तो हमें ज्ञान होता है कि मन्त्रि-परिषद् सम्पूर्ण काम राज्यपाल के नाम से करती है। परन्तु असम सीमा के प्रदेश में यह बात लागू नहीं होती। व्यवहार में राज्यपाल के अधिकार मन्त्रि-परिषद् के अधिकार हैं जिनके सम्बन्ध में राज्य का विधान मण्डल कानून बनाता है। उनका कार्यकारिणी सम्बन्धी कार्य वही तक सीमित है। विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य-क्रम बनाना, उनके पक्ष में बोलना, विधान मण्डल में अपने बहुमत से उन्हें स्वीकृत कराना ये सब मन्त्रि-परिषद् के ही काम हैं। मन्त्रि-मण्डल को विधान मण्डल के प्रश्नों का तथा आलोचना का जवाब देना होता है तथा साथ ही विधान मण्डल में अपनी नीति की व्याख्या उसे करनी पड़ती है। कहने का अर्थ यह है कि उन सब बातों में यह निश्चय है कि मन्त्रि-परिषद् राज्य की सरकार का बहुत ही आवश्यक अंग है।

मुख्य मन्त्री

चूँकि मन्त्रि-परिषद् का मुख्य, मुख्य मन्त्री ही होता है अतः इसके सम्बन्ध में थोड़ा अलग से ज्ञान होना जरूरी है। जैसा कि ऊपर भी कहा गया है कि मुख्य मन्त्री को राज्यपाल नियुक्त करता है, परन्तु यह याद

रहे कि विधान सभा में जिस राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसी के नेता को राज्यपाल मुख्य मंत्री बनाता है। श्री हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्य मंत्री थे। उनके बाद श्री जयनारायण व्यास को यह पद मिला, अब इस पद पर श्री मोहनलाल जी सुखाडिया हैं। मुख्य मंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रीगण चुने जाते हैं। उसमें राज्यपाल का कोई हाथ नहीं होता। परन्तु मुख्य मंत्री को अन्य मंत्रियों के चुनते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे उसे अपने दल के प्रभावशाली नेताओं को मन्त्रिमण्डल में लेना जरूरी होता है। साथ ही उसे यह भी ख्याल रखना पड़ता है कि मन्त्रिमण्डल में अल्पसंख्यकों जैसे मुसलमान, परिगणित जाति आदि के प्रतिनिधि भी आये। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर राजस्थान का मन्त्रिमण्डल बनाया गया है। मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों की कितनी सख्या हो यह निश्चित करना भी मुख्य मंत्री का ही काम है।

(3)

विधान मण्डल

मविधान में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधान मण्डल होगा। यह विधान मण्डल राज्यपाल, एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा (क्योंकि कुछ राज्यों में एक सदन है कुछ में दो सदन हैं अतः ऐसा कहा गया है) जहाँ पर दो सदन होते हैं वहाँ निम्न सदन को विधान सभा और उच्च सदन को विधान परिषद् के नाम से पुकारा गया है। राज्यों के पुनः संगठन के बाद निम्नलिखित राज्यों में दो सदनों का निर्माण किया गया है

- 1 आन्ध्र
- 2 बिहार
- 3 मद्रास
- 4 महागण्ट

- 5 उत्तर प्रदेश
- 6 पश्चिमी बंगाल
7. पंजाब
- 8 मैसूर
- 9 मध्य प्रदेश
- 10 जम्मू तथा काश्मीर

विधान परिषद् के निर्माण तथा तोड़ने की विधि

संविधान में यह लिखा है कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद् नहीं है, सरकार वहाँ (उस राज्य में) इसका निर्माण करना चाहती है, तो वह विधान सभा के दो-तिहाई बहुमत से विधान परिषद् बना सकती है। इसके विपरीत यदि कहीं विधान परिषद् है और वहाँ से उसे हटाना है, तो भी उसे विधान सभा के दो-तिहाई बहुमत के प्रस्ताव से पास होने पर हटाया जा सकता है। अब हम नीचे यह बतायेंगे कि विधान मण्डल के दोनों सदनों का कैसे निर्माण किया जाता है और उनके कार्य क्या हैं ? पहले हम विधान सभा को ही लेंगे।

विधान सभा

विधान सभा की निर्वाचन विधि तथा सदस्यों की संख्या

विधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जायेगा। अर्थात् वह व्यक्ति जो कि 21 वर्ष का हो तथा उस पर कोई भ्रष्टाचार, गैर-कानूनी कार्यवाही का आरोप न हो, विधान सभा के सदस्यों को चुन सकता है। संविधान में कहा गया है कि यह प्रयत्न रहना चाहिए कि सारे देश के प्रतिनिधित्व का अनुपात ममान हो। विधान सभा का निर्वाचन नयुक्त निर्वाचन प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा होगा। अर्थात् हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब अलग-अलग अपनी-अपनी जाति को नहीं बरन् सब मिलकर सबका निर्वाचन करेंगे।

विधान सभा के सदस्यों की सख्या कितनी होगी यह राज्यों की आबादी पर निर्भर होगा । राज्यों के पुनः संगठन होने के बाद विधान सभा के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित रूप में दिखाई गई है —

राज्य का नाम विधान सभा के सदस्यों की सख्या

1 आन्ध्र	301
2 असम	108
3 बिहार	318
4 गुजरात	154
5 मध्य प्रदेश	288
6 मद्रास	205
7 महाराष्ट्र	264
8 मैसूर	208
9 पंजाब	154
10 राजस्थान	176
11 पश्चिमी बंगाल	252
12 जम्मू तथा कश्मीर	75
13 केरल	126
14 उड़ीसा	140
15 उत्तर प्रदेश	430
16 नागालैंड	(अन्तर्ग्रिम परिपद्)

विधान सभा के सदस्यों की योग्यताएँ, कार्य-काल,
वेतन तथा भत्ते

विधान सभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को यह जरूरी है कि—

(1) वह भारत का नागरिक हो ।

(2) उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो ।

(3) वह विधान मण्डल द्वारा निर्धारित सब योग्यताएँ पूरी करता हो ।

(4) वह किसी सरकारी लाभ के पद पर आसीन न हो ।

(5) वह पागल, कोढ़ी या दिवालिया न हो ।

विधान सभा के सदस्यों का कार्य-काल 5 वर्ष होता है । सकट-कालीन अवस्था में ससद उनका कार्य-काल एक समय में एक वर्ष बढ़ा सकती है । विधान मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन और भत्ते विधान सभा के सदस्यों को दिये जायेंगे ।

विधान सभा के सदस्यों के अधिकार

विधान सभा के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं । इन सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सदन में भाषण दें और अपने विचारों को प्रकट करें । इन सदस्यों में जो सदस्य अपने विचार प्रकट करते हैं किसी भी न्यायालय में उनकी कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

राजस्थान विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 176 है । 1962 में सम्पन्न हुए तृतीय आम चुनावों के पश्चात् कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला । विधान सभा में विभिन्न दलों की स्थिति निम्न प्रकार है —

कांग्रेस	88
साम्यवादी	5
स्वतन्त्र पार्टी	36
जनसंघ	15
प्रजा-समाजवादी	2
अन्य	30

विधान परिषद्

विधान परिषद् का चुनाव तथा उसके सदस्यों की संख्या

विधान परिषद् का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में जनता के प्रतिनिधियों के निर्वाचन-मण्डल द्वारा किया जाता है । यह निर्वाचन-मण्डल चार प्रकार के होते हैं जो इनमें चुनते हैं —

(1) न्यायिक संस्थाओं जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड तथा वे

स्थानीय कर्मचारी जिन्हें समद द्वारा निर्वाचन-मण्डल में शामिल होने की आज्ञा है, विधान परिषद् के सदस्यों में से $\frac{1}{3}$ भाग चुनेंगे ।

(2) एक ऐसा शिक्षित व्यक्तियों का मण्डल जो उस राज्य का निवासी हो तथा जो बी० ए० की परीक्षा तीन वर्ष पहले पास कर चुका हो वह कुल सदस्यों का $\frac{1}{3}$ वा भाग चुनेगा ।

(3) ऐसे अध्यापकों का निर्वाचन-मण्डल जो कि किसी माध्यमिक पाठशाला तक ही पढ़ाते हों, सदस्यों का $\frac{1}{3}$ वां भाग चुनेगा ।

(4) राज्य की विधान सभा का स्वयं निर्वाचन-मण्डल होगा जो परिषद् के सदस्यों का $\frac{1}{3}$ भाग चुनेगा ।

(5) विधान परिषद् के $\frac{1}{3}$ सदस्यों का चुनाव राज्यपाल द्वारा होगा । राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान आदि के ज्ञाता को ही इसका सदस्य बनायेगा ।

यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि वह निर्वाचन-मण्डल एकल-सक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा परिषद् के सदस्य चुनता है । विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों की $\frac{1}{3}$ होनी चाहिए परन्तु यह संख्या 40 से कम न हो । इस समय उत्तर-प्रदेश विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 108 है । अतः भिन्न-भिन्न राज्यों में इस संख्या को बँटते रखा गया है इसे नीचे दिखाया जाता है ।

राज्य का नाम परिषद् के सदस्यों की संख्या

आन्ध्र	90
बिहार	96
महाराष्ट्र व गुजरात	108
मद्रास	63
मध्य प्रदेश	90
जम्मू तथा कश्मीर	36
मैसूर	63

उत्तर प्रदेश	108
पश्चिमी बंगाल	75
पंजाब	51

विधान परिषद् के सदस्यों की योग्यताएँ

कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते

विधान परिषद् का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को निम्न योग्यताएँ पूरी करनी चाहिए —

- (1) वह भारत का नागरिक हो ।
- (2) 30 वर्ष से कम उम्र न हो ।
- (3) वह उन सब योग्यताओं को पूरी करता हो जो विधान मण्डल द्वारा निश्चित की गई हैं ।

(4) वह पागल, कोढ़ी, दिवालिया और अपराधी न हो ।

विधान परिषद् एक स्थाई सभा है, वह पूर्णतः भंग नहीं होती । प्रति दो वर्ष के बाद इसके एक-तिहाई सदस्य अपना पद छोड़ते हैं और उनके स्थान पर नये सदस्य चुने जाते हैं । इस प्रकार से प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल 6 वर्ष कहा जा सकता है । विधान परिषद् को विधान मण्डल द्वारा निश्चित किये वेतन और भत्ते दिये जाते हैं ।

विधान परिषद् के अधिकारी तथा अधिकार

परिषद् के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उप-सभापति चुनते हैं । विधान सभा के समस्त अधिकारों का उपभोग विधान परिषद् के सदस्य करते हैं ।

(राजस्थान राज्य में यद्यपि विधान-परिषद् नहीं है, फिर भी विद्यार्थियों के ज्ञान के लिए विधान-परिषद् का विवरण दिया गया है ।)

विधान मण्डल के अधिकार

हम यह कह सकते हैं कि विधान मण्डल के वही अधिकार हैं जो कि

संसद को सघीय विषयो मे मिले हुए है । इनका वर्णन हम निम्न शीर्षको मे करेगे —

(1) विधि निर्माण सम्बन्धी अधिकार—कानून बनाना विधान मण्डल का प्रमुख काम है । राज्यो की सूची मे दिये गये सभी विषयो के सम्बन्ध मे विधान मण्डल कानून बनाता है । उसे समीपवर्ती सूची के विषयो पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है । परन्तु इस क्षेत्र मे यदि राज्य और संसद के कानूनों मे कोई विरोध होता है तो वह कानून लागू नहीं किया जायेगा । साधारण परिस्थिति मे विधान मंडल स्वतन्त्र है, परन्तु सकट-काल मे उसके अधिकारो मे राष्ट्रपति तथा संसद दखल दे सकता है ।

(2) आर्थिक अधिकार—विधान मंडल का दूसरा मुख्य काम वजट पास करना है । प्रति वर्ष विधान सभा मे आय-व्यय का व्योरा राज्यपाल की सम्मति से पेश किया जाता है । विधान मंडल इसमे कमी कर सकता है, और अस्वीकृत भी कर सकता है, परन्तु उसे बढ़ाने का अधिकार नहीं है । विधान सभा के निणय वजट के बारे मे अन्तिम होते हैं, परन्तु विधान परिषद् के पास यह विचार के लिए अवश्य भेजा जाता है ।

(3) शासन-सम्बन्धी अधिकार—विधान मण्डल मन्त्रि-परिषद् को नियन्त्रण मे रखकर उसे जन-कल्याण मे लगाती है । विधान मण्डल को यह अधिकार है कि वह मन्त्रि-परिषद् से प्रश्न पूछे या उसकी नीति की आलोचना करे । विधान मण्डल यदि अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो मन्त्रि-मण्डल को त्यागपत्र देना पड़ता है ।

इस प्रकार मे हम देखते हैं कि विधान मण्डल पर शासन के नियन्त्रण का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है ।

(4)

उच्च न्यायालय

राज्य का सबसे मुख्य न्यायालय उच्च न्यायालय है । प्रत्येक राज्य मे एक उच्च न्यायालय होता है । यह उच्चतम न्यायालय के अधीन

होता है। जो निर्णय उच्चतम न्यायालय देता है उसे उच्च न्यायालय को मानना पड़ता है। परन्तु उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह उस निर्णय को बदल सकता है। वैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की भांति नागरिकों के मताधिकारों का संरक्षण करता है।

उच्च न्यायालय का संगठन व न्यायाधीशों की योग्यताएँ

एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दूसरे न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी वह राष्ट्रपति ही निश्चित करता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीश हैं।

किमी भी व्यक्ति को किमी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने से लिए निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करना जरूरी होता है —

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी न्याय सम्बन्धी पद पर रहा हो, या,

(3) राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगभग 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।

न्यायाधीशों का कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते

60 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर कार्य कर सकता है। परन्तु इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग-पत्र दे सकता है। यदि मनद के दोनों भवनों के सदस्य अलग-अलग दो-तिहाई बहुमत में किमी न्यायाधीश को दुर्गचारी सिद्ध करते हैं तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 4000 रु० वेतन और अन्य भत्ते तथा अन्य न्यायाधीशों को 3500 रु० वेतन और अन्य भत्ते दिये जाते हैं। यह वेतन और भत्ते उनके कार्य की अवधि में कम नहीं किये जा सकते।

उच्च न्यायालय के अधिकार

प्रत्येक उच्च न्यायालय के दो प्रकार के अधिकार होते हैं—

(1) न्याय सम्बन्धी अधिकार, और

(2) प्रवन्ध सम्बन्धी अधिकार ।

1 न्याय सम्बन्धी अधिकार—न्याय सम्बन्धी अधिकारों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(क) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार, और (ख) अपीलीय क्षेत्राधिकार ।

(क) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारी—कौन कौन से मुकदमे उच्च न्यायालय सुनेगा, इनका जिक्र सविधान में नहीं किया गया है । परन्तु सविधान बनने के पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के उच्च न्यायालय प्रारम्भिक क्षेत्राधिकारों का भोग करते थे, वैसा अब भी होता है । इस क्षेत्र में वे दीवानी मुकदमे होते हैं जिनको खफीफा अदालतों में पेश नहीं किया जा सकता और वे फौजदारी मुकदमे आते हैं, जिनका फैसला सेशन जज की अदालत में नहीं होता । मूल अधिकार सम्बन्धी मुकदमे विशेष रूप में उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में आते हैं । मुकदमे या तो उच्च न्यायालय मुनता है या उच्चतम न्यायालय । व्यवहार में उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे कम ही मुनता है ।

(ख) अपीलीय क्षेत्राधिकार—इस अधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय दीवानी, फौजदारी और माल सम्बन्धी सभी प्रकार के मुकदमों की अपील मुनता है । इसके साथ उच्च न्यायालय को यह भी अधिकार है कि वह अपने पास के किसी भी न्यायालय का कोई मुकदमा मँगाकर उसकी छानबीन करे ।

2 प्रवन्ध सम्बन्धी अधिकार—उच्च न्यायालयों को यह अधिकार होता है कि वे अपने पास के न्यायालयों का उचित रूप में प्रवन्ध करें तथा उनके कार्या का निरीक्षण करें । उच्च न्यायालय निम्नलिखित तरीकों में उनका निरीक्षण करता है —

(1) उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय में किसी भी मुकदमे के कागज मँगाकर उनकी जाँच कर सकता है ।

(2) उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह न्यायालय के लिए ऐसे नियम बनाये जिससे उनका काम आसानी से चल सके ।

(3) उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में भी नियम बना सकता है कि किसी भी न्यायालय को किन मुकदमों का रिकार्ड रखना चाहिए ।

(4) उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, उनके वेतन में कमी और छुट्टी आदि के सम्बन्ध में भी नियम बनाने का अधिकारी है ।

(5) उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह एक न्यायालय का मुकदमा दूसरे न्यायालय में भेज दे ।

(6) उच्च न्यायालय मूलाधिकारों को पुनः स्थापित करने हेतु राज्य के कर्मचारियों को अपना आदेश दे सकता है । यदि कोई व्यक्ति गैर-कानूनी ढंग से जेल में बन्द कर दिया गया हो तो उसे वह छुड़ा सकता है ।

(7) कोई भी न्यायालय बिना उच्च न्यायालय की आज्ञा के किसी भी व्यक्ति को फाँसी की सजा नहीं दे सकता ।

इस प्रकार हमने देखा कि उच्च न्यायालय अपने अधिकारों के कारण काफी महत्व का स्थान न्याय के क्षेत्र में रखता है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. राज्यपाल किसे कहते हैं ? राज्यपाल का पद प्राप्त करने के लिए किन योग्यताओं का होना जरूरी है ?
2. राज्यपाल के अधिकारों की संक्षिप्त विवेचना करिए ।
3. मन्त्रि-परिषद् का संगठन कैसे होता है ? इसमें मुख्य मन्त्री की क्या स्थिति होती है ?
4. मन्त्रि-परिषद् के कार्यों की विवेचना करो ।

- 5 विधान मण्डल का निर्माण कैसे होता है ? उसके दोनो सदनों के बारे में संक्षेप में बताओ ।
- 6 विधान मण्डल के कार्यों की विवेचना करिए ।
- 7 उच्च न्यायालय का संगठन कैसे होता है ? न्यायाधीशों में किन योग्यताओं का होना जरूरी है ?
- 8 उच्च न्यायालय के अधिकारों की संक्षिप्त विवेचना करिए ।

भाग 3

राजस्थान तथा उसका प्रशासन

भारत के अन्य भागों की तरह यहाँ कृषि आदि की सुविधा है। राजस्थान का पूर्वी प्लैटो वेतवा नदी के वर्षा वाले क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर काफी वर्षा भी होती है।

(2) जनसंख्या—सन् 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में आबादी 2,01,55,602 है। 1951 की जनगणना के अनुसार 26 20 प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वैसे राजस्थान की जनसंख्या सन् 1901 से निरन्तर बढ़ रही है जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट है

वर्ष	जनसंख्या (लाखों में)
1901	102
1911	109
1931	127
1941	138
1951	159
1961	202

राजस्थान की 2,01,55,602 की आबादी में 1,05,64,082 पुरुष और 95,91,520 स्त्रियाँ हैं। राजस्थान की जनसंख्या में यौन अनुपात 1,000 908 का आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुपात पिछले 60 वर्षों में इसी प्रकार चला आ रहा है।

(3) राजस्थान का एकीकरण—आज का राजस्थान इतिहास में पहली बार अपने इस वर्तमान स्वरूप में आया है। इसके पहले यह विभिन्न राज्यों एवं जागीरों में बँटा हुआ था जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मिलाकर एक किये गये हैं।

राज्य पुनर्गठन के पूर्व राजस्थान 'वी' श्रेणी का राज्य था और यहाँ पर महाराजप्रमुख, राजप्रमुख और उप-राजप्रमुख के पद थे। राज्यों के पुनर्गठन के बाद राज्यों का यह वर्गीकरण समाप्त हो गया और राजस्थान भी अन्य राज्यों की भाँति भारतीय संघ का एक राज्य बना

दिया गया और महाराजप्रमुख, राजप्रमुख, उप-राजप्रमुख आदि के पदों को समाप्त कर दिया गया और अन्य राज्यों की भाँति राष्ट्रपति, गवर्नर (राज्यपाल) की नियुक्ति करने लगा ।

यह जानना बहुत ही उपयुक्त होगा कि वर्तमान राजस्थान कैसे बना ? सर्वप्रथम (सबसे पहले) अलवर, भगतपुर, बीलपुर, करौली को मिलाकर 18 मार्च, 1948 को मत्स्य सघ (यूनियन) बनाया गया । इसका उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री (वर्कम, माइन्स एण्ड पावर्म) श्री नरहरि विष्णू गाडगिल ने किया । इसके एक मप्नाह बाद राजस्थान सघ का उद्घाटन हुआ जिसमें बाँसवाडा, बूँदी, झगरपुर, भालावाड, किशनगढ़, शाहपुरा और टोक शामिल थे । इसके तीन दिन बाद उदयपुर के महाराणा ने भी इस सघ में सम्मिलित होने के लिए सहमति प्रकट की और नवीन राजस्थान यूनियन बनाया गया । इसकी राजधानी उदयपुर थी । इसका उद्घाटन 18 अप्रैल, 1948 को प्रधानमन्त्री प० जवाहरलाल नेहरू ने किया । मार्च, 1949 में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैमलमेर को मिलाकर बृहत् राजस्थान सघ बनाया गया । इसका उद्घाटन तत्कालीन ग्रह मन्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च, 1949 को किया । 15 मई, 1948 को मत्स्य सघ का शासन भी राजस्थान को सौंप दिया गया । मिर्गोही राज्य को जनवरी, 1950 में दो भागों में बाँट दिया गया । आबू और दिलवाडा के ताल्लुके वम्बई को दे दिये गये और बाकी हिस्सा राजस्थान को दे दिया गया । छह वर्षों के बाद मन् 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद अजमेर, जो 'भी' श्रेणी का राज्य था, राजस्थान में मिला दिया गया तथा साथ ही आबू, जो कि वम्बई में मिला दिया गया था और मध्यप्रदेश का टप्पा मुनैल राजस्थान में मिला दिया गया । इसके बदले में मिर्गोज का इलाका राजस्थान में हटाकर मध्यप्रदेश को दे दिया गया ।

यह है हमारे राजस्थान के निर्माण की कहानी । वर्तमान राजस्थान छोटी-बड़ी 22 भूतपूर्व देशी ग्यामनो को मिलाकर बना है ।

(4) सामाजिक एवं आर्थिक दशा—सामाजिक दृष्टि से राजस्थान का इलाका स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय में ही काफी पिछड़ा हुआ था। इसका कारण यह था कि राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग में आवागमन की सुविधा नहीं थी, लोगों को पढ़ने लिखने के साधन प्राप्त नहीं थे। जागीरदारी प्रथा के कारण गरीबी भी थी। इसके अलावा यह इलाका बहुत से छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था जो कि सामाजिक उन्नति के लिए अधिक कुछ कर सकने में असमर्थ थे। किमान गरीब थे क्योंकि बहुत बड़े भू-भाग में वर्षा की कमी के कारण उन्हें अपनी फसलों के लिए प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यह दूसरी बात है कि इस इलाके के लोगों ने भारत के औद्योगीकरण में प्रमुख भाग लिया है। मारवाटी पूँजीपतियों ने कलकत्ते और बम्बई में कारोबार स्थापित किये हैं और देश के आर्थिक विकास में सहयोग दिया है। देश के अनेक सफल पूँजीपति राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आये हैं।

राजनीतिक दृष्टि से भी राजस्थान पिछड़ा हुआ था क्योंकि यहाँ के राजा और जागीरदार अपनी सत्ता के विरोध में या आलोचना के रूप में कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। राजनीतिक जाग्रति थोड़ी-बहुत ब्रिटिश भारत के सम्पर्क में आने से हुई थी क्योंकि राजस्थान के अनेक लोग ब्रिटिश भारत में व्यापार और नौकरी के मिलमिले में आया-जाया करते थे। परन्तु वह जाग्रति उन्हीं तक सीमित थी। प्रान्त के आन्तरिक भागों में रहने वाली जनता तक शायद यह भावना नहीं पहुँच पाती थी।

कुछ बड़े राज्यों में शासन प्रबन्ध काफी ठीक था, लोगों के विचार जानने के लिए राजा प्रयत्नशील भी थे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राज्यों में लेजिस्लेटिव एसेम्बली भी थी जो जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी, परन्तु छोटे राज्यों में ऐसा नहीं था। वहाँ जागीरदार या राजा का हुक्म ही कानून होता था और उपेक्षा करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाता था।

राजस्थान की जनमग्या को दो भागों में बाँट सकते हैं—ग्रामीण

और गहरी जनता । यहाँ जनमस्या का 47 6 प्रतिशत ही खेती पर निर्भर करता है । यहाँ के काफी लोग (राजपूत, गूजर, जाट) भारतीय सेना में सैनिक और अधिकारी के रूप में काम करते रहे हैं । बहुत नारे दूसरे लोग देश के अन्य भागों में नौकरी आदि करते हैं । इस तरह यह कह सकते हैं कि राजस्थान की जनता आर्थिक दृष्टि से उतनी पिछड़ी हुई नहीं है जितनी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या आसाम, बंगाल आदि में है ।

आज राजस्थान ने अँगड़ाई ली है और परिवर्तन के पथ पर अग्रसर हो रहा है । आज राजस्थान प्रकृति से भगड कर अपनी सत्ता स्थापित करने को उताव्र हो रहा है । विज्ञान को महायत्ना से हजारों एकड़ रेगिस्तानी इलाके अब कृषि योग्य बनाये जा रहे हैं । खेती के पुराने तरीकों का स्थान नये वैज्ञानिक ढंग ले रहे हैं । बहुत जल्दी ही राजस्थान भारत मध्य का एक उन्नतिशील राज्य हो जायेगा ।

(5) राजस्थान की साहित्य-परम्परा—राजस्थान बाहर वालों के लिए सदैव से ही आकर्षण का केन्द्र रहा है । आज भी राजस्थान में काफी तादाद में बाहर से पर्यटक आते हैं । राजस्थान का अपना स्वयं का एक इतिहास है और इसकी अपनी एक परम्परा है । भारतीय इतिहास राजस्थान के वीरों की अनेक ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जो राजपूतों की वीरता एवं शौर्य की अटूट श्रृंखला का निर्माण करती हैं । राजस्थान के राजभवन, गढ़ और पुराने किले पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण के केन्द्र हैं ।

साहित्यिक दृष्टि से राजस्थानी साहित्य बड़ा समृद्ध है । पृथ्वीराज रासो की रचना राजस्थान में हुई थी । डिगल और पिंगल का हिन्दी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान है । मीराबाई की रचनाएँ भी राजस्थानी में ही हैं । राजपूतों ने समय-समय पर भारत के इतिहास में भाग लेने का प्रयत्न किया है, यह दूसरी बात है कि किन्हीं विशेष कारणों-

वण उन्हें सफलता न मिल सकी । यदि 1163 में पृथ्वीराज शाहवुद्दीन गोरी से हार नहीं जाता तो भारतीय इतिहास की रूपरेखा दूसरी होती । इसी तरह यदि राणा सांगा खनवाहा की लड़ाई में हार नहीं जाता तो फिर एक बार इतिहास बदल जाता । अकबर के समय में एक बार फिर से मेवाड़ के शासकों ने स्वतन्त्रता स्थापित करने की चेष्टा की और बहुत हद तक सफल भी हुए ।

आज हमारा नया राजस्थान तेजी से तरक्की कर रहा है । यह तरक्की हर दिशा में हो रही है—राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक । राजनीतिक दृष्टि से हमने सबसे पहले लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का प्रयास किया है । वैसे यह कहा जा सकता है कि उसमें हम कहाँ तक सफल हुए हैं परन्तु परिश्रम का श्रेय हमें है ही । राजस्थान में जहाँ किसी समय जागीरदारी का बोलबाला था वहाँ प्रजानन्त्र और लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण अवश्य ही महत्वपूर्ण कदम है । सामाजिक क्षेत्र में नई उन्नति हो रही है । सामाजिक कुुरीतियों का अन्त किया जा रहा है । पर्दा-प्रथा कम हो रही है । मृतक भोज में अब पहले जैसा उत्साह नहीं दिखाया जाता । प्रान्तों के आन्तरिक भागों में लड़के, लड़कियों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं । औद्योगिक विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है । लड़कियों के लिए कालेज गुल रहे हैं । यह सब विकास के ही तो प्रमाण हैं ।

आर्थिक दृष्टि में राजस्थान के पूँजीपतियों ने अब राजस्थान की ओर भी फिर कर देखा है और नये-नये कन-कारखाने राजस्थान में स्थापित किये जा रहे हैं । राजस्थान नहर बन जाने के बाद राजस्थान के एक बहुत बड़े भू-भाग में पानी की कमी दूर हो जायगी और यह भू-भाग भी उतना ही विकसित और समृद्धिवाली हो जायगा जितना कि आज गगानगर का इलाका है ।

(ग) सामाजिक सेवाएँ—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व राजस्थान की सामाजिक सेवाओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था । छोटी ग़ियानों

के शासक इतना धन सामाजिक सेवाओं पर व्यय भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी आय सीमित थी। दूसरे उनमें सामाजिक सेवाओं को उपलब्ध करने की भावना का भी सर्वथा अभाव था। आज हमारे राज्य में शहरी क्षेत्र में 165 अस्पताल हैं जहाँ कि 7,739 रोगियों को भर्ती किया जा सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 90 सरकारी अस्पताल हैं जहाँ कि 857 रोगियों को भर्ती किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त राज्य में 249 डिस्पेंसरियाँ (औषधालय) भी हैं जिनमें 82 शहरी क्षेत्र में और 167 ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इनके अतिरिक्त विशेष रोगों की चिकित्सा के लिए राज्य में 39 अस्पताल (चिकित्सालय) हैं, जहाँ कि 465 रोगियों को भर्ती किया जा सकता है। इसी प्रकार 41 औषधालय (डिस्पेंसरियाँ) भी हैं जिनमें से 73 शहरी क्षेत्रों में और 4 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राजस्थान के धन सम्पन्न सेटों ने भी चिकित्सालय आदि बनवाने में उचित उत्साह दिखाया है। कुछ चिकित्सालय तो सर्वथा निजी धन से ही चलाये जाते हैं और कुछ में सरकारी और गैर-सरकारी धन का सहयोग रहता है। राज्य में ऐसे 25 चिकित्सालय हैं जो या तो गैर-सरकारी हैं या सरकारी और गैर-सरकारी सहयोग से चलाये जाते हैं इन चिकित्सालयों में 1,414 रोगियों की चिकित्सा का प्रवन्ध है। इसी प्रकार राज्य में 40 औषधालय भी सरकारी और गैर-सरकारी सहयोग से चलाये जा रहे हैं जिनमें 26 शहरी इलाकों में और 14 ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं।

राज्य में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्रयत्न किया है। जयपुर में मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। बीकानेर में दूसरा मेडिकल कॉलेज खोला गया है। दोनों जगहों में निलानर प्रति वर्ष 220 विद्यार्थी डाक्टरों शिक्षा के लिए भर्ती किये जाने की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त राज्य में चैचक उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन तथा अन्य रोगों के उन्मूलन के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे

हैं। नर्सों, प्रशिक्षित दाइयों आदि की कमी को दूर करने के लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जा रही है।

(ग) जागीरदारी उन्मूलन—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सन् 1952 में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम पास किया गया। परन्तु सन् 1954 तक जागीरदारी उन्मूलन का काम पूरा नहीं हो सका। अब ऐसे धार्मिक जागीरदारों को छोड़कर जिनकी आय 1,000 रुपये से कम है, सभी जागीरें समाप्त कर दी गई हैं और इन जागीरदारों को मुआवजा दे दिया गया है जो कि 15 वार्षिक किश्तों में जागीरदारों को दे दिया जायगा। इसी तरह विस्वादारी और जमींदारी की प्रथाओं का भी अन्त कर दिया गया है। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 के अनुसार जो भी रैयत जमीन जोत रहा था वह अब जमीन का मालिक हो गया है।

जागीरदारी उन्मूलन एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है क्योंकि राजस्थान की कृषक जनता जागीरदारों के अत्याचारों से अत्यन्त ही पीड़ित थी। कोई भी किसान अपनी भूमि का मालिक नहीं हो पाता था, फलस्वरूप भूमि की उपज को बढ़ाने के लिए वह पैसा खर्च करना नहीं चाहता था क्योंकि उसे सदैव ही यह भय बना रहता था कि जागीरदार उसे हटा देगा। अब राजस्थान में किसान अपनी भूमि का मालिक हैं। वह अब इस विषय के साथ उस पर पैसे खर्च कर सकता है कि इसका फल उसे और उसके बाल-बच्चों को ही मिलेगा।

(घ) सामाजिक समानता—राजस्थान में सामन्तशाही और जागीरदारी के कारण सामाजिक असमानता बहुत ही अधिक थी। जागीरदारों की कोठियों के आगे उत्तरी लगा कर निकलना या किसी सवारी पर बैठ कर निकलना मना था। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ काफी अन्याय विये जाते थे। भारतीय संविधान के अनुसार अब दृष्टान्त एक दण्टनीय अपराध घोषित कर दिया गया है और सामाजिक समानता को मालिक अधिकारों में सम्मिलित कर लिया गया है। यही

नहीं पिछड़ी हुई जातियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों में, विधान सभाओं में, ससद में, उनके लिए स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। उनके लिए शिक्षण-संस्थाओं में विशेष छात्र-वृत्तियों का प्रबन्ध भी किया जाता है।

यह कहना अनुचित होगा कि राजस्थान में अब सामाजिक समानता स्थापित हो गई है और दृष्टाछूत आदि का अन्त हो गया है। राज्य की जनता का बहुत बड़ा भाग गाँवों में रहता है और वहाँ अभी भी दृष्टा-छूत की प्रथा चालू है। यह दूसरी बात है कि शिक्षित युवक और युवतियाँ इसमें विश्वास न करें, परन्तु घरों में उनका व्यवहार भी प्रायः उसी प्रकार का होता है जैसा कि उनके माता-पिता या अन्य वयोवृद्ध लोगों का होता है। यह इसलिए होता है कि दृष्टाछूत को लोग अब भी घृणास्पद नहीं समझते इसलिए इसके उन्मूलन के लिए जो भी कदम उठाया गया है यह जनता की वास्तविक माँग न होकर उन पर थोपी गई वस्तु-सी हो गई है।

(ड) अनुसूचित जातियाँ या जन जातियाँ—राज्य में प्रायः 23 लाख के लगभग अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लोग रहते हैं। यदि सारे पिछड़े वर्गों को देखा जाय तो इनकी संख्या प्रायः 68 लाख के करीब हो जायगी, इन लोगों की आर्थिक दशा अत्यन्त ही दयनीय है। इसमें दो बातें पैदा हो जाती हैं। पहली तो यह कि वे राज्य को कर (टैक्स) नहीं दे सकते अतः राज्य की आय कम हो जाती है और दूसरी यह कि राज्य को इनके लिए शिक्षा, चिकित्सा और दूसरी सुविधाओं को उपलब्ध करना पड़ता है।

राज्य इन लोगों की सहायता देने के लिए कई प्रकार से काम करता है, जैसे उनके विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का प्रबन्ध, छात्रालयों (होस्टलो) का प्रबन्ध, आश्रम, स्कूल आदि। ऐसी संस्थाओं को सहायता दी जाती है जो कि अनुसूचित जातियों के बीच काम करती हैं। बहुतों के पास भूमि नहीं है उन्हें भूमि पर बसाने का प्रबन्ध किया जाता है।

सिंचाई और पीने के पानी के लिए कुए खुदवाये जाते हैं। 1962-63 में राज्य सरकार ने 13 05 लाख रुपया अनुसूचित जातियो एव जन-जातियो की उन्नति के कार्या पर खर्च किए।

आर्थिक

(क) सिंचाई एव जल-विद्युत—राजस्थान के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होने का एक कारण यह भी है कि राज्य के बहुत बड़े भाग में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में कई बड़े-बड़े बाँव और नहरें आदि बनाने की योजनाएँ बनाई गई हैं जिसमें राजस्थान की विजली और पानी की कमी पूरी की जा सके। इस सम्बन्ध में चम्बल योजना, राजस्थान नहर योजना आदि का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। यदि ये सब योजनाएँ पूरी हो जाए तो राजस्थान खाद्यान्न की दृष्टि से केवल आत्म-निर्भर ही नहीं हो जायगा बल्कि यहाँ में खाद्यान्न दूसरे राज्यों में भेजा भी जा सकेगा।

आर्थिक दृष्टि में राजस्थान खेती पर ही निर्भर करता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 70 प्रतिशत लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। राज्य के क्षेत्रफल का 88 प्रतिशत भू-भाग अभी केवल वर्षा पर ही निर्भर करता है। राजस्थान सरकार खेती को विशेष महत्त्व देती है। नहर और सिंचाई योजनाओं के अलावा यंत्रीकृत फार्म (मेकेनाइज्ड फार्म) की भी स्थापना की गई है। नूरतगढ़ में सोवियत संघ से सहायता के रूप में प्राप्त मशीनों की सहायता से 30 हजार एकड़ का एक फार्म खोला गया है।

(ख) कल-कारखाने—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद में कल-कारखानों और उद्योग-धन्धों का भी प्रोत्साहन देने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। पूँजीपतियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे राजस्थान में अपनी पूँजी लगायें। राजस्थान वित्त-निगम (राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन) मध्यवर्गीय और छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता भी देता है। छोटे-छोटे उद्योगों के लिए स्मान स्केल सर्विस

इन्स्टीट्यूशन की स्थापना भी की गई है जहाँ पर छोटे उद्योगपतियों को वैज्ञानिक और दूसरी प्रकार की जानकारी दी जाती है। कुटीर-उद्योगों की भी प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

वैसे उद्योग की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रान्त रहा है। क्योंकि आवागमन के साधनों का पूर्ण विकास न होने के कारण यहाँ के पूँजीपति अपनी पूँजी दूसरी जगहों पर ही लगाते थे, फिर यहाँ पर पानी और सस्ती विजली की भी कमी थी। इस समय राजस्थान में प्रायः 800 फैक्टरियाँ हैं जिनमें प्रायः 55 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। इनमें 125 फैक्टरियों को बड़ी फैक्टरियों की गिनती में रखा जा सकता है। राज्य में चीनी, कपड़े और खनिज उद्योग सम्बन्धी व्यवसाय उन्नति कर रहे हैं।

सरकारी सहायता के फलस्वरूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रायः 2,000 छोटे उद्योग-वन्धे चालू किये गये। उसमें से 640 इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, 62 नान-फैरम मेटल इण्डस्ट्रीज, 150 केमिकल इण्डस्ट्रीज और 1,100 से ऊपर साबुन, वालों के तेल आदि के कारखाने खोले गये हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में 260 86 लाख रुपया इन उद्योगों के विकास पर खर्च किया जायगा। इसका विस्तृत व्यौरा इस प्रकार है —

	(लाख रुपये में)
टैण्डलूम और उन (हाथ कर्घा और ऊन)	22 41
ट्रेनिंग, कर्ज, सहायता आदि	161 35
खादी और ग्रामोद्योग	10 00
एग्रीकल्चर	1 00
टैण्ड्रीक्राफ्ट (हस्तकला)	6 50

(ग) सहकारिता—सन् 1953 में राजस्थान कोऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट बना, जिसमें सारे राज्य में सहकारिता के लिए एक-सा नियम बनाया गया। पिछले दस वर्षों में सहकारी आन्दोलन ने राजस्थान में

काफी तरक्की की है। क्रय-विक्रय (मार्केटिंग) समितियाँ, सहकारी बैंक, औद्योगिक (इण्डस्ट्रीयल) सहकारी समितियाँ, उपभोक्ता भण्डार (कन्ज्यूमर स्टोर्स) आदि सहकारिता के आधार पर खोले गये हैं। राजस्थान में सहकारिता के आन्दोलन की सफलता का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जबकि लक्ष्य केवल 6,000 सहकारी समितियों के निर्माण का था। राजस्थान के इस काल में प्रायः 7,000 सहकारी समितियों का निर्माण किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में 400 लाख रुपये सहकारिता पर खर्च करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है। सहकारिता के विकास के लिए कोऑपरेटिव एक्सटेन्शन आफिसर पंचायत समितियों में भेजे गये हैं। सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए रिजर्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से कोटा में एक संस्था खोली गई है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह 1950 से काम कर रही है और अब तक प्रायः 550 व्यक्ति यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- 1 राजस्थान राज्य के निर्माण का वर्णन करते हुए उसकी सामाजिक एवं आर्थिक दशा का उल्लेख करें।

राजस्थान राज्य की कार्यपालिका

राजस्थान राज्य की कार्यपालिका के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल और मन्त्रिमण्डल आते हैं। राज्य के वर्तमान राज्यपाल श्री सम्पूर्णानन्द जी और वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल मुखाडिया हैं। सविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, परन्तु कार्य रूप में राज्यपाल सवैधानिक प्रधान में अधिक नहीं है। राज्यपाल की स्थिति ठीक उसी प्रकार की है जैसी केन्द्रीय प्रशासन में राष्ट्रपति की है। केवल एक ही अन्तर दोनों में देखा जा सकता है और वह यह है कि जबकि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं, राज्य की विधान सभा राज्यपाल को हटा नहीं सकती। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वह राष्ट्रपति के प्रामाद पर्यन्त अपने पद पर रहता है।

शासन के सभी काम राज्यपाल के नाम से होते हैं, परन्तु शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग मन्त्रिमण्डल करता है। जैसे यदि पूछा जाय तो मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी अपने अधिकारों का स्वयं उपयोग न कर अपने नीचे के अधिकारियों को दे देते हैं। उसी तरह मन्त्रिमण्डल के सदस्यों या राज्यपाल के नाम में अनेक कार्य होते हैं जिनका कि उन्हें पता भी नहीं रहता। यह ठीक उसी प्रकार की स्थिति है जिसके बारे में लन्दन के किसी सम्राट ने कहा था कि बहुत से कामों को जो कि मैं करता हूँ मुझे तब पता चलता है जबकि मैं दूसरे दिन समाचार-पत्र पढ़ता हूँ।

राज्यपाल

राज्य पुनर्गठन के पहले राजस्थान में राज्यपाल का पद नहीं था। यहाँ पर राजप्रमुख, उपराजप्रमुख और महाराजप्रमुख के पद थे। अब अन्य राज्यों की भाँति राजस्थान में भी राज्यपाल की नियुक्ति होने लगी है। वर्तमान राज्यपाल राजस्थान के दूसरे राज्यपाल हैं। पहले राज्यपाल श्री गुरुमुख निहालमिह थे। राज्यपाल की योग्यताएँ, वेतन तथा भत्ते एवं अधिकार आदि पर विस्तार से वर्णन राज्यों की सरकार वाले अध्याय में कर दिया है।

राज्यपाल की स्थिति

राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, परन्तु राज्य का प्रमुख शासक नहीं होता। वर्तमान संविधान में उसकी स्थिति एक संवैधानिक प्रमुख से अधिक नहीं है। यद्यपि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है फिर भी अपने पद पर बने रहने के लिए आवश्यक है कि वह राज्य विधान सभा के बहुमत दल के नेता से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता हो अन्यथा उसका राज्यपाल पद पर बना रहना सम्भव नहीं हो सकता। वैसे भी वर्तमान संविधान में ऐसी शक्तियाँ जिनमें कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से काम करे, बहुत ही कम हैं। उसका कार्य मन्त्रिमण्डल की सलाह से होना चाहिए जो कि राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्य विधान सभा के प्रति मन्त्रिमण्डल अपना उत्तरदायित्व तभी निभा सकता है जबकि राज्यपाल मन्त्रिमण्डल के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल सके। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाय जबकि राज्य विधान सभा में किसी एक दल का प्रत्यक्ष बहुमत न हो तो उस दल में राज्यपाल कुछ अधिक शक्तिशाली बन सकता है। यदि संवैधानिक संकट की निपोट राष्ट्रपति का भजनी हो तो वह अपने स्वविवेक से ही काम करेगा।

राज्यपाल कभी भी एक स्वच्छाचारी शासक नहीं बन सकता। शान्तिमान में उसे अपने मन्त्रिमण्डल की सलाह से कार्य करना पड़ेगा।

ओर यदि सकटकालीन अवस्था आ गई है तो उसे राष्ट्रपति और केन्द्रीय ससद की सलाह पर काम करना पड़ेगा ।

मन्त्रिपरिपद् ही राज्य की वास्तविक कार्यकारिणी होती है । इसमें विधान सभा के बहुमत वाले राजनैतिक दल के सदस्य होते हैं । मन्त्रिपरिपद् का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यह विधान सभा के प्रासाद काल पर्यन्त शासन का भार सभालती है । मन्त्रिपरिपद् को हम एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली समिति कह सकते हैं, जिसने कि विधान सभा के सारे अविकारो को अपने हाथों में ले लिया है और जो राज्य की सर्वोच्च प्रशासकीय सस्था बन गई है ।

मन्त्रिमण्डल

मन्त्रिपरिपद् में एक मुख्यमन्त्री व अन्य मन्त्री होते हैं । मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की सन्ध्या सेविधान में निर्धारित नहीं है, आवश्यकतानुसार मुख्यमन्त्री इसको घटा-बढ़ा सकता है । तृतीय आम चुनाव के पश्चात् सभी राज्यों के मन्त्रिमण्डलों की सन्ध्या में बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई थी । मन्त्रियों के अतिरिक्त उपमन्त्री भी होते हैं, जो कि मन्त्रियों की सहायता करते हैं । उपमन्त्री मन्त्रिपरिपद् के सदस्य तो होते हैं, परन्तु मन्त्रिमण्डल या कैबिनेट के सदस्य नहीं होते । साधारणतया उन्हें मन्त्रिमण्डल की बैठकों में भाग लेने का अधिकार भी नहीं होता, परन्तु उन्हें विशेष रूप से आमन्त्रित अवश्य किया जा सकता है । राजस्थान में आजकल मन्त्रिपरिपद् के निम्नलिखित सदस्य हैं —

मन्त्रि-गण

विभाग

श्री मोहनलाल सुखाड़िया

मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, गृह, राज-
नैतिक नियुक्तियाँ, गजस्त्र, अकाल,
सहायता और पुनर्वास (कोलोनाइजेशन)
महिन, सहकारिता, खनिज एवं खनिज
सम्बन्धी उद्योग, योजना, गृह-निर्माण
(हाउसिंग) एवं साक्ष्यकी (स्टेडिस्टिक्म) ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय	शिक्षा, देवस्थान, खादी एव ग्रामोद्योग, पूर्ति-विभाग (सिविल सप्लाइज) और उद्योग (वृहद्-उद्योग एव खनिज सम्बन्धी उद्योगों को छोड़कर) ।
श्री मथुरादाम माथुर	नियोजन, कानून, न्याय, विधान सभा, चुनाव एव प्रचार ।
श्री नाथूराम मिर्धा	कृषि, पशु-पालन, वृहद् मिर्चाई योजनाएँ स्टेट उद्योग, खनिज उद्योग, एव खाद्य ।
श्री हरिश्चन्द्र	जन-कार्य (पब्लिक वर्क्स), ट्रान्सपोर्ट, वृहद् उद्योग (यातायात), शक्ति (पावर), छापेखाने (प्रिंटिंग प्रेसेज) ।
श्री बालकृष्ण कौल	वित्त, एक्साइज एव टेक्मेशन ।
श्री भीष्मा भाई	मिर्चाई (वृहद् मिर्चाई योजनाओं को छोड़ कर), वन, लेबर, आयुर्वेद, समाज कल्याण, रिलीफ एव पुनर्वास, पंचायतराज ।
श्री बरकतुल्ला खाँ	चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य एव लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट (स्वायत्त-शासन) और नगर निर्माण (टाउन प्लानिंग) ।
उपमन्त्री	
श्री दौलतराम मारग	वृहद् मिर्चाई, स्वायत्त शासन और आयुर्वेद ।
श्रीमती कमला बेनीवान	योजना और विकास, कृषि और पशु-पालन अकाल-महायना (फैमाइन-रिलीफ), तथा सरकारी उद्योग (स्टेट-एन्टरप्राइज) ।
श्रीमती प्रभा मिश्रा	चिकित्सा, समाज-कल्याण, लॉ, जन-स्वास्थ्य ।
श्री परमराम मदेरगा	सामान्य-प्रशासन, महायना एवं पुनर्वास

(रिलीफ एव गृहविलिटेसन), शक्ति
(पावर) न्याय एव गृह-निर्माण ।

- श्री रामप्रसाद लड्ढा राजस्व, खान एव देवस्थान ।
 श्री चन्दनमल वंश शक्ति, नागरिक पूर्ति और उद्योग ।
 श्री दिनेशराज डागी माध्यमिक एव लघु सिचाई योजनाएँ
 खादी एव ग्रामोद्योग तथा लघु वस्त्र ।
 श्री निरजननाथ आचार्य गृह, शिक्षा, वन एवसाइज एव टेक्मेशन ।
 श्री भीमसिंह गृह, यातायात एव सहकारिता ।

नियुक्ति—राज्यपाल पहले मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है । मुख्यमन्त्री की सलाह से मन्त्रियों एव उपमन्त्रियों की नियुक्तियाँ होती । राज्यपाल उसी को मुख्यमन्त्री नियुक्त करेगा जो कि विधान-मण्डल बहुमत दल का नेता होगा । अतः जब तक कि ऐसी स्थिति नहीं हो जा है कि किसी भी दल का प्रत्यक्ष बहुमत न हो, राज्यपाल को मुख्यमन्त्री या मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने का अवसर नहीं मिलेगा । राज्यपाल की सिफारिश पर कोई व्यक्ति मन्त्रिमण्डल में लिया जा सकता है या किसी व्यक्ति का नाम सर्वोच्च सूची से हटाया जा सकता है, परन्तु ऐसा करने की जिम्मेदारी मुख्यमन्त्री पर रहेगी और मन्त्रिमण्डल के सदस्य कौन होंगे इसका अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्री को करना है न कि राज्यपाल को । नियुक्ति की आज्ञाएँ राज्यपाल के नाम से प्रकाशित होती हैं और राजकीय गजट में प्रकाशित की जाते हैं । प्रत्येक मन्त्री और उपमन्त्री को पद ग्रहण करने के पूर्व मन्त्रिमण्डल के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई जाती है ।

मुख्यमन्त्री की राय से राज्यपाल कार्य-विभाजन करता है । विभाग का अध्यक्ष एक मन्त्री होता है, यदि विभाग बड़ा हो तो मन्त्री की सहायता के लिए उपमन्त्री आदि भी नियुक्त कर दिये जाते

दिए जाते हैं। उपमन्त्री स्वतन्त्र रूप से विभागों के अध्यक्ष नहीं बनाये जाते हैं, वे सदैव किसी न किसी के अधीन कार्य करते हैं।

योग्यताएँ— मन्त्रिमण्डल का सदस्य होने के लिए विधान-मण्डल का सदस्य होना आवश्यक है। परन्तु ऐसा व्यक्ति भी अस्थायी रूप से मन्त्री बनाया जा सकता है जो कि विधान सभा का सदस्य नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए विधान में यह निर्देश है कि उसे 6 महीने के अन्दर विधान सभा का सदस्य चुन लिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। साधारणतया यह होता है कि पहले उसे मन्त्री बना लिया जाता है और उसके बाद दल का कोई सदस्य त्यागपत्र दे देता है और उस चुनाव-क्षेत्र से चुनाव में ऐसा व्यक्ति चुन लिया जाता है।

वेतन एवं भत्ता— मन्त्रियों के वेतन एवं भत्ते समय-समय पर विधान सभा द्वारा तय किये जाते हैं और विधान सभा उन्हें जब भी चाहे बदल सकती है। राजस्थान में निम्नलिखित दर से इस समय वेतन दिया जाता है —

(1) मुख्य मन्त्री	1000 रु० प्रतिमाह तथा 500 रु० " भत्ता
(2) अन्य मन्त्री	1000 रु० "
(3) उपमन्त्री	800 रु० "

इसके अतिरिक्त मन्त्रियों को बिना किराये का निवास स्थान तथा मवागी भी राज्य की ओर से दी जाती है। यदि कोई मन्त्री राजकीय वॉगले में नहीं रहता है तो उसे इसके बदले में 250 रु० प्रतिमाह का भत्ता जीर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई मन्त्री राजकीय मवागी का उपयोग नहीं करता है तो उसे 250 रु० प्रतिमाह का भत्ता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मन्त्रियों को दौरे जादि करने के लिए भत्ते दिये जाते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 अपने राज्य की कार्यपालिका पर एक निबन्ध लिखिए।

मन्त्रियों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे दिन-प्रतिदिन के प्रशासन का कार्य-भार सँभाल सकें। इस कारण प्रशासन के विभिन्न विषयों के लिए सचिव होते हैं। इसी 'सचिव' शब्द से सचिवालय शब्द बना है। हर राज्य में प्रशासन के लिए एक सचिवालय होता है जिसमें अलग-अलग विषयों के लिए या कुछ विषयों के समूह के लिए विभाग होते हैं। सारा सरकारी काम इसी सचिवालय में होता है। प्रत्येक विभाग अपने-अपने विषयों के लिए नीति निर्वाहित करता है और इन नीतियों को कार्यरूप में परिणत करवाता है। अपने-अपने विषयों में प्रगति की जिम्मेदारी इन विभागों की होती है। वास्तव में कार्यरूप में परिणत करने का काम डायरेक्टर और इसके अधीनस्थ अधिकारियों का होता है। उदाहरण के लिए पुलिस विभाग लीजिए। सचिवालय के स्तर पर गृह-विभाग में पुलिस की नीति आदि निर्धारित की जाती है। इन नीतियों को कार्यरूप में परिणत करने का काम इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का है। शिक्षा सम्बन्धी नीतियाँ शिक्षा मंत्रालय के सचिवालय में निर्धारित की जाती हैं। कार्यरूप में परिणत करने का काम राज्य के डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन का है।

विभागों की व्यवस्था

प्रत्येक विभाग का प्रधान एक सचिव होता है। सचिव का यह उत्तरदायित्व होता है कि उसके अधीन विभाग की व्यवस्था सुचारु रूप में चले व कार्य की गति व कुशलता उचित हो। एक विभाग के लिए सचिव ही मन्त्री का प्रमुख सलाहकार होता है।

सचिव की सहायता के लिए उप-सचिव और सहायक-सचिव भी होते हैं। सहायक-सचिव उप-सचिव से छोटा होता है। साधारणतया उप-सचिव व सहायक-सचिव एक विभाग में एक-एक अधिक होते हैं। जैसे किसी विभाग में एक सचिव, दो उप-सचिव और तीन सहायक-सचिव हो सकते हैं। इन उप-सचिवों को कुछ भिन्न-भिन्न विषय साप-दिये जाते हैं, जिससे सचिव पर अधिक बोझ न पड़े। इतना होने पर भी सारे विभाग के काम की जिम्मेदारी सचिव पर ही होती है। जब विषय बहुत महत्वपूर्ण हो और नीति से सम्बन्धित हो तो सचिव को मन्त्री के पास तक जाना पड़ता है। कभी-कभी उप-सचिवों को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वे सीधे ही मन्त्री से परामर्श कर सकते हैं और सचिव को बीच में छोड़ सकते हैं। यह काम में शीघ्रता लाने के लिए किया जाता है। परन्तु इस रीति से कोई हानि नहीं होती क्योंकि सचिव जब भी चाहे इस प्रकार के विषयों के द्वारा उप-सचिव से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से एक विभाग में इन तीन प्रकार के अधिकारियों द्वारा कार्य चलता है।

परन्तु यह बात ध्यान में रखने की है कि एक विभाग में दिन में सैकड़ों पत्र आते हैं व सब भिन्न-भिन्न समस्याओं को लिये होते हैं। इन पत्रों के उपर विभाग में ही निर्णय लिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी काम इतना अधिक फैला हुआ होता है कि केवल सचिव, उप-सचिव, और सहायक-सचिव ही वह सब कुछ नहीं कर सकते। इन सब की सहायता के लिए कई कर्मचारी होते हैं जो कि सारे दफ्तर का काम करते हैं, जैसे चिट्ठियों को रजिस्टर में चढ़ाना, उनको फाइल करना, उनके जवाबों को टाईप करना, उनको भेजना आदि-आदि। यह सब कर्मचारी अपने अधिकारियों के आदेशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। एक विभाग में बहुत-से ऐसे कर्मचारी होते हैं और एक सचिवालय में तो यह दफ्तरों की मर्यादा में पाये जाते हैं।

प्रत्येक विभाग कुछ खण्डों (Sections) में बंटा हुआ होता है।

प्रत्येक खण्ड अलग-अलग विषयों के लिए होते हैं। इस प्रकार से विभाग के सारे काम को अलग-अलग खण्डों में बाँट देने से काम अच्छी तरह हो जाता है, और कुशलता बढ़ जाती है। प्रत्येक खण्ड एक खण्ड-अधिकारी के नीचे होता है। एक खण्ड में कई कर्मचारी होते हैं। मुख्यतः यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो अधिक योग्यता व ऊँचे पद वाले बाबू या क्लर्क और एक कम ऊँचे पद व योग्यता वाले बाबू। ऊँचे पद वाले उच्च स्तरीय कर्मचारियों को नीचे पद वाले या निम्न स्तरीय कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलता है। एक विभाग में साधारणतया पाँच उच्च स्तरीय कर्मचारी होते हैं। जिन विभागों में पाँच से अधिक उच्च स्तरीय अधिकारी होते हैं वहाँ एक अतिरिक्त कर्मचारी भी होता है जो खण्ड-अधिकारी के नीचे होता है और क्लर्कों से ऊपर। इसको 'सहायक' कहते हैं।

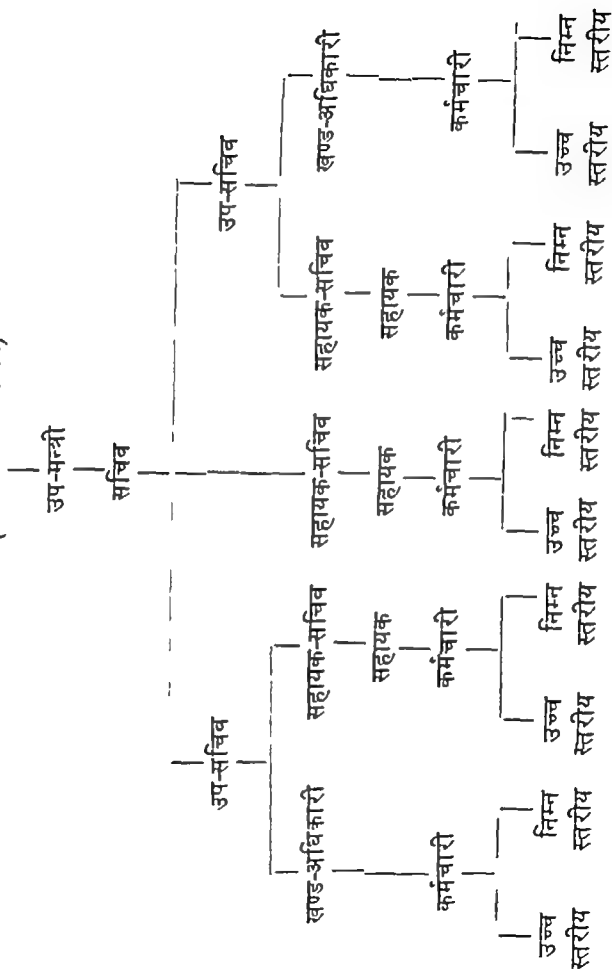
कार्य की गति शीघ्र करने के लिए एक खण्ड में भी आजकल कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं। प्रत्येक खण्ड को भी दो भागों में बाँट दिया जाता है। एक भाग तो खण्ड-अधिकारी मँभालता है और एक सहायक-सचिव। काम बाँट जाने में वह अधिक सरल हो जाता है।

यह ध्यान रखने की बात है कि पहले प्रत्येक पत्र नीचे के एक कर्मचारी से लेकर ऊपर सचिव तक जाता था, तब कही जाकर उस पर फैसला किया जाता था। आजकल यह प्रयत्न किया जाता है कि कोई भी पत्र अधिक से अधिक तीन हाथों से गुजरें और उस पर अधिक व्यक्तियों का समय नष्ट हुए बिना निर्णय ले लिया जाय।

राजस्थान में सरकारी विभाग

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जब राज्यों का अपना-अपना प्रशासन हुआ तब से शासन सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। इस समय राजस्थान में निम्नलिखित प्रमुख-प्रमुख विभाग हैं। संक्षेप में उनके कार्यों का वर्णन इस प्रकार है —

एक विभाग की व्यवस्था
मन्त्री (मन्त्रिवालय स्तर पर)



(1) गृह विभाग—यह राज्य का सबसे प्रमुख विभाग है। इसका कार्य राज्य में शान्ति, न्याय एवं व्यवस्था रखने का होता है। इसके अन्तर्गत कई मुख्य विषय आते हैं जैसे पुलिस का प्रशासन, हथियारों पर प्रतिबन्ध, मोटर यातायात, जेलें, छापेखाने, जन-सम्पर्क, सरकारी प्रकाशन, विदेशों में जाने के लिए पासपोर्ट, राज्य की सुरक्षा आदि।

(2) वित्त विभाग—सारा प्रशासन धन से चलता है, इस कारण इस विभाग का बहुत महत्व है। इसके प्रमुख कार्यों में राज्य का वजट बनाना, खर्चों का निर्णय करना, धन प्राप्ति के साधन जुटाना, कर लगाना, मुद्रा का प्रशासन करना, सरकारी खातों का बनवाना, पैसे को उधार लेने या देने सम्बन्धी बातें, सरकारी खजानों का प्रबन्ध, सरकारी बीमा व अन्य सरकारी विभागों को आर्थिक अधिकार देना आदि हैं।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग—जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस विभाग के सारे कर्तव्य प्रशासन की सामान्य समस्याओं से सम्बन्धित होते हैं, जैसे सरकारी काम के नियम बनाना, विभिन्न विभागों को काम करने का स्थान देना, उनके लिए भवन बनवाना, सरकारी अधिकारियों के घरों का प्रबन्ध करना, दफ्तरों में बिजली का इन्तजाम करना, छुट्टियों के बारे में निर्णय देना, सरकारी पुस्तकालयों का प्रबन्ध करना, जनगणना सम्बन्धी काम करने में केन्द्र को सहायता देना आदि।

(4) नियुक्ति विभाग—राज्य के समस्त सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी प्रशिक्षा (Training), उनकी तरक्की, उनमें अनुशासन आदि बातें इस विभाग के अन्तर्गत आती हैं। नियुक्ति के लिए यह अलग-अलग परीक्षाएँ करवाता है और अन्य नियम निर्धारित करता है। सारे सचिवालय में काम करने वाले व्यक्तियों की भी नौकरी सम्बन्धी बातें इसी विभाग द्वारा निर्धारित होती हैं। जिला परिषदों और पंचायत समितियों में नियुक्तियों के लिए 'चयन आयोग' और राजस्थान का जन-सेवा आयोग जो व्यक्तियों को परीक्षाओं के द्वारा छांटते हैं, इसी विभाग के आधीन होते हैं।

(5) शिक्षा विभाग—इस विभाग का प्रमुख कार्य राज्य में शिक्षा की सभी समस्याओं को हल करना, शिक्षण-संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों का प्रशासन, प्रौढ शिक्षा, कला संस्थाएँ, सैनिक शिक्षा एवं यात्रिक प्रशिक्षण का प्रवन्ध आदि हैं। समस्त प्राथमिक पाठशालाएँ, माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाएँ जिनमें सभी कालेज शामिल हैं, इसी विभाग की देखरेख में काम करती हैं।

(6) योजना विभाग—भारत में चूँकि समस्त आर्थिक विकास योजनाबद्ध होता है व प्रत्येक राज्य में भी अपनी वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएँ होती हैं, इसलिए योजना विभाग का महत्व काफी बढ़ गया है। इस विभाग का प्रमुख कार्य सारे राज्य के लिए योजना बनाना व उसको कार्य रूप में बदलना होता है। इसी का कर्तव्य है कि यह देखे कि राज्य में विभिन्न साधनों से कितना धन जुट सकता है, केन्द्र से कितना पैसा मिल सकता है व इस समस्त धन का उपयोग, उद्योग, कृषि, समाज सेवाओं, यातायात आदि में किस प्रकार किया जाय जिससे कि राज्य की आर्थिक स्थिति अधिक से अधिक सुदृढ़ हो सके। इस विभाग को सचिवालय व बाहर के सभी विभागों में सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है व उनकी अपनी योजनाओं को मिलाकर राज्य स्तरीय योजना बनानी पड़ती है। इसका सम्बन्ध केन्द्र के योजना आयोग से बहुत निकट का है क्योंकि समस्त राज्यों के योजना विभागों को योजना की नीति का पालन करना पड़ता है।

(7) उद्योग एवं खनिज विभाग—इस विभाग का प्रमुख कार्य राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य पर नियन्त्रण रखना, उद्योगों की वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण, लघु कुटीर, ग्राम सहकारी उद्योग का प्रशासन, उद्योगों के विकास एवं योजना का प्रवन्ध, फैक्टरियों को परमिट देना, राज्य की गन्तों, तेल और खनिजों पर नियन्त्रण, नमक उत्पादन, तौल और माप, भूगर्भ अन्वेषण, औद्योगिक आविष्कार एवं ट्रेड मार्क आदि

है। राज्य में औद्योगिक प्रगति एवं खनिजों में उन्नति का उत्तरदायित्व इसी पर है।

(8) राजस्व विभाग—इस विभाग के अधीन प्रमुख विषय भूमि का प्रबन्ध है। जमीन पर अधिकार, जमीन के मालिक व किरायेदारों के बीच का सम्बन्ध, कृषि योग्य भूमि का वेचना, कृषि ऋण, जागीरें, पट्टे, भूमि के लगान का निर्धारण व उसका इकट्ठा करना, बाढ़ और अकाल सहायता, राजस्व बोर्ड का प्रशासन आदि अन्य प्रमुख विषय भी इसी के अन्तर्गत प्रशामित होने हैं।

(9) वन-विभाग—इस विभाग का प्रमुख काम राज्य के वनों की सुरक्षा, उनका काटना, शिकार की जगहों का प्रबन्ध, जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना, बेकार व खतरनाक जंगली जानवरों को मारने पर इनाम देना आदि मुख्य हैं।

(10) कर एवं छावकारी विभाग—इस विभाग के प्रमुख कार्य नशीली वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण पर प्रतिबन्ध, उनके बाहर आने-जाने पर नियन्त्रण, कोर्ट फी व अन्य टिकटों की दर निर्धारित करना, मकानों, धन्धों, व्यापारों, नौकरियों, जानवरों, सड़कों व नहरों द्वारा आने-जाने वाले समान, मनोरंजन, जुआ, मट्ठा, बिक्री, कृषि-आय आदि पर कर लगाना व उससे सम्बन्धित प्रशासनिक समस्याओं को हल करना है।

(11) कृषि-विभाग—इस विभाग में कृषि से सम्बन्धित सभी विषय आ जाते हैं जैसे कृषि की शिक्षा, खोज, पौधों का संरक्षण, कृषि पदार्थों की बिक्री, मछली उद्योग, घी, फल, अण्डे, मांस, सब्जियों का उत्पादन व वितरण, भूमि का कटाव, अधिक अन्न एवं मज्जी उपजाओ आन्दोलन, जमीन को अधिक उपजाऊ बनाना, भेड़ एवं ऊँट उद्योग आदि।

(12) नागरिक पूर्ति (Supplies) विभाग—इस विभाग का प्रमुख काम गुड़, तेल व तिनहन की कीमतों, उनका वितरण, उनके राज्य के विभिन्न भागों में आने-जाने आदि विषयों पर नियन्त्रण रखना है।

खाद्यान्न इसी विभाग के अन्तर्गत एक अलग विभाग है जिसका काम खाद्यान्नों एवं चीनी की कीमतों, राशनिंग, वितरण आदि समस्याओं को सुलझाना है ।

(13) स्वायत्त शासन विभाग—इस विभाग के अधीन ही समस्त नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, एवं अन्य स्वायत्त शासन संस्थाओं का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण होता है । एक स्थानीय क्षेत्र में विक्री अथवा उपभोग के लिए आने वाली वस्तुओं पर कर लगाना, श्मशान गृहों का प्रबन्ध करना, नगर निगमों अथवा ग्राम पंचायतों के बाजारों का प्रबन्ध, ग्रामों में पीने के पानी का प्रबन्ध, निम्न व मध्य वर्ग के मकानों का निर्माण, सफाई आदि काम इसी विभाग के अन्तर्गत हैं ।

(14) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य विभाग—राज्य के समस्त अस्पतालों, यूनानी व आयुर्वेदिक औषधालयों, पागलखानों का प्रबन्ध इसी विभाग के अधीन होता है । स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं में लगे व्यक्तियों की जरूरतें पूरी करना, चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध करना, शिक्षण-संस्थाओं में स्वास्थ्य की जांच करना, भोजन, दूध व दूध से बने पदार्थों में मिलावट को रोकना, जन्म व मृत्यु के सम्बन्ध में आकड़े इकट्ठे करना, एवं 'रेड क्रॉस' के कार्यों पर नियन्त्रण रखना आदि कुछ अन्य प्रमुख विषय हैं जो इस विभाग के क्षेत्र में आते हैं ।

(15) जन-निर्माण विभाग—राज्य की भूमि एवं भवन का प्रबन्ध, सड़कों, पुलों, आन्तरिक जल यातायात, नगरों में जल का प्रबन्ध, सरकारी बाग आदि कार्य इस विभाग के अधीन आते हैं ।

(16) श्रम विभाग—सरकारी अथवा व्यक्तिगत उद्योगों, व्यापारों अथवा सेवा में लगे सभी कर्मचारियों की समस्याएँ इसी विभाग के अन्तर्गत आती हैं । मजदूरों की भलाई की योजनाएँ, उनके काम करने के घण्टे व स्थान, काम करते समय शारीरिक चोट लगने अथवा मृत्यु होने पर हर्जाना, औरतों व बच्चों में काम कराना, वृद्धों

को पेंशन देना, खानों में सुरक्षा का वातावरण करवाना, मजदूरों को उनके काम के लिए प्रशिक्षा देना, समाज कल्याण, सामाजिक बीमा, मजदूरों के संगठन, औद्योगिक भग्गडे, वेतन का भुगतान आदि प्रमुख विषय इसी विभाग के अन्तर्गत हैं ।

(17) चुनाव विभाग—इस विभाग का काम राज्य विधान सभा व लोक सभा के लिए राजस्थान से चुनावों का प्रवन्ध करना है ।

(18) शक्ति विभाग—विद्युत, जल विद्युत एवं इन्जीनियरिंग में खोज इस विभाग के अधीन आने वाले विषय हैं ।

(19) सहकारिता विभाग—ग्राम निर्माण एवं सहकारी संस्थाओं का प्रवन्ध इस विभाग की जिम्मेदारी है । राज्य में सहकारिता आन्दोलन इसी आधार पर आगे बढ़ता है ।

(20) सहायता एवं पुनर्वास विभाग (Relief and Rehabilitation Department)—इस विभाग का कार्य पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को आर्थिक रूप से सहायता देना, उनके लिए मकान बनवाने के लिए ऋण देना आदि है । ज्यों ही शरणार्थियों की समस्या हल हो जायगी, इस विभाग का बन्द कर दिया जायेगा ।

(21) न्याय विभाग—राज्य में न्याय का प्रशासन, न्यायालयों की व्यवस्था, कोर्ट फीस, नव प्रकार के कानून बनवाना व उनको कार्य रूप में परिणत करना इस विभाग का प्रमुख कार्य है ।

इसी विभाग की दूसरी शाखा कानून विभाग है जिसका कार्य विधान सभा के सामने कानून बनाने के लिए बिल तैयार करना, राजस्थान विधान सभा की व्यवस्था करना, समस्त कानूनों को समय-समय पर सशोधित करना व राजस्थान के राजपत्र (Gazette) में समस्त कानूनों को छपवाना है ।

(22) विधि बोधक कार्यालय एवं विधि विभाग (Legal Remembrancer's Office and Legal Affairs Department)—इस

विभाग का कार्य भी न्याय विभाग से मिलता-जुलता है। सरकार के विरुद्ध मुकदमों का लड़ना, विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह को इकट्ठा करके निर्णय लेना, कानूनी धन्धे से सम्बन्धित नियम बनाना, सरकारी वकीलों की नियुक्ति आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

(23) पशु-पालन एवं समाज कल्याण विभाग—पशुओं की नस्ल को उन्नत करना, जानवरों की सुरक्षा, पशु रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा की प्रशिक्षा, डेरियो (Dairies) का प्रशासन एवं समाज-सेवाएँ जिनमें पिछड़ी जातियों व उनके क्षेत्रों की उन्नति भी सम्मिलित है, इस विभाग के प्रमुख विषय हैं।

(24) पंचायत एवं विकास विभाग—राज्य की समस्त सामुदायिक विकास एवं अन्य विकास योजनाओं को संगठित करना, पंचायतों की समस्याओं का हल, उनका प्रशासन एवं अन्य स्थानीय विकास कार्यों पर नियंत्रण इस विभाग के अन्तर्गत प्रमुख विषय हैं।

(25) राजस्थान नहर योजना विभाग—पंजाब व राजस्थान में आर्थिक झान्ति लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण, नहर से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति, मिन्धु-जल-मन्त्रि का प्रशासन एवं राजस्थान नहर निगम का कार्य इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है।

(26) मन्त्रि-परिषद् सचिवालय (Cabinet Secretariate)—राजस्थान सचिवालय में इस विभाग का बहुत महत्व है। इस विभाग में सरकारी कार्यों में अधिक संगठन एवं कार्य-कुशलता सम्भव होती है।

मन्त्रि-परिषद् की समस्त सभाओं, वैधानिक समझौतों, राजस्थान राज्य के अन्य राज्यों व केन्द्रीय सरकार में सम्बन्ध, राज्यपाल व राज-भवन में सम्बन्धित सभी कार्य, मन्त्रियों की नियुक्ति सम्बन्धी बातें, क्षेत्रीय परिषदों की प्रशासन सम्बन्धी बातें, मुख्य मन्त्री, मन्त्रियों एवं मुख्य सचिव को आवश्यक जानकारी देना, जनसंख्या, कृषि उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुख बानों के बारे में आकड़े उकट्टे करना,

मन्त्रिमण्डल खण्ड को समय-समय पर बातों के बारे में जानकारी देना, दफ्तर के काम में संगठन एवं व्यवस्था (Organisation and Methods) का प्रबन्ध करना जिससे काम शीघ्र हो सके, सरकारी रिपोर्टों को तैयार करना तथा अन्य अविकारियों की रिपोर्टों का अध्ययन करना आदि कुछ ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो इस विभाग के अन्तर्गत आते हैं। प्रणामन की दृष्टि से यह सबसे प्रमुख भाग गिना जाता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- 1 राज्य के प्रणामन में विभागों की व्यवस्था पर एक लेख लिखिए।
- 2 अपने प्रदेश के विभिन्न प्रशासकीय सरकारी विभागों का वर्णन करिए।

विभाग का कार्य भी न्याय विभाग से मिलता-जुलता है। सरकार के विरुद्ध मुकदमों का लड़ना, विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह को इकट्ठा करके निर्णय लेना, कानूनी धन्धे से सम्बन्धित नियम बनाना, सरकारी वकीलों की नियुक्ति आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

(23) पशु-पालन एवं समाज कल्याण विभाग—पशुओं की नस्ल को उन्नत करना, जानवरों की सुरक्षा, पशु रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा की प्रशिक्षा, डेरियों (Dairies) का प्रशासन एवं समाज-सेवाएँ जिनमें पिछड़ी जातियों व उनके क्षेत्रों की उन्नति भी सम्मिलित है, इस विभाग के प्रमुख विषय हैं।

(24) पंचायत एवं विकास विभाग—राज्य की समस्त सामुदायिक विकास एवं अन्य विकास योजनाओं को संगठित करना, पंचायतों की समस्याओं का हल, उनका प्रशासन एवं अन्य स्थानीय विकास कार्यों पर नियंत्रण इस विभाग के अन्तर्गत प्रमुख विषय हैं।

(25) राजस्थान नहर योजना विभाग—पंजाब व राजस्थान में आर्थिक क्रान्ति लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण, नहर से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति, मिन्धु-जल-मवि का प्रशासन एवं राजस्थान नहर निगम का कार्य इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है।

(26) मन्त्रि-परिषद् सचिवालय (Cabinet Secretariate)—राजस्थान सचिवालय में इस विभाग का बहुत महत्व है। इस विभाग में सरकारी कार्यों में अधिक संगठन एवं कार्य-कुशलता सम्भव होती है।

मन्त्रि-परिषद् की समस्त भागों, वैधानिक समस्याएँ, राजस्थान राज्य के अन्य राज्यों व केन्द्रीय सरकार में सम्बन्ध, राज्यपाल व राज-भवन में सम्बन्धित सभी कार्य, मन्त्रियों की नियुक्ति सम्बन्धी बातें, क्षेत्रीय परिषदों की प्रशासन सम्बन्धी बातें, मुख्य मन्त्री, मन्त्रियों एवं मुख्य सचिव को आवश्यक जानकारी देना, जनसमस्या, कृषि उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुख बातों के बारे में आकड़े इकट्ठे करना,

मन्त्रिमण्डल खण्ड को समय-समय पर वानों के बारे में जानकारी देना, दफ्तर के काम में संगठन एवं व्यवस्था (Organisation and Methods) का प्रवन्ध करना जिससे काम शीघ्र हो सके, सरकारी रिपोर्टों को तैयार करना तथा अन्य अविकारियों की रिपोर्टों का अध्ययन करना आदि कुछ ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो इस विभाग के अन्तर्गत आते हैं। प्रणामन की दृष्टि में यह सबसे प्रमुख भाग गिना जाता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- 1 राज्य के प्रणामन में विभागों की व्यवस्था पर एक लेख लिखिए।
- 2 अपने प्रदेश के विभिन्न प्रणामकीय सरकारी विभागों का वर्णन करिए।

विभाग का कार्य भी न्याय विभाग से मिलता-जुलता है। सरकार के विरुद्ध मुकदमों का लड़ना, विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह को इकट्ठा करके निर्णय लेना, कानूनी धन्धे से सम्बन्धित नियम बनाना, सरकारी वकीलों की नियुक्ति आदि इस विभाग के प्रमुख कार्य हैं।

(23) पशु-पालन एवं समाज कल्याण विभाग—पशुओं की नस्ल को उन्नत करना, जानवरों की सुरक्षा, पशु रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा की प्रशिक्षा, डेरियों (Dairies) का प्रशासन एवं समाज-सेवाएँ जिनमें पिछड़ी जातियों व उनके क्षेत्रों की उन्नति भी सम्मिलित है, इस विभाग के प्रमुख विषय हैं।

(24) पंचायत एवं विकास विभाग—राज्य की समस्त सामुदायिक विकास एवं अन्य विकास योजनाओं को मगठित करना, पंचायतों की समस्याओं का हल, उनका प्रशासन एवं अन्य स्थानीय विकास कार्यों पर नियंत्रण इस विभाग के अन्तर्गत प्रमुख विषय हैं।

(25) राजस्थान नहर योजना विभाग—पंजाब व राजस्थान में आर्थिक क्रान्ति लाने वाली राजस्थान नहर का निर्माण, नहर से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति, सिन्धु-जल-संधि का प्रशासन एवं राजस्थान नहर निगम का कार्य इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है।

(26) मन्त्रि-परिषद् सचिवालय (Cabinet Secretariate)—राजस्थान सचिवालय में इस विभाग का बहुत महत्व है। इस विभाग में सरकारी कार्यों में अधिक मगठन एवं कार्य-कुशलता सम्भव होती है।

मन्त्रि-परिषद् की सम्मेलन मभाएँ, वैधानिक समस्याएँ, राजस्थान राज्य के अन्य राज्यों व केन्द्रीय सरकार में सम्बन्ध, राज्यपाल व राज-भवन में सम्बन्धित सभी कार्य, मन्त्रियों की नियुक्ति सम्बन्धी बातें, क्षेत्रीय परिषदों की प्रणामन सम्बन्धी बातें, मुख्य मन्त्री, मन्त्रियों एवं मुख्य सचिव को आवश्यक जानकारी देना, जनमर्यादा, कृषि उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि प्रमुख बातों के बारे में आकड़े इकट्ठे करना,

खण्ड (Sub-division) तहसीलो में विभाजित है। प्रत्येक तहसील के अन्तर्गत कई गाँव शामिल हैं।

जिले के अधिकारीगण

प्रत्येक जिले में एक उच्च अधिकारी होता है, जिसे जिलाधीश अथवा कलक्टर कहते हैं। उप-खण्डों में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा तहसीलों में तहसीलदार होते हैं। यद्यपि राजस्थान में खण्ड-व्यवस्था को कायम रखा गया है लेकिन खण्ड-कमिश्नर (Divisional Commissioner) के पद को समाप्त कर दिया गया है। कलक्टर ही जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसका राज्य सरकार से सीधा सम्बन्ध होता है।

जिले का मचने बड़ा अफसर होने के नाते यह कलक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वह जिले में प्रशासन की सभी शाखाओं का काम सुचारु रूप से चलाये। राजस्थान में नावारणत अखिल भारतीय प्रशासन सेवा (I A S) के व्यक्ति कलक्टर नियुक्त किये जाते हैं। कलक्टर का मुख्य काम भूमि-कर सम्बन्धी झगड़ों के निबटारे में सम्बन्धित है। वह जिले में शान्ति स्थापित रखता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है। इसके अतिरिक्त कलक्टर को विकास सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम भी करना पड़ता है और लोकतयात्मक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात् वह पचायती राज मन्थाओं के लिए मित्र, दार्शनिक एवं पय-प्रदर्शक सभी कुछ है।

कलक्टर (जिलाधीश) जिला स्तर पर होने वाले सभी सरकारी कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर नियुक्त अन्य अधिकारियों के बीच तालमेल रखना जिलाधीश का ही काम है। उने जिला स्तर पर होने वाले कार्य, और कार्य करने वाले सभी पदाधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार है। वह

इन अधिकारियों से निकट का सम्बन्ध स्थापित रखता है ताकि जिले का सम्पूर्ण प्रशासन एकवद्ध, सुचारु रूप से चल सके ।

जिले के अन्य अधिकारी

जिलाधीश के अतिरिक्त जिले के अन्य मुख्य अधिकारियों में, सुपरिण्टेण्डेंट ऑफ पुलिस, जिले का मुख्य न्यायाधीश (District and Session Judge), मुख्य चिकित्सक (Civil Surgeon), एकजीक्यूटिव इंजीनियर तथा इस्पेक्टर आब स्कूल होते हैं । पुलिस का मुख्य अधिकारी सुपरिण्टेण्डेंट ऑफ पुलिस है जो जिलाधीश के साथ कार्य करते हुए जिले में कानूनी व्यवस्था एवं शान्ति स्थापित रखने में योग देता है । मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के अन्तर्गत कार्य करता है । मुख्य चिकित्सक के अधिकार में जिले के सारे चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरीज होती हैं । जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसके लिए उचित व्यवस्था बनाये रखना मुख्य चिकित्सक का ही कार्य है । एकजीक्यूटिव इंजीनियर जिले में निर्माण कार्य की देख-रेख करता है और जिला स्तर पर जन-निर्माण विभाग का कार्य सम्पादन करता है । डिस्ट्रिक्ट इस्पेक्टर ऑफ स्कूल के अन्तर्गत जिले में स्थित सभी प्राइमरी स्कूल एवं मिडिल स्कूल आ जाते हैं । इन स्कूलों का उचित प्रबन्ध बनाये रखना तथा शिक्षा प्रदान करने की इन मस्थाओं में व्यवस्था और शिक्षा के स्तर को कायम रखना इसी का काम है ।

उपरोक्त उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त जिले में और भी कुछ अधिकारी-गण होने हैं जैसे जिला आंकडा अधिकारी, न्याय अधिकारी, उप-जिला विकास अधिकारी आदि । खण्ड विकास योजनाओं के प्रारम्भ होने के फलस्वरूप बहुत से नये पदों का निर्माण किया गया है, जैसे विकास अधिकारी तथा उनके अन्तर्गत अन्य सहायक अधिकारी आदि । पचायती राज्य व्यवस्था कायम हो जाने के बाद बहुत-से गैर-सरकारी पदों का निर्माण भी हुआ । जिले के स्तर पर जिला परिषद् का निर्माण

हुआ, जिसका प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है। इन संस्थाओं का विस्तृत वर्णन राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत किया गया है। यहाँ यह कहना ही पर्याप्त होगा कि कलक्टर के हाथों में सम्पूर्ण जिले का प्रशासन है। ये गैर-सरकारी पदाधिकारी भी जिले के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं।

कलक्टर के पद का मूल्यांकन

ब्रिटिश शासन काल में कलक्टर राज्य-सत्ता का प्रतीक था और जिले के मुख्य अधिकारी के रूप में वह जनता की दृष्टि में 'मान्य' सरकार का एक अंग होने के कारण डर से उत्पन्न श्रद्धा का पात्र बन गया था। जिले में उसका प्रभाव अतुलनीय था। राज्य की सरकार के लिए जिलाधीश 'आँख और कान' की तरह था। राज्य की सरकार जिला स्तर पर जिलाधीश की मन्त्रणा से कार्य करती थी। अब जनतन्त्रात्मक सरकार की स्थापना के पश्चात् जिलाधीश के पद के प्रति डर से उत्पन्न श्रद्धा का भाव प्रायः नष्ट हो गया है। अब वह सत्ता का केवल यन्त्र न होकर विकास और साधारण जनता के हित में अधिक से अधिक सुविधाएँ प्रदान करने का एक साधन बनता जा रहा है। जिला स्तरीय प्रशासन की सम्पूर्ण कार्य-विधि में एक आधारभूत परिवर्तन आ गया है। जिलाधीश, प्रमुख तथा जिले के अन्य अधिकारी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर कार्य करते हुए जिला प्रशासन के इतिहास में एक नये अध्याय की रचना कर रहे हैं।

ग्रन्थासार्थ प्रश्न

1. जिले के प्रशासन में तुम क्या समझते हो? जिले की शासन व्यवस्था में कलक्टर का क्या स्थान है?

स्थानीय प्रशासन

स्थानीय स्वशासन-व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं है। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन का वर्णन करने से पहिले हमें यह जानना आवश्यक है कि यह व्यवस्था सम्पूर्ण भारत में किस प्रकार प्रारम्भ हुई, और अब यह किस अवस्था में पहुँच चुकी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि राजस्थान में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसी प्रकार पनपी है जैसे कि भारत के अन्य भागों में विशेष कर देहातो में। पचायत प्रथा सारे भारत की तरह राजस्थान में भी पाई जाती थी। राज्य केवल सुरक्षा और मालगुजारी वसूल करने के कार्य तक सीमित रहता था। स्थानीय शासन साधारणतः स्थानीय सस्थाओं की जिम्मेदारी थी। परन्तु जमींदारी प्रथा के प्रचलन के पश्चात् विशेषकर केन्द्रित शासन व्यवस्था के पनपने के फलस्वरूप स्वशासन पिछले दो सौ वर्षों में प्रायः नष्ट हो चला था। विशेषकर इसका प्रभाव ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पर पड़ा था।

स्थानीय स्वशासन सस्थाओं का पुनः पनपना शहरों और नगरों में आरम्भ हुआ। आरम्भ में इन सस्थाओं का गठन सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों द्वारा होता था। तत्पश्चात् कुछ सदस्य भी चुने जाने लगे, यद्यपि जिन्हें मताधिकार दिया गया था उनकी मर्यादा बहुत थोड़ी हुआ करती थी। जन-जन मनोनीत व्यक्तियों का स्थान चुने हुए व्यक्ति लेने लगे और मताधिकार प्राप्त जनता की मर्यादा में वृद्धि होने लगी। जहाँ तक इन मर्यादों के अधिकार-क्षेत्र का प्रश्न है, वह प्रारम्भ में अत्यन्त सीमित था, परन्तु धीरे-धीरे इन मर्यादों की उपयोगिता एवं प्रतिनिधि

स्वरूप के विकास के साथ-साथ इनका अधिकार-क्षेत्र भी विकसित होता गया । स्थानीय स्वशासन की समस्याएँ जो उच्च स्तर पर थी और उन समस्याओं में जो निम्न स्तर पर कार्य करती थी कोई पारस्परिक सम्बन्ध नहीं था । इसका मतलब यह है कि उस समय स्थानीय स्वशासन अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तरह से पाया जाता था । उनका कोई एक स्वरूप नहीं था । सरकार के कड़े नियन्त्रण के अन्तर्गत इन्हे कार्य करना पड़ता था । ब्रिटिश राज्य के अन्तिम युग में कहीं जाकर इन स्थानीय समस्याओं को कुछ स्वतन्त्र विचार और कार्य करने की क्षमता मिल गई थी ।

राजस्थान बनने से पहले रजवाड़ों में स्थानीय स्वशासन विभिन्न रूपों में पाया जाता था । प्रत्येक रजवाड़ा अथवा रियासत अपनी-अपनी व्यवस्था रखती थी । जबकि कुछ रियासतों में कई गाँवों को मिलाकर एक पचायत तथा शहरों में नगरपालिकाएँ थी तो अन्य कई रजवाड़ों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी । कुछ रियासतों में ग्रामों की स्थानीय स्वशासन की समस्याओं के रूप में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी थे । 1956 ई० में राजस्थान पचायत एक्ट स्वीकार किया गया और उसके लागू होने के साथ-साथ सारे राजस्थान में पचायतें स्थापित की गईं । नगरपालिकाएँ भूतपूर्व रियासतों के प्रमुख शहरों में पहले से थी । 1951 ई० में राजस्थान टाउन म्यूनिसिपल एक्ट स्वीकार किया गया, जिसके अन्तर्गत बड़े-बड़े और प्रमुख नगरों को छोड़कर अन्य कस्बों और शहरों की नगरपालिकाएँ आ गईं । इसके फलस्वरूप यह सभी नगरपालिकाएँ एक कानून के अन्तर्गत संगठित की जाने लगी और उनका स्तर समान हो गया । 1956 ई० में राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट पास किया गया और प्रमुख शहरों की नगरपालिकाएँ भी इस कानून के अन्तर्गत व्यवस्थित की गईं । जनतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली को देश में अपनाने का यह एक स्वाभाविक नतीजा था कि स्थानीय स्वशासन की समस्याओं को और अधिक बल मिले और उनका विस्तार किया जाये । सत्ता का विकेन्द्री-

करण जनतन्त्र को निम्न स्तर तक ले जाने का एक मही तरीका है। इसी ध्येय को दृष्टि में रखते हुए, वलवन्तराय मेहता कमेटी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में 1959 ई० में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति एक्ट स्वीकार किया गया और 2 अक्टूबर, 1959 ई० को सम्पूर्ण राजस्थान में जनतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था लागू किया गया। इस प्रकार शहरो, नगरो और गाँवों में स्थानीय स्वशासन वास्तविक रूप में स्थापित हुआ।

अब हम स्थानीय स्वशासन की इन संस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन करेंगे।

नगरपालिका

कस्बों और शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को नगरपालिका, नगर परिषद् अथवा नगर निगम कहते हैं। राजस्थान में प्रमुख नगरों में नगर परिषद् हैं और माधारण छोटे शहरों अथवा कस्बों में नगरपालिकाएँ। नगरपालिका एवं नगर परिषद् के संगठन एवं कार्य और अधिकारों में कोई आधारभूत अन्तर नहीं होता। स्थानीय स्वशासन की इन संस्थाओं का नामकरण नगर की जनसंख्या पर निर्भर है। 8,000 जनसंख्या वाले नगर में नगरपालिका और 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर परिषद् होती है। बहुत बड़े शहरों में निगम होते हैं। आटे हम नगरपालिका के संगठन एवं कार्य-क्षेत्र के बारे में विचार प्रारंभ करें।

संगठन - यदि किसी नगर की जनता यह माँग करे कि उसे नगरपालिका चाहिए, तो सरकार वह नगरपालिका के संगठन की व्यवस्था करती है। नगरपालिका के निम्न वयस्क मतधिकार के आधार पर प्रत्येक तीसरे वर्ष चुनाव कराये जाते हैं। चुनाव 'गुप्त' मतदान द्वारा होता है। चुनाव के निम्न नगर तो बोर्ड्स (क्षेत्रों) में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यदि

किसी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों का बहुमत होता है तो वह क्षेत्र इन जातियों के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्रों में से केवल इन जातियों का प्रतिनिधि ही चुनाव लड़ सकता है। स्त्रियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यदि चुनाव में कोई स्त्री जीतकर न आई हो तो नगरपालिका के चुने हुए सदस्य दो स्त्री सदस्यों को मनोनीत करते हैं इस प्रकार चुने हुए तथा मनोनीत सदस्य नगरपालिका गठित करते हैं।

पदाधिकारी—नगरपालिका के सदस्य अपने आप में से एक सदस्य को नगरपालिका का अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। राज्य की सरकार नगर परिषद् के मुख्य अधिकारी म्यूनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति करती है, नगरपालिका में इस अधिकारी को एक्जीक्यूटिव आफ़ीसर कहते हैं।

नगरपालिका अपने अन्य कर्मचारियों की स्वयं नियुक्ति करती है।

अधिकार—नगरपालिका अपने कार्य को मुचारु रूप से चलाने के लिए कर लगाती है। मकान-कर, सामान के आवागमन पर कर और व्यवसाय-कर नगरपालिकाओं को लगाना आवश्यक है। कुछ कर ऐसे भी हैं जिन्हें लगाना अनिवार्य नहीं है परन्तु यदि नगरपालिका चाहे तो ये कर लगाये जा सकते हैं। इनमें मोटरो पर कर, नावों पर कर तथा आवागमन के अन्य साधनों पर कर शामिल हैं। नगरपालिकाओं की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए राज्य सरकार ऋण और कभी सहायता के रूप में धन नगरपालिकाओं को देती रहती है।

कार्य—नगरपालिकाओं का कार्य नगरों अथवा शहरों में सफ़ाई, रोशनी, पानी, स्वास्थ्य-रक्षा आदि का इन्तजाम करना है। नगरपालिका नगर की सड़कों को ठीक रखती है, नई सड़कें बनवाती है। नगर में वाग-वगीचे लगवाना और इनकी देखभाल करना भी नगरपालिका का

काम है। शिक्षा का प्रसार तथा उसके लिए स्कूल स्थापित करना और उन्हें चलाना भी नगरपालिका के कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित है। वास्तव में नगर के सम्पूर्ण जीवन को सुचारु रूप से चलाना नगरपालिका की कार्य-कुशलता पर निर्भर है।

गांवों में स्थानीय स्वशासन

खण्ड विकास योजनाओं के लागू होने से पहले पंचायतों का कार्य-क्षेत्र स्थानीय छोटे-छोटे भूखंडों को सुलभाने तथा अपने अधिकार के क्षेत्र को साधारण नागरिक प्रशासन तक सीमित था। परन्तु खण्ड विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इन पंचायतों का उपयोग किया जाने लगा। इस प्रकार पंचायतों के पास साधारण कानूनी अधिकारों के साथ-साथ योजनाओं को स्थानीय रूप से कार्यान्वित करने का काम भी सौंपा गया। परन्तु बलबन्त राय मेहता कमेटी रिपोर्ट के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार एक ही संस्था के पास होने से उनका कार्य सुचारु रूप में चलना असम्भव था। इसलिए कमेटी ने राय दी कि न्यायपालिका का कार्य किसी स्वतन्त्र संस्था को सौंप देना चाहिए। पुरानी पंचायतें जो कि बड़े गांवों को मिलाकर मण्डल की गई थीं कमेटी की राय में एकत्व की भावना जाग्रत करने में असमर्थ थीं। इसलिए उसने छोटी पंचायतें बनाने का सुझाव दिया। इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान सरकार ने छोटी पंचायतें बनाई और न्याय पंचायतों की अलग व्यवस्था की। अब पंचायतों का मण्डल निम्न प्रकार है —

पंचायतों का मण्डल—पहले 4,000 से 8,000 तक जनसंख्या के ऊपर एक पंचायत होती थी। नई व्यवस्था के अनुसार 1,500 से 2,000 तक जनसंख्या पर एक पंचायत है। एक पंचायत में पंचों की संख्या 8 से 15 तक होती है। पंचायतों के लिए चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष में होते हैं। पंचायतों का क्षेत्र नितने पंच चुनते हैं उनमें वाटों में विभाजित कर दिया

जाता है। प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि राजस्थान विधान सभा के चुनाव-क्षेत्र का रहने वाला है जिसमें वह पचायत स्थित है, पच चुनाव लड़ सकता है। परन्तु वह व्यक्ति मत उसी वार्ड में दे स है जिसमें उसका घर हो। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने अधिकार है।

सरपंच—प्रत्येक पचायत में एक सरपंच होता है जो कि प क्षेत्र के तमाम मताधिकारियों द्वारा चुना जाता है। सरपंच पचायत बैठक बुलाता है और बैठक की अध्यक्षता भी वही करता है। पच के कोष के लिए भी वही जिम्मेदार होता है। वही घन एकत्रित है और पचायत के निर्णय के अनुसार उसे खर्च करता है। पचायत इलाके में योजनाओं को कार्यान्वित करना उसी की देख-रेख में होता है।

प्रत्येक पचायत में एक सचिव होता है जो कि दफ्तर के काम देखभाल करता है।

पचायतो के कार्य—पचायत का कार्य-क्षेत्र विस्तृत है। अधिकार में नागरिक सुधार का कार्य, प्रशासन एवं विकास सम् सभी कार्य आ जाते हैं। पचायत पैदावार बढ़ाने के लिए योज बनाती है और अपने क्षेत्र में रहने वालों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शि आराम और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास के सुविधाएँ प्रस्तुत करती है। गाँवों में एकत्व स्थापित करने वड़े-वड़े कामों में अधिकतम नागरिकों का पक्ष प्राप्त करने की उ श्यकता पर बल देते हुए इस बात की व्यवस्था की गई है कि विकास वड़े-वड़े कामों को हाथ में लेने से पूर्व पचायत के क्षेत्र के निवा के ३ व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त किया जावे। ऐसे वड़े-वड़े कार्यों में में कुएँ खुदवाना, नई इमारतें बनवाना तथा शौचालय आदि का नि करता है।

ग्राम सभा

लोकतंत्र को निम्न स्तर तक पहुँचाने के लिए पंचायत कानून के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पंचायत वर्ष में कम से कम दो बार अपने क्षेत्र की कुल जनसंख्या की बैठक बुलाये। इन बैठकों को ग्राम सभा कहते हैं। इन बैठकों में पंचायतों के कार्यों का सिद्धान्तोक्त किया जाता है और आगामी योजनाओं की रूपरेखा पर विचार-विनिमय करके उन्हें स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास में स्वयं सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है।

पंचायतें कर लगाकर घन एकत्रित करती हैं। इन करों में यातायात के साधनों पर कर, चीजों के आवागमन पर कर, सिचाई-कर, पशुओं के चरागाहों पर कर, मकानों पर कर आदि सम्मिलित हैं।

पंचायतों के पास अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की व्यवस्था होती है। पंचायत अपने कर्मचारियों की स्वयं नियुक्ति करती है।

न्याय पंचायत

5 में 7 पंचायतों के ऊपर एक न्याय पंचायत होती है। इन न्याय पंचायतों का मार्ग-पीट के भगटों में सम्बन्धित तथा माली दोनों प्रकार के मुकदमों में मुनने और उस पर निर्णय देने का अधिकार है। न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव उनके अन्तर्गत आने वाली पंचायतों करती है। प्रत्येक पंचायत को एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। न्याय पंचायत तीन-तीन सदस्यों की समितियों द्वारा कार्य करती है। न्याय पंचायत का सम्पत्ति, उसके सदस्य आपस में ही किसी को चुन लेते हैं। राजस्थान में इस समय 1,369 न्याय पंचायतें हैं।

मार्गपीट के भगटों के निचले स्तर में न्याय पंचायत 50 ₹० तक जुर्माना कर सकती है और 250 ₹० तक के माली मुकदमों में उनके मामले पेज किये जा सकते हैं। न्याय पंचायत के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती

यद्यपि इन फैसलों पर पुनः दृष्टिपात मुमकिन अथवा प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है।

पंचायत समिति

पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायत समिति का अत्यन्त ऊँचा स्थान है। पूर्व स्थित विकास खण्डों के आधार पर पंचायत समितियों का संगठन किया गया है। योजनाओं और विकास के क्षेत्र में ये पंचायत समितियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और योजनाओं के निर्माण में योग देती हैं।

संगठन—एक पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाली तमाम पंचायतों के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। उस विकास खण्ड में रहने वाले कृषि-पंडित एवं कृषि-निपुण भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। इनके अनिरीकृत यदि कोई स्त्री पंचायत समिति की सदस्य नहीं है तो दो स्त्रियों को सदस्य बनाया जाता है। इसी प्रकार दो अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि, दो अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधि, दो प्रशासन क्षेत्र में निपुण व्यक्ति, एक सहकारी समितियों का प्रतिनिधि और एक ग्रामदान गाँव का प्रतिनिधि भी पंचायत समिति के सदस्य अपनाये जाते हैं। इन सदस्यों को अपनाया जाना पंचायत समिति के अन्य सदस्य गुप्त मतदान द्वारा करते हैं।

प्रधान—पंचायत समिति के समस्त सदस्य मिलकर अपने आप में से एक को प्रधान चुनते हैं। प्रधान का चुनाव भी गुप्त मतदान द्वारा होता है। चुनाव के समय पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता जिलाधीश अथवा उनके द्वारा मनोनीत अन्य कोई अधिकारी करता है।

पंचायत समिति का कार्य-काल तीन वर्ष होता है।

पंचायत समिति के कार्य—अपने क्षेत्र में समस्त विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने का भार पंचायत समिति का है। पंचायत समिति अपने कार्य को मुचारु रूप से चलाने के लिए स्थाई समितियों

ग्राम सभा

लोकतंत्र को निम्न स्तर तक पहुँचाने के लिए पंचायत कानून के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पंचायत वर्ष में कम से कम दो बार अपने क्षेत्र की कुल जनसंख्या की बैठक बुलाये । इन बैठकों को ग्राम सभा कहते हैं । इन बैठकों में पंचायतो के कार्यों का सिंहावलोकन किया जाता है और आगामी योजनाओं की रूपरेखा पर विचार-विनिमय करके उन्हें स्वीकार किया जाता है । इस प्रकार पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास में स्वयं सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाता है ।

पंचायते कर लगाकर घन एकत्रित करती हैं । इन करों में यातायात के साधनों पर कर, चीजों के आवागमन पर कर, सिचाई-कर, पशुओं के चरागाहों पर कर, मकानों पर कर आदि सम्मिलित हैं ।

पंचायतो के पास अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की व्यवस्था होती है । पंचायत अपने कर्मचारियों की स्वयं नियुक्ति करती है ।

न्याय पंचायत

5 में 7 पंचायतो के ऊपर एक न्याय पंचायत होती है । इन न्याय पंचायतों का मार्ग-पीट के भण्डो में सम्बन्धित तथा माली दोनों प्रकार के मुकदमों में मुनने और उस पर निर्णय देने का अधिकार है । न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव उसके अन्तर्गत आने वाली पंचायतें करती हैं । प्रत्येक पंचायत को एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है । न्याय पंचायत तीन-तीन सदस्यों की समितियों द्वारा कार्य करती है । न्याय पंचायत का मरपत्र, उसके सदस्य आपस में ही किसी को चुन लेते हैं । राजस्थान में इस समय 1,369 न्याय पंचायतें हैं ।

मार्गपीट के भण्डो के निपटारे में न्याय पंचायत 50 ₹० तक जुर्माना कर सकती है और 250 ₹० तक के मामलों में मुकदमों के मामले पेश किये जा सकते हैं । न्याय पंचायत के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती

यद्यपि इन फैमलो पर पुन दृष्टिपात मुसिक अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कर सकता है ।

पंचायत समिति

पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत पंचायत समिति का अत्य ऊँचा स्थान है । पूर्व स्थित विकास खण्डों के आधार पर पंचायत समितियों का संगठन किया गया है । योजनाओं और विकास के दृष्टि में ये पंचायत समितियाँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और योजना के निर्माण में योग देती हैं ।

संगठन—एक पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाली तम पंचायतों के सरपंच पंचायत समिति के सदस्य होते हैं । उस विकास खण्ड में रहने वाले कृषि-मजदूर एवं कृषि-निपुण भी पंचायत समिति सदस्य होते हैं । इनके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री पंचायत समिति सदस्य नहीं है तो दो स्त्रियों को सदस्य बनाया जाता है । इसी प्रकार दो अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि, दो अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधि, दो प्रजामन क्षेत्र में निपुण व्यक्ति, एक महकारी समिति का प्रतिनिधि और एक ग्रामदान गाँव का प्रतिनिधि भी पंचायत समिति के सदस्य अपनाये जाते हैं । इन सदस्यों को अपनाया जाना पंचायत समिति के अन्य सदस्य गुप्त मतदान द्वारा करते हैं ।

प्रधान—पंचायत समिति के नमस्त सदस्य मिलकर अपने आप में एक को प्रधान चुनते हैं । प्रधान का चुनाव भी गुप्त मतदान द्वारा होता है । चुनाव के समय पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता जिनायीश अथवा उनके द्वारा मनोनीत अन्य कोई अधिकारी करता

पंचायत समिति का कार्य-काल तीन वर्ष होना है ।

पंचायत समिति के कार्य—अपने क्षेत्र में समस्त विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने का भार पंचायत समिति का है । पंचायत समिति अपने कार्य को नुसार रूप से चलाने के लिए न्याई समिति

का निर्माण करती है। प्रत्येक स्थाई समिति में सात से अधिक सदस्य नहीं होते। पचायत समिति अपने अधिकारों को इन समितियों को उनके कार्यों के अनुरूप सौंप देती है। समितियों के निर्णय पचायत समिति के निर्णय समझे जाते हैं, परन्तु पचायत समिति को यह अधिकार है कि वह स्थाई समितियों के फैसलों को रद्द कर दे अथवा उनमें संशोधन कर दे।

पचायत समितियों की श्राय—पचायत समिति की आय भूमि-कर उद्योग पर कर, शिक्षा-कर, मेलों और उत्सवों पर कर, मनोरंजन कर आदि से होती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है और उन विकास योजनाओं की पूर्ति के लिए रुपया भी राज्य सरकार देती है जो पचायत समिति को सौंप दी गई हों। राज्य सरकार रुपया बर्ज भी देती है।

प्रत्येक पचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विकास अधिकारी होता है जो कि प्रधान की सहायता करता है और पचायत समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को कार्यान्विन करता है। इसके अतिरिक्त विकास कार्य में सहायता देने अथवा निपुण सम्मति प्रदान करने के लिए कई अन्य अधिकारीगण भी होते हैं।

जिला परिषद्

जिले के स्तर पर जिला परिषद् होती है। इसके सदस्यों में जिले की तमाम पचायत समितियों के प्रधान, जिले में चुने गये विधान सभा के सदस्य तथा लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य होते हैं। उनके अतिरिक्त दो मंत्री, एक महत्वागी समितियों का प्रतिनिधि और यदि उन जिले की जनसंख्या 5% या उससे अधिक अनुसूचित जातियों की संख्या हो और उनका कोई प्रतिनिधि जिला परिषद् का सदस्य न बन सके तो उनका एक प्रतिनिधि गुप्त मतदान द्वारा सदस्य बनाया जाता है। यह मतदान जिला परिषद् के अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद् भी जिला परिषद् का सदस्य होता है परन्तु उसे मत

देने का अधिकार नहीं होता है। प्रत्येक जिला परिषद् में एक सचिव होता है जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है।

जिला परिषद् के कार्य—जिला परिषद् को कार्यपालिका के कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। उसका कार्य केवल पंचायत समितियों के कार्यों पर निगरानी रखना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त पंचायत समितियों और राज्य सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित करना भी जिला परिषद् का काम है। जिला परिषद् पंचायत समितियों द्वारा निर्मित योजनाओं के आधार पर सम्पूर्ण जिले के लिए योजना बनाती है।

प्रमुख—जिला परिषद् का एक प्रमुख होता है जिसका चुनाव जिला परिषद् के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा करते हैं। यह गैर-अधिकारी पक्ष का नेता होता है और पंचायत समितियों से सम्पर्क स्थापित रखता है। यह लोकतन्त्र की वृद्धि के लिए अच्छी परम्पराओं को स्थापित करने में सहायक होता है। जिला परिषद् के अध्यक्ष की स्थिति में यह सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में मदद देता है। पंचायत समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का निरीक्षण करके प्रमुख जिला परिषद् को पंचायत समितियों की गति-विधि से अवगत कराता रहता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. स्थानीय प्रशासन पर एक लेख लिखिए।
2. नगरपालिकाओं का स्थानीय प्रशासन में क्या स्थान है ?

न्यायिक-प्रशासन

भारत में न्यायपालिका की शृंखला में सबसे ऊँचा स्थान उच्चतम न्यायालय का है। हमारे राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन ही अपना काम करता है। अपने देश की न्याय-व्यवस्था की उपमा हम एक पर्वत से यदि दें तो उच्चतम न्यायालय को हम पर्वत का उच्च शिखर कह सकते हैं। उच्च न्यायालय के दिये गये निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में अपील मनुता है —

(क) सवैधानिक अपीलें—उच्च न्यायालय यदि किसी मुकदमे के सम्बन्ध में यह कहे कि इसमें मविधान की किसी धारा के उच्च अर्थ के विषय में शका की गई है तो ऐसे मुकदमे के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील मनी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय स्वयं प्रार्थनापत्र के आधार पर इस प्रकार की आज्ञा दे सकता है। दोनों ही परिस्थितियाँ में उच्चतम न्यायालय मविधान की व्याख्या करता है।

(ख) फौजदारी अपीलें—तीन प्रकार की परिस्थितियों में फौजदारी अपीलें मनी जा सकती हैं—

(1) यदि किसी अपराधी के मुक्त करने के आदेश को कोई न्यायालय उसे मृत्यु-दण्ड में बदल दे तो उस सम्बन्ध की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।

(2) यदि कोई उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय में मुकदमा मँगार उसी मृत्यु-दण्ड में बदल दे तो उसी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।

(3) यदि उच्च न्यायालय किसी मुकदमे के बारे में यह सिद्ध कर दे कि इसमें कोई महत्वपूर्ण कानूनी समस्या पेश की गई है तो ऐसे मुकदमे के निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।

(ग) दीवानी मुकदमे सम्बन्धी अपीलें—दीवानी मुकदमों के सम्बन्ध में दो प्रकार की अपीलें उच्चतम न्यायालय में की जा सकती हैं। यदि कोई उच्च न्यायालय यह सिद्ध कर कर दे कि अमुक मुकदमे की राशि का मूल्य 20,000 रु० में अधिक है तो ऐसी स्थिति की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि अमुक मुकदमा बहुत महत्वपूर्ण है तो ऐसे मुकदमे की अपील उच्चतम न्यायालय में हो सकेगी।

उच्चतम न्यायालय सारे देश के लिए एक ही है और दिल्ली में स्थित है।

उच्च न्यायालय

राज्य का सबसे मुख्य न्यायालय उच्च न्यायालय है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय भी भाँति नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करता है।

उच्चतम न्यायालय का संगठन व न्यायाधीशों की योग्यताएँ

एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दूसरे न्यायाधीश होते हैं। उन न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी यह राष्ट्रपति ही निश्चित करता है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। इसमें मुख्य न्यायाधीशों के सहित 10 न्यायाधीश हैं। इनमें 2 अतिरिक्त जज भी शामिल हैं।

किसी भी व्यक्ति को किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करना जरूरी होता है जैसे—

(1) वह भारत का नागरिक हो।

(2) कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी न्याय सम्बन्धी पद पर रहा हो, या

(3) राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगभग 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो ।

न्यायाधीशों का कार्य-काल, वेतन तथा भत्ते

62 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश अपने पद पर कार्य कर सकता है । परन्तु इसके पूर्व भी वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है । यदि समद के दोनों भवनों के सदस्य अलग-अलग दो-तिहाई बहुमत से किसी न्यायाधीश को दुराचारी सिद्ध करते ह तो राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 4,000 रु० वेतन और अन्य भत्ते तथा अन्य न्यायाधीशों को 3,500 रु० वेतन और अन्य भत्ते दिये जाते हैं । यह वेतन और भत्ते उनके कार्य की अवधि में कम नहीं किये जा सकते ।

उच्च न्यायालय के अधिकार

प्रत्येक उच्च न्यायालय के दो प्रकार के कार्य होने हैं—

(1) न्याय सम्बन्धी अधिकार, और

(2) प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार ।

(1) न्याय सम्बन्धी अधिकार—न्याय सम्बन्धी अधिकारों को दो भागों में बांटा जा सकता है—

(क) प्राग्भिक क्षेत्राधिकार, और (ग) अपीलिय क्षेत्राधिकार ।

(क) प्राग्भिक क्षेत्राधिकार—कौन-कौन से मुकदमे उच्च न्यायालय सुनता उनका जिल्ला मविधान में नहीं किया गया है । परन्तु मविधान बनने के पश्चात् बलरत्ता, बम्बई, मद्रास के उच्च न्यायालय प्राग्भिक क्षेत्राधिकारों का भोग करने थे, वैया अब भी होता है । उन क्षेत्र में वे दीवानी मुकदमे हों हैं जिनमें गफीफा जदालना में पक्ष नहीं किया जा सकता और वे फाजदारी मुकदमे आते हैं, जिनका फैसला मेहनत जज

की अदालत में नहीं होता । मूल अधिकार सम्बन्धी मुकदमे विशेष रूप से उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में आते हैं । ये मुकदमे या तो उच्च न्यायालय सुनता है या उच्चतम न्यायालय । व्यवहार में उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे कम ही सुनता है ।

(ख) अपीलीय क्षेत्राधिकार—इस अधिकार के अन्तर्गत उच्च न्यायालय दीवानी, फौजदारी और माल सम्बन्धी सभी प्रकार के मुकदमों की अपील सुनता है । इसके साथ उच्च न्यायालय को यह भी अधिकार है कि अपने पास के किसी भी न्यायालय का कोई मुकदमा मँगाकर उसकी छानबीन करे ।

(2) प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार—उच्च न्यायालयों को यह अधिकार होता है कि वह अपने पास के न्यायालयों का उचित रूप में प्रबन्ध करें तथा इनके कार्यों का निरीक्षण करे । उच्च न्यायालय निम्नलिखित तरीकों से उनका निरीक्षण करता है ।

(1) उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय से किसी भी मुकदमे के कागज मँगाकर उसकी जाँच कर सकता है ।

(2) उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह न्यायालय के लिए ऐसे नियम बनाये जिनसे उनका काम आसानी से चल सके ।

(3) उच्च न्यायालय इस सम्बन्ध में भी नियम बना सकता है कि किसी भी न्यायालय को किन मुकदमों का रिकार्ड रखना चाहिए ।

(4) उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, उनके वेतन में कमी और छुट्टी आदि के सम्बन्ध में भी नियम बनाने का अधिकारी है ।

(5) उच्च न्यायालयों को अधिकार है कि वह एक न्यायालय का मुकदमा दूसरे न्यायालय में भेज दे ।

(6) उच्च न्यायालय मूलाधिकार को पुनः स्थापित करने हेतु राज्य के कर्मचारियों को अपना आदेश दे सकता है । यदि कोई व्यक्ति

गैर-कानूनी ढंग से जेल में बन्द कर दिया गया हो तो उसे यह छड़वा सकता है।

(7) कोई भी न्यायालय विना उच्च न्यायालय की आज्ञा के किसी भी व्यक्ति को फाँसी की सजा नहीं दे सकता।

इस प्रकार हमने देखा कि उच्च न्यायालय अपने अधिकारों के कारण काफी महत्व का स्थान न्याय के क्षेत्र में रखता है।

न्यायिक प्रशासन के लिए राज्य को 16 भागों में विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक एक डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज (District and Session Judge) के अधीन है। ये जज दोनों प्रकार के फौजदारी एवं दीवानी मुकदमों में सुनते हैं। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजों के अधीन निम्नलिखित अदालतें हैं

(1) डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन अदालत	16
(2) मिजिल एण्ड एडीशनल सेशनल कोर्ट	17+1 (अस्थायी)
(3) मिजिल जज की अदालत	28
(4) स्माल काउजेज कोर्ट	4
(Small Causes Court)	
(5) मु सिफ और मु सिफ मजिस्ट्रेट	97+2 (अस्थायी)
(6) स्पेशल (रेनवे) मजिस्ट्रेट	3

योग = 168

राजस्थान न्यायिक सेवा (Rajasthan Judicial Service) दो भागों में विभक्त है। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा और राजस्थान न्यायिक सेवा। राजस्थान उच्च न्याय सेवा में 40 पद हैं। राजस्थान न्यायिक सेवा में 148 पद हैं।

(1) मिनम्बर मन् 1962 का आंशिक रूप में न्यायपालिका को कार्य-पालिका में प्रवेश करने का काम प्रारम्भ किया गया। एडीशनल

कलक्टर के 17 पदों के स्थान पर एक सिविल जज और तीन मु सिफ मजिस्ट्रेट की अदालतें स्थापित की गईं ।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बाद न्याय पचायतें भी बनाई गई हैं जो छोटे-छोटे दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निर्णय करती हैं ।

माल सम्बन्धी मुकद्दमे

माल सम्बन्धी मुकदमों से लिए राज्य का बोर्ड आफ रेवेन्यू (Board of Revenue) सबसे ऊँचा न्यायालय है । इसके निर्णयों के विरुद्ध हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में सवैधानिक प्रश्नों के सम्बन्ध में अपील की जा सकती है ।

बोर्ड आफ रेवेन्यू के नीचे माल सम्बन्धी मुकदमों के लिए निम्न-लिखित अदालतें हैं —

- (1) कलक्टर की अदालत—जिला स्तर पर
- (2) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट—सब-डिविजन स्तर पर
- (3) तहसीलदार की अदालत—तहसील स्तर पर
- (4) नायब तहसीलदार की अदालत—तहसील स्तर पर

ग्रन्थासार्थ प्रश्न

1. उच्च न्यायालय किन-किन दशाओं में अपील मुनता है एवं उसके अधिकारों का वर्णन करिए ।
2. राजस्थान न्यायिक सेवा पर एक टिप्पणी लिखिए ।

भाग 4

राजस्थान में नियोजित विकास

राजस्थान में नियोजन

मनुष्य के मुख, शान्ति, समृद्धि व सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि गरीबी, बीमारी, बेकारी, अज्ञानता को दूर किया जाये। प्रत्येक राज्य का आदर्श है कि हर नागरिक को खाना, कपड़ा, काम, मकान व जीवन की सुरक्षा के साधन प्राप्त हों जिनसे वे अवसर प्राप्त हों जो व्यक्तिगत व सामूहिक विकास के लिए अत्यावश्यक हैं। समाज की प्रगति, आर्थिक समानता व राजनैतिक जाग्रति के और कोई सार्थक माध्यम नहीं हैं। समाज की गिरी व्यवस्था व अवस्था को सुधारने का और कोई रास्ता नहीं है। इतना स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति की भलाई व बढ़ोतरी में ही समाज का वैभव व राज्य का उत्कर्ष निहित है। इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुभव व विचारों के आधार पर यह मित्र हो चुका है कि सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए ऐसी योजना की परम आवश्यकता है जिससे विधिवत् व व्यवस्थित रूप में सामूहिक विकास के कार्य पूर्ण किये जाये।

यह कहावत सत्य है कि चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। देश की प्रगति के लिये भी यही सत्य है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि 'चादर' को घटाने का प्रयत्न ही नहीं किया जाये, क्योंकि जितनी बड़ी चादर होती जायेगी उतना ही विस्तृत क्षेत्र हमें अपने पैर फैलाने को मिलेगा। इसी प्रकार यदि प्रत्येक राज्य में जनता की बढ़ोतरी होती रहे तो अवश्य ही सामूहिक विकास की भी प्रगति होगी।

जैसे—एक परिवार की समृद्धि आय और व्यय के सतुलन पर निर्भर है, उसी प्रकार एक देश की प्रगति व विकास, योजना और व्यवस्थित साधनों पर आश्रित है। आयोजित विकास जैसे एक परिवार के लिए आवश्यक है उसी प्रकार एक देश के लिए भी।

ठीक उसी प्रकार राजस्थान की प्रगति के लिये भी आयोजन की व्यवस्था है जो भारत के योजना कार्यक्रम का ही अंग है। समाज को सर्वांगीण रूप से व्यवस्था में लाने का यह उपाय अनुभव व बौद्धिक तर्क की कसौटी पर पूरा उतरता है।

सम्पूर्ण देश की व्यवस्था के अनुरूप राजस्थान में भी प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार विविध क्षेत्रों में प्रगति की गई। कृषि-प्रधान राज्य होने के कारण, राजस्थान में भी कृषि उत्पादन को बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है तथा इस दिशा में सफलता प्राप्ति के लिये चक्रवर्ती के कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है। पशु नस्ल सुधार, पशु भोजन व्यवस्था व बीमारी की रोकथाम के लिये प्रयास किये गये। 1961 तक 16 आदर्श ग्राम खण्ड खोले गये और गौशालाओं व पशु-चिकित्सालयों की संख्या में विशेष वृद्धि हुई।

प्रथम व द्वितीय योजनाओं के कार्यक्रम के अनुसार सहकारिता के अन्तर्गत 6,000 सहकारी समितियों का गठन हुआ। 103 प्राथमिक मार्केटिंग समितियाँ बनाई गईं। राजस्थान वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई व 32 वेयर-हाउस बने। 97 संयुक्त कृषि सहकारी समितियाँ बनीं। मेवा सहकारी समितियों की संख्या 3,893 हो गई। छोटी समितियों की व्यवस्था में सुधार किये गये। नावर्जनिक आर्थिक विकास व व्यवस्था के लिये राजस्थान औद्योगिक सहकारी बैंक की स्थापना की गई।

वन-विकास व भू-रक्षण के क्षेत्र में विशेष प्रयास किये गये। मैट्रन गमिंग जॉन एम्प्टीट्यूट की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मछली-रक्षा, पालन व विकास के लिये कार्य किये गये तथा सहकारी समितियों द्वारा उत्साहजनक फल प्राप्त हुए ।

राज्य की भूमि को सुधार कर, कृषि-विकास में सहायक नहरों के विकास के लिये कदम उठाये गये । पूर्व गंगा नहर, भाखरा व चम्बल की बहुउद्देशीय योजना, मध्य व छोटी सिंचाई योजनायें—सबसे राज्य को लाभ पहुँचा ।

सामुदायिक विकास के क्षेत्र में भी, इसी प्रकार, महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये जिनसे ग्रामीण जीवन में कृषि, पशु-पालन, सिंचाई, सहकारिता, भूमि-सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विभिन्न उद्योग-वन्धे व यातायात के साधनों का विकास किया गया । सामूहिक विकास के लिए पंचायत सहकारी समितियों, पाठशालाओं, युवक मंडल, महिला मंडल आदि के सार्थक माध्यम द्वारा रचनात्मक कार्य किये गये । विभिन्न स्थानों पर विजली की व्यवस्था की गई । इस प्रकार उत्पादन की बढ़ोत्तरी हुई ।

राज्य के विकास के साधनों में मंडको को बनाया जाना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधायें, जल-वितरण, गृह-निर्माण योजना, समाज कल्याण, पिछड़ी जातियों का उद्धार और श्रमिक-कल्याण की गति-विधियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

तीसरी योजना, अन्य राज्यों की ही भाँति, पहली दो योजनाओं पर काफी अंश में निर्भर है तथा इस दिशा में यह कहना असंगत नहीं होगा कि जो कमियाँ पहले रह गई थीं उनको पूर्ण करना है ।

तीसरी योजना की मुख्य रूपरेखा 26 जनवरी, 1960 को प्रकाशित की गई जिसका उद्देश्य लोक-तान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सस्थाओं द्वारा जन-कल्याण के आदर्श को रचनात्मक रूप देना था । योजना में प्राथमिकता, फिर एक बार, कृषि को दी गई है । तीसरी योजना के लिए 23,60,000 लाख रुपये की धनराशि का प्रबन्ध किया गया है । जिसे निम्न कार्यों में व्यय करने की व्यवस्था रखी गयी है ।

(1) कृषि उत्पादन

अन्न की कमी को ध्यान में रखते हुए 16 लाख टन अधिक खाद्यान्न उपजाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। इस अधिक खाद्यान्न की उपलब्धि के लिये रासायनिक खाद के उपयोग के अलावा हरी खाद का भी प्रयोग किया जायगा। इसके साथ ही साथ फसलों के सुरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में वर्तमान कृषि विद्यालयों में अधिक अनुसन्धान तथा शिक्षा के अतिरिक्त एक नया कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान है।

तीसरी योजना में कृषि विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रवृत्तियों के अन्तर्गत मिर्चाई की कुओ, नहर, नलकूप, तालाब इत्यादि के द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। इनके अतिरिक्त वर्तमान सिंचाई के साधनों को सुचारु रूप से कार्यशील रखने के लिए भी व्यवस्था है। मिर्चाई के अलावा खेती की चक्रवन्दी पर भी ध्यान दिया गया है। जोतो का विखण्डीकरण राज्य की कृषि-प्रगति में बाधक रहा है। अतः प्रदेश की 25 लाख एकड़ भूमि पर चक्रवन्दी करने का प्रस्ताव है। खेती के लिए अच्छे बीजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आदर्श ग्राम योजना गण्ड आरम्भ हो चुके हैं। हाट बाजारों को भी संगठित किया जायगा। राजकीय पशु-फार्म का विस्तार किया जायगा और ऐसे फार्म तीसरी योजना में और भी आरम्भ किये जा रहे हैं। पशुओं की उचित चिकित्सा के लिए प्रदेश भर में पशु औषधालय तथा पशु चिकित्सालय गठित जायेंगे।

मट्टनी पानन, वन तथा डियरी के अलावा महकाग्नि पर राज्य में अन्वेषित जाय दिया जायगा। राज्य के प्रत्येक गांव तथा 67 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में महकाग्नि का प्रसार करने का लक्ष्य रखा गया है। नया महकाग्नी समितियाँ, महकाग्नी कृषि समितियाँ तथा प्राथमिक भूमि दफ्तर बँट गाने जायेंगे। कृषि सुधार समितियों के सदस्यों का कृषि उत्पत्ति के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रावधान

लालबहादुर

शर्मा



क्रिया गया है। इसके अलावा सम्पूर्ण राज्य में सामुदायिक विकास मण्डल स्थापित करने तथा इसके अन्तर्गत पंचायती राज को बढ़ावा दिया जायगा।

(2) सिंचाई

वर्तमान विभिन्न सिंचाई कार्यों के पूरा होने पर लगभग 11 46 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि सींची जा सकेगी। सिंचाई कार्यक्रम राज्य के सिंचाई विभाग तथा राजस्थान नहर बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। राज्य में राजस्थान नहर परियोजना का निर्माण दो चरण में होगा। पहले चरण में राजस्थान फीडर का निर्माण किया जायगा। दूसरे चरण में मुख्य नहर का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के साथ हुई मिथु जल संधि के अनुसार भारत को सतलज, व्यास तथा रावी नदियों से पानी मिल सकेगा। राजस्थान नहर को व्यास तथा रावी के पानी पर निर्भर रहना होगा। व्यास परियोजना में व्यास नदी पर पोग बांध बनाना है। व्यास नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है जो उम बांध के निर्माण की सलाह देगा।

राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर-प्लान बना लिया गया है। इसमें नव प्रकार की विकास की प्रवृत्तियों का समावेश है।

लघु सिंचाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए धनराशि कृषि व सिंचाई विभागों द्वारा दी जाती है। कुओं के निर्माण, डीजल तेल में चलने वाले डजनों, बिजली की मोटरों के लिए, गांवों के तालाबों के विकास के लिए, वर्तमान कुओं को गहरा करने तथा नल कूपों को खोदने का विस्तृत कार्यक्रम है। वर्तमान कुओं को गहरा करने, निजी व राज्य के नलकूपों का निर्माण करने व भूमि व जल मण्डल योजनाएँ अण्डर-ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं।

25,000 रुपये या इससे कम खर्च के जो काम पंचायत समितियों द्वारा कराये जावेंगे उनके लिए तकनीकी सहायता देने को प्रत्येक जिले

मे एक इंजीनियर की नियुक्ति कर दी गई है। यह उस जिले की सभी पाचयत समितियों के सभावित कार्यों का सर्वेक्षण कर तखमीना तैयार करने में सहायता करेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना-काल में रपटो (एनीकट) के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। इनके निर्माण का अभिप्राय कुओं में जल के वर्तमान तल को ऊँचा उठाना है। क्योंकि पानी की कमी के कारण कुओं के सूख जाने की समस्या है। सरकार ध्यानपूर्वक विचार कर इसके कारणों तथा कुओं में पानी के स्तर को बढ़ाने के तरीकों की खोज करवा रही है।

राज्य की योजनाओं में सम्मिलित की गई योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित सिंचाई में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण और पानी के प्रयोग की भी योजना है।

(3) विद्युत-शक्ति

राजस्थान में उद्योग-वृद्धों को चलाने और उनको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचाने में सबसे बड़ी दिक्कत विद्युत के अभाव की है। लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए नगरों में बड़े कारखाने स्थापित करने व ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग चलाने की आवश्यकता है। राज्य में पानी का बहुत गहगाई पर मिलना भी एक समस्या है। वास्तव में हमारी समस्या विद्युत शक्ति की माँग पैदा करने की नहीं बल्कि माँग के अनुसार विद्युत उत्पन्न करने की है। उद्योग-वृद्धों की दृष्टि में पिछड़े हुए ऐसे राज्य के लिए जो आगे की ओर कदम बढ़ा रहा हो, यह एक पुनर्लक्षण है।

विद्युत योजना के उद्देश्य राजस्थान के पन विद्युत (हाईड्रल) के साधनों को पूर्ण उपयोग करना तथा तापीय विद्युत (थर्मल) का आवश्यकता के अनुसार विकास करना। जहाँ तक पन-विद्युत का सम्बन्ध है उपाय बनाये उद्देश्य की पूर्ति का मतलब है गंगा प्रताप नागर परिवोजना का पूर्ण होना व साटा और माही परियोजना का

काम आरम्भ होना जिससे चौथी पंचवर्षीय योजना काल में इनसे बिजली मिल सके। भाखरा परियोजना के दाहिने किनारे के बिजली घर से उत्पन्न होने वाली विद्युत का उपयोग भी इसी उद्देश्य की ओर बढ़ने में सम्मिलित है।

चम्बल क्रम से कोटा डिवीजन भुनभुनूँ व सीकर को छोड़कर सारे अजमेर डिवीजन और उदयपुर के चित्तौड़, भीलवाड़ा व उदयपुर जिलों को विद्युत मिलेगी। पाली होते हुए जोधपुर को भी चम्बल क्रम से जोड़ने के प्रस्ताव हैं। भाखरा से बीकानेर डिवीजन को भी विद्युत प्राप्त होगी। तापीय विद्युत के उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा बिजली घर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

राज्य के गाँवों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव है कि 5,000 व इससे अधिक जनसंख्या के गाँवों में तीसरी योजना में विद्युत लगाई जायेगी।

विद्युत के विकास पर तीसरी योजना में 35 करोड़ रु० खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रावधान में भाखड़ा नागल परियोजना, चम्बल परियोजना, तापीय बिजली परियोजना, ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम तथा विद्युत के संचरण तथा वितरण होने वाला व्यय भी शामिल है। इन सब के परिणामस्वरूप 3 51,000 किलोवाट विद्युत के उत्पादन की क्षमता की जायेगी।

(4) उद्योग-धन्धे तथा खनिज

उद्योग-धन्धे—जहाँ तक औद्योगीकरण का सम्बन्ध है, राजस्थान भारतवर्ष के कम विकसित क्षेत्रों में आता है। यहाँ औद्योगिक व्यवसाय, उत्पादन और रोजगारी दोनों ही दृष्टियों से कम महत्वपूर्ण हैं। लेकिन देश के आर्थिक विकास के सम्बन्ध में प्रादेशिक अनमानता को कम करने के उद्देश्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी यदि देश के उद्योग की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

राजस्थान में औद्योगिक प्रगति के लिए कच्चे माल व खनिज सम्पत्ति की बहुतायत है किन्तु विद्युत शक्ति की कमी, आवागमन के माधन व प्रशिक्षित मानव शक्ति की सीमित मात्रा में उपलब्धि के कारण यह सम्पत्ति पूरी तरह काम में नहीं ली जा सकती है। सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए उचित वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य में एक ठोस व उत्साह पूर्ण नीति अपनाई है व बहुत-सी रियायतों व सुविधाओं की घोषणा की गई है। राजस्थान की ओर जहाँ कि समृद्धि-शाली उद्योगों की संभावना है धीरे-धीरे उद्योगपति भी आकर्षित हो रहे हैं।

औद्योगिक सम्पदा निर्माण के लिए 157 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान उन उद्योगपतियों को सभी सम्भव सुविधाएँ प्रदान करेगा जो निजी क्षेत्र में उद्योग चलाने के इच्छुक हैं। राज्य द्वारा जहाँ तक समय हो उचित दरों पर आवश्यक विद्युत दिलाने, शीघ्र ही भूमि प्रदान कराने तथा विन्नी-कर चुगी-कर में छूट देने का भरसक प्रयत्न किया जायगा।

जिन स्थानों पर भविष्य में औद्योगीकरण की आशा की जाती है वहाँ तीसरी योजना में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा। मुख्यतः जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अजमेर, भरतपुर जिलों में तीसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्रों के अत्यधिक विकास की व्यवस्था की गई। ग्राम तथा न्यु-उद्योगों को भी बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है।

प्राथमिक शिक्षा—तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना कार्यान्वयन में शिक्षा-प्रसार मन्त्रालय निम्न उद्देश्य है —

(1) 6 से 11 वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं को शिक्षा-सुविधा देना।

(2) 11 से 14 तक की आयु के बालक-बालिकाओं को शिक्षा-मुक्ति देना ।

दोपहर को भोजन व मुफ्त पुस्तकें पाठशालाओं में दी जायेंगी । दोपहर में स्कूल में ही दूध देने की व्यवस्था का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया गया है । वर्तमान मिडिल पाठशालाओं, मीनियर बुनियादी शालाओं तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को और मजबूत बनाया जावेगा तथा उनकी क्षमता बढ़ाई जावेगी ।

माध्यमिक शिक्षा—तीसरी योजना के अन्तर्गत 14 से 17 वर्ष की आयु के 113 प्रतिशत विद्यार्थियों को शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्तमान मिडिल शालाओं तथा उच्च शालाओं को उच्चतर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित किया जायगा ।

विश्वविद्यालय शिक्षा—इस योजना-काल में जोधपुर में दूसरे महा-विद्यालय की स्थापना की जायेगी । वर्तमान महाविद्यालयों में नवीन विषय पढ़ाये जायेंगे । विदेशी भाषाओं की शिक्षा मुक्तिदायक देने का भी प्रस्ताव है । गुणोत्कृष्ट विद्यार्थियों को देश में उपलब्ध सर्वोत्तम शिक्षा दिलाने का भी प्रस्ताव किया गया है ।

समाज-शिक्षा के कार्यक्रम का जिला स्तर पर समन्वय किया गया है । जिला पुस्तकालयों में सुधार किया जायेगा । समाज शिक्षा के क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष महत्व दिया जायगा । इसके अलावा संस्कृत शिक्षा, प्राचीन अभिलेखों का मुद्रण, पुरातत्व संग्रहालय तथा ललित कला अकादमियों पर ध्यान दिया जायगा ।

तकनीकी शिक्षा—तीसरी योजना में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए 331 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । योजना काल में संचालनालय तकनीकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा बोर्ड को सुदृढ़ बनाने के प्रस्ताव हैं । वर्तमान इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा पॉलिटेक्निक के क्षमता बढ़ाने तथा नये महाविद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव किये गये हैं ।

खनिज—खनिज की दृष्टि से राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। भारत में बुनियादी उद्योगों के लिए आवश्यक लोहा, कोयला आदि खनिज बहुतायत से मिलते हैं किन्तु भारत की अलौह खनिज जैसे ताँबा, जस्ता, सीसा आदि की कमी को राजस्थान ही पूरा कर सकता है। तीसरी योजना में 365 लाख रुपये उनके विकास के लिए प्रस्तावित किये गए हैं। खनिज उत्पादन में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इसलिये छोटे खानों के मालिकों को 'न लाभ न हानि' के आधार पर तकनीकी सहायता व आवश्यक उपकरण देने का विचार है। प्रयोगशाला की सुविधाएँ भी प्रयोग के लिए उपलब्ध की जायेंगी।

जैसलमेर क्षेत्र में तेल और गैस की खोज का कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस कमीशन ने एक फ्रामीसी फर्म के सहयोग से आरम्भ किया है।

(5) स्वास्थ्य

तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य कार्यों के अन्तर्गत लगभग 8 करोड़ रु० व्यय करने का प्रावधान किया गया है। उसके अन्तर्गत क्षेत्रीय और जिला अस्पताल का निर्माण तथा वर्तमान अस्पतालों में शैयाओं की वृद्धि का कार्य-क्रम है। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र प्रत्येक खण्ड में खोले जायेंगे। बीमारियों की रोकथाम के लिए विस्तृत स्फुरेखा तैयार की गई है। प्रत्येक जिले में टी० बी० के मरीजों को अलग रखने का प्रवन्ध किया जायगा। मरीजों का उन्मूलन कार्य-क्रम पर विशेष ध्यान दिया जायगा। सामाजिक प्रयोगशालाएँ, परिवार नियोजन केन्द्र, मातृ एवं शिशु-मृत्युता केन्द्र, स्थापित किये जायेंगे। चिकित्सा, शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्य-क्रमों पर योजना में विशेष महत्व दिया गया है। आयुर्वेदिक दवाइयों का महत्व प्रदान करने के लिए सारे प्रदेश में लगभग 300 आयुर्वेदिक व यूनानी औषधालय तीसरी योजना में खोले जायेंगे। उन्हीं अनिश्चित आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में उपकरणों की गिनती वगैरह उन्हें आधुनिक बनाया जायगा।

ग्राम जल-वितरण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव में 400 आदमियों पर एक साफ-सुथरा पानी पीने का कुआँ बनाना है। साथ ही साथ 5,000 की जन-संख्या वाले प्रत्येक ऐसे गांव के लिए नल योजना चालू की जायेगी जहाँ पानी की सतह 100 फीट गहरी हो। तीसरी योजना में 10,000 जन-संख्या वाले सब ही नगर नल-जल वितरण योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे। प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत फिटर्स, मैकेनिक व पम्प अपरेटर्स को प्रशिक्षण दिया जावेगा।

(6) यातायात

सड़क—यात्रियों के लिए सड़क से आरामदेह, उत्तम, पर्याप्त एवं कम खर्चीली यातायात सेवा को राजकीय नीति का एक आवश्यक अंग मान लिया गया है। ऐसा निश्चित किया गया है कि राजस्थान में सड़क यात्री-यातायात का राष्ट्रीयकरण कार्य 'ए' श्रेणी तक ही सीमित रखा जायेगा। राज्य की राजधानी को भूतपूर्व डिवीजनल मुख्यालयों तथा महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयों से मिलाने वाला मार्ग राष्ट्रीय जन-पथ, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जन-पथ तथा राज्य के बड़े कस्बों को पड़ोसी राज्यों के मुख्य कस्बों से मिलाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा।

तीसरी योजना में राजस्थान स्टेट रोडवेज पर किये जाने वाले खर्च के लिए धनराशि साधारण बजट में रखी गई है। पर्यटकों के लिए राजस्थान स्टेट रोडवेज पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योग देगी। पर्यटकों के लिए वातानुकूलित डीलक्स गाड़ियों तथा डीलक्स कारों के खरीदने का प्रावधान है।

रेलें—रेल-विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में राज्य की सीमा में से गुजरने वाली उदयपुर, हिम्मतनगर, हिन्दूमल-कोट, श्री गंगानगर रेलवे लाइनों बनाने का प्रावधान है। उदयपुर-गुजरात रेलवे लाइन बनाई जावेगी। खेतडी-बुरू को सीधी लाइन द्वारा

मिला देने का काम भी तीसरी योजना में होगा। खेतड़ी एक सघन खनिज क्षेत्र है।

डाक व तार—पहली दो योजनाओं में तारघरो व टेलीफोन आदि की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर की टेलीफोन व्यवस्था स्वचालित करने का निर्णय लिया गया है। डाकघानों की संख्या 5,000 तक बढ़ जायगी। तारघर 225 हो जायेंगे।

सड़कें—तीसरी योजना में सड़कों का कार्यक्रम नीचे लिखे उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए बनाया गया है —

(1) पांच हजार तथा इसमें अधिक जनसंख्या वाले सब गांवों को सड़कों द्वारा मिला देना।

(2) सड़कों द्वारा सब तहसील और मुख्यालयों को जिला मुख्यालयों से जोड़ना।

(3) नव-विकसित अथवा भविष्य में विकास होने वाले भागवरा नहर एवं राजस्थान नहर के क्षेत्रों में उपयुक्त सड़क-सुविधा देने की प्रगति को जारी रखना।

(4) धातु एवं पत्थर की खानों के क्षेत्र को जोड़ना।

(5) राज्य मार्ग तथा जिले की मुख्य सड़कों पर डामर बिछाना।

(6) पुल बनाकर राज्य मार्ग और जिले की मुख्य सड़कों को हर मौसम योग्य बनाना।

तीसरी योजना में इस प्रकार कुल 3,136 मील सड़कों का निर्माण होगा।

(7) गृह-निर्माण

तीसरी योजना में गन्दी घमियों में 1,200 मकान बनाने का विचार है। ग्रामीण गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ग्रामवासियों को नये मकान बनाने तथा पुराने मकानों को सुधारने के लिए ऋण दिया जायगा।

योजना की अवधि में 400 नये गाँवों में इस कार्यक्रम का संचालन विकास विभाग के ग्रामीण गृह-निर्माण कक्ष द्वारा किया जा रहा है।

औद्योगिक वस्तियाँ बसाने के लिए दूसरी योजना में शुरू किये गये कार्यक्रमों पर कार्य जारी रहेगा तथा 90 अन्य योजनाएँ तीसरी योजना के अन्तर्गत इन वस्तियों के निर्माण के लिए बनाई गई हैं।

प्राथमिकताओं के आधार पर निम्न कार्यों को पहले पूरा किया जायगा —

- (1) राज्य की श्रम-शक्ति में जो बढ़ोतरी हुई है उसको कार्य में लाना।
- (2) कृषि के क्षेत्र में विकास व समृद्धि के लिए तत्पर उपाय।
- (3) सिंचाई में साधनों की उपलब्धि।
- (4) विद्युत शक्ति का विकास।
- (5) नि शुल्क, अनिवार्य शिक्षा की सुविधा।
- (6) पीने के पानी की सुविधाजनक योजना।
- (7) पशु-धन विकास।
- (8) खनिज सम्पत्ति का उपयोग।
- (9) तकनीकी ज्ञान का विकास।
- (10) उद्योग-धन्धों का विकास।
- (11) गृह-निर्माण योजनाओं को पूरा करना।
- (12) यातायात के साधनों का विकास।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि पहली दो योजनाओं में राजस्थान में प्रगति के चिन्ह मिलें तथा तृतीय योजना का कार्यक्रम विकास व प्रगति का प्रतीक है। व्यक्तिगत कल्याण व सामूहिक विकास क्षेत्रों में योजनाबद्ध व्यवस्थित कार्य ही सार्थक मित्र होंगे, इसमें दो रायें नहीं हो सकती। भारतवर्ष की समाजवादी समाज की धारा की रचनात्मकता केवल योजना से ही सम्भव है। यदि कुछ कमियाँ रह जाती हैं तो भी

योजना का स्थान कोई अन्य माध्यम नहीं ले सकता । वास्तव में सामूहिक प्रगति के रचनात्मक माध्यम को ही हम योजनावद्ध विकास कहते हैं ।

यह सत्य है कि व्यक्तिगत विकास व सामूहिक समृद्धि रचनात्मक योजना पर आधारित है । चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे राज्य में—व्यक्तिगत क्षेत्र में, बिना योजना के किसी भी प्रकार से विकास सम्भव नहीं है । विशेष रूप से भारतवर्ष के लिये, जबकि हमारा इतिहास इस बात का द्योतक है कि छिन्न-भिन्न व अव्यवस्थित राजनैतिक प्रवाह कार्य रूप में असफलता के प्रतीक हैं, यह अनिवार्य हो जाता है कि प्रजातन्त्र की सफलता आयोजन पर आश्रित हो ।

अध्यासार्थ प्रश्न

1. नियोजन से तुम क्या समझते हो ? अपने राज्य की तृतीय पंच-वर्षीय योजना की प्रगति पर एक लेख लिखिए ।

सामुदायिक विकास योजना, श्रमदान तथा सहकारी आन्दोलन

हमारा भारत पन्द्रह अगस्त, 1947 को स्वतन्त्र हुआ। इस प्रकार से हमारे देश ने राजनीतिक स्वराज्य प्राप्त किया। परन्तु राजनीतिक स्वराज्य जिसके फलस्वरूप हम स्वयं अपने देश के शासक बन गए केवल एक प्रारम्भिक कदम है। महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता संग्राम में हमें स्वराज्य की जिस कल्पना से प्रेरित किया, वह अभी अधूरी है। उनके अनुसार हमारे देश को पूर्ण स्वराज्य उम समय प्राप्त होगा जब वह आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी हो जाए और राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ ही सामाजिक पिछड़ेपन से भी मुक्ति पा ले। इस प्रकार से राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् हमारे लिए यह अनिवार्य हो गया कि हम देश के बहुमुखी विकास जिसमें स्वाभावतः ही आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति का महत्वपूर्ण स्थान हो, की ओर उन्मुख हो।

ग्रामीण विकास का महत्व—देश के बहुमुखी विकास का गहरा सम्बन्ध हमारे गाँवों से है। इसके कई कारण हैं—प्रथम, हमारे देश की 80% से अधिक जनता गाँवों में रहती है। इसीलिए महात्मा गाँधी कहा करते थे कि भारत गाँवों में रहना है। इस प्रकार से यदि उन्नति की प्रक्रिया केवल गाँवों तक सीमित रहती है तो सम्भवतः देश की विकास योजनाओं में ग्रामीण विकास को स्वतन्त्रता के पश्चात् महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना स्वाभाविक ही है। द्वितीय, अंग्रेजों के शासन-काल में गाँव के विकास की ओर विशेषकर अधिक ध्यान न दिया जा

सका । उन्होंने जो कुछ भी थोड़े बहुत कल्याणकारी काय किए वे बहुधा शहर तक ही सीमित रहे । इसीलिए गाँवों के विकास की समस्या और भी अधिक महत्वपूर्ण तथा कठिन हो गई । तृतीय, हमारे देश की अधिकांश जनता के गाँव में रहने के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था कृषि-प्रधान हो गई । गाँवों का विकास इसी कारण और भी आवश्यक हो गया है । गाँवों के विकास के साथ हमारे देश में उत्पादन के विकास की समस्या जुटी हुई है जिस पर खाद्य पदार्थों की उपलब्धि निर्भर है । अन्त में, हमारे ग्रामीण भाई तथा बहिने अज्ञानता के कारण पुराने विचारों वाले हैं, वे अब भी छूत-अछूत की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तथा स्त्रियों को पुरुषों के समान स्थान नहीं देते । साथ ही वे अपने वर्चों के जीवन में शिक्षा के महत्व को भी भली-भाँति नहीं समझते । गाँव वालों के इन प्राचीन विचारों के कारण न केवल उनके विकास में बाधा पड़ती है बल्कि सम्पूर्ण देश के विकास-क्रम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है । उन सब कारणों से भारत के विकास की योजना में ग्रामीण विकास का सर्वाधिक महत्व है ।

सामुदायिक विकास योजना—भारत ने प्रजातन्त्रीय समाजवाद के आदर्श को अपनाया और उसे प्राप्त करने के लिए नियोजित विकास का मार्ग ग्रहण किया । उस आचार पर हमारे देश में तीन पंचवर्षीय योजनाएँ बन चुकी हैं । दो पंचवर्षीय योजनाओं की यात्रा तय करके अब भारत तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में है तथा चौथी योजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है । हमारी तीनों ही योजनाओं में ग्रामीण विकास को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । इसके माध्यम मात्र सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को अपनाया गया जिसे उन कार्यक्रमों को करने के लिए पंचायती राज समितियों को सौंप दिया गया है ।

यह पता चल रहा है कि सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों की प्रेरणा हमें अमेरिका ने मिली जहाँ यह अधिक महत्व

रहा है और जहाँ पर इसने देश के कृषि सम्बन्धी विकास में बहुत अधिक योग दिया है। इसका उद्देश्य गाँव वालों को अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य बनाना तथा उनके द्वारा गाँवों में एक ऐसी सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्था का निर्माण करना था जो स्वयं गाँव वालों के परिश्रम तथा स्वनिर्भरता पर आधारित हो और जिसके लिए उन्हें राजकीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का मुँह न देखना पड़े। इस प्रकार से सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर ग्रामीणों तथा आत्मनिर्भर गाँवों का निर्माण करना था। इस प्रकार की आत्मनिर्भरता महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज्य की कल्पना का आधार थी।

सामुदायिक विकास योजना के लागू करते समय हमारे देश के नियोजनकर्ता यह भली-भाँति जानते थे कि आत्मनिर्भर गाँव और ग्रामीणों के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति अधिक कठिन है। शताब्दियों की दाम्मता के कारण गाँव वालों में सरकार को माँ-बाप समझने की प्रवृत्ति विद्यमान हो गई थी और इस प्रवृत्ति को बदलने में अधिक समय लगना स्वाभाविक है। इस कारण यह निश्चय किया गया कि प्रारम्भ में सरकार अपने कर्मचारियों के द्वारा सामुदायिक विकास योजना को कार्यान्वित करे और इनसे प्रेरणा लेकर गाँव वाले धीरे-धीरे अपने पैरों पर आप खड़ा होना सीख जाएँ।

सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के सम्बन्ध में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि प्रारम्भ में इसका गठ-बन्धन खाद्य पदार्थों के अधिक उत्पादन से था परन्तु जल्दी ही यह अनुभव हो गया कि सामुदायिक विकास को केवल कृषि से नहीं बाँधा जा सकता, उसे बहुमुखी रखना होगा। आज जब देश की खाद्य समस्या विगड़ रही है तब इस कार्यक्रम को कृषि-प्रधान तो बना दिया गया है, परन्तु अब भी इसका बहुमुखी स्वरूप चल रहा है।

राजस्थान में सामुदायिक विकास योजना—राजस्थान में अन्य राज्यों की भाँति सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर, 1952 में प्रारम्भ

की गई। प्रारम्भ में सात स्थानों पर इस कार्यक्रम को लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान में भी सरकार के पदाधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को उनके बहुमुखी विकास की ओर उन्मुख करना रहा। आज जब कि राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हो चुकी है, सामुदायिक विकास योजना के द्वारा जो सामुदायिक विकास के क्षेत्र (Blocks) निश्चित हुए थे वही विकेन्द्रीकरण का आधार है। राजस्थान में आज 232 सामुदायिक विकास से सम्बन्धित क्षेत्र हैं जिनमें से 23 विस्तार से पूर्व की स्थिति में, 98 प्रथम श्रेणी में, 91 द्वितीय श्रेणी में और 20 तृतीय श्रेणी में हैं।

सामुदायिक विकास योजना के फलस्वरूप गाँव वालों ने राजस्थान में खेती-बाड़ी के नये तरीके सीखे। सिंचाई की वैज्ञानिक व्यवस्था करना सीखा। अच्छे बीज और खाद की सहायता से उपज बढ़ाना सीखा। बच्चों की शिक्षा के महत्व को पहचाना साथ ही जीवन में सफाई की उपयोगिता भी जानी। इन सभी बातों में उनका रुढ़िवाद कमजोर पड़ा। इतना सब होते हुए भी वह अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होना न सीख पाए और सरकार का ही मुँह ताकते रहे। इस कारण बलवन्त रे मेहता गिपोर्ट ने यह निश्चय किया कि पंचायती राज के द्वारा जनता के प्रतिनिधियों को सामुदायिक विकास योजना को कार्यान्वित करने का काम सौंप दिया जाए जिससे वे अपने प्रतिनिधियों के नेतृत्व में रहकर अपने पैरों पर आप खड़ा होना सीख लें। इस प्रकार में राजस्थान, सामुदायिक विकास योजना से पंचायती राज की ओर बढ़ा।

जो कुछ भी सफलता सामुदायिक विकास योजना को पंचायती राज ने पूर्व हुई उम्मीदों के उन कर्मचारियों को है जो इसे लागू कर रहे थे। उनमें से प्रमुख हैं विकास अधिकारी, प्रमाण अधिकारी और ग्राम-सेवक। ये तीनों ही प्रशासकीय मण्डल की दृष्टि में सामुदायिक विकास योजना के वर्ग-प्रारंभ कहे जा सकते हैं। आज भी

पचायती राज मे इसी कारण इन कर्मचारियों का बहुत अधिक महत्व-पूर्ण स्थान है ।

राजस्थान मे श्रमदान—प्रारम्भ से ही यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि केवल सरकारी धन की सहायता से ही पिछड़े हुए गांवों की दशा नहीं सुधारी जा सकती । अतः गांव वालों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने श्रम का दान स्वयं अपने विकास के सम्बन्ध मे दे । यह दान हाथ-पैर की मेहनत के रूप मे, सामग्री आदि के दान के रूप मे और रुपये के रूप मे हो सकता है । प्रारम्भ मे श्रमदान ने नागरिकों को बहुत अधिक प्रेरित किया और उन्होंने बहुत अधिक सहयोग भी दिया । आज भी जबकि और क्षेत्रों मे उनका सहयोग कम होता जा रहा है, उन कार्यों के लिए जिनसे उनकी निकट की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह अब भी श्रमदान करने को तत्पर दिखाई देते हैं । परन्तु इस सत्य से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता कि पहले की तुलना मे श्रमदान के लिए उत्साह कम हो रहा है । प्रथम, श्रमदान से ग्रामीण उकता से गए हैं, अब वह उन्हें भार-सा लगने लगा है । अब श्रमदान की वह नवीनता जिसने उन्हें प्रेरित किया था, आकर्षित नहीं करती । द्वितीय, उनमे अब यह चेतना आ गई है कि शहर वालों से श्रमदान की माँग नहीं की जाती, इसलिए वह भी श्रमदान नहीं करना चाहते । तृतीय, श्रमदान गांवों के उच्च और घनाढ्य कुल के लोगों ने नहीं किया और इसलिए सामान्य मनुष्य अपने सन्दर्भ मे उसे बेगार की मज्जा देने लगे । अन्त मे, बढ़ते हुए स्वार्थ ने भी श्रमदान के आकर्षण को कम कर दिया तथा पचायती राज के आवरण मे जो गांवों मे नेता उत्पन्न हुए वे भी स्वार्थ से ऊँचे न उठ सके । उनके शक्ति की लालसा मे लिप्त होने के कारण वे गांव वालों को श्रमदान के लिए प्रेरित न कर सके ।

राजस्थान में सहकारी आन्दोलन

सहकारिता का अर्थ है माधारण रूप से मिल-जुल कर कार्य

करना । इसकी नींव पारस्परिक सहायता की पवित्र भावना पर स्थापित है । सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए मनुष्यता के नाते समानता के आधार पर स्वेच्छा से सम्मिलित होता है । इसकी अर्थ-प्रणाली जनतान्त्रिक है । नियोजन को लोकतन्त्रीय बनाने के लिए सहकारी संगठन को उपयुक्त तथा सर्वोत्तम माध्यम माना गया है ।

आज तो ममार के सभी देशों में, सभी प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाओं में सहकारी आन्दोलन का महत्व स्वीकार किया जाने लगा है । भारतीय लोकतन्त्र में इस आन्दोलन का महत्व कई दृष्टियों से बढत अधिक है । हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उद्देश्य अपने सामने रखा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहकारी व्यवस्था को बहुत बड़ा योग-दान देना होगा ।

भारतीय मविधान के अनुसार हमारे देश के आर्थिक संयोजन को स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के मूल्यों पर आधारित किया गया है और उनका प्राण है न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक । हमारी इन योजनाओं का मूल उद्देश्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें अवश्य पूरी हों । भारतीय समद ने घोषित किया है कि हमारी आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य होगा—“समाजवादी नमूने पर नये समाज की रचना करना ।” इस समाज की स्थापना तभी हो सकेगी जब भेनी और उद्योगों में हम सहकारिता को अपनाएँ । सभी हम उत्पादन को काफी बढा सकेंगे तथा बनी और निधन दोनों ही की आय का भी न्यायपूर्वक वितरण हो सकेगा । पहली और दूसरी योजना में देश के विभिन्न भागों में छोटे-बड़े कार्यक्रमों द्वारा इन उद्देश्यों को पूरा करने का यत्न किया गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना का भी मुख्य उद्देश्य महसूना पर आधारित समाजवादी समाज की रचना है । दूसरे शब्दों में हम बड़े तो भारत में सहकारी लोक राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें हर व्यक्ति को पचायतों और सहकारी मस्थाओं

से सहायता मिल सके तभी वह अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा हर प्रकार की उन्नति करने का समान अवसर पा सकेगा ।

समाजवादी समाज-रचना नगरो और गाँवों के क्षेत्रों में भी सम्पत्ति और आय की विषमताओं को दूर करने में जरूरी मदद करेगा । राष्ट्र-जीवन के तमाम अंगों में सहकारिता लागू करने से कुछ हद तक यह हो सकता है । अब तक सहकारिता को अधिकतर केवल खेती में ही आजमाने का यत्न किया गया है लेकिन आवश्यक है कि अब यह पद्धति बड़े-बड़े उद्योगों में भी लागू की जाय और फिर व्यापार, व्यवसाय, मजदूरी के ठेके और मकान बनाने के क्षेत्र आदि भी इसमें क्यों छूटे रहे । माराण यह है कि हम इस अच्छी पद्धति को जितने भी अधिक क्षेत्रों पर लागू कर सकें अवश्य करें, जिससे छोटे-छोटे उत्पादक और निर्धन उपभोक्ताओं का विशाल समाज शोषण से बच सके ।

देश को मजबूत नींव पर खड़ा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के गरीब से गरीब और कमजोर में कमजोर अंग—अर्थात् हरिजन और आदिवासियों—का ध्यान रखा जाय और यह सहकारिता से ही सम्भव है ।

भारतवर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य में सहकारिता को शिशु रूप की सजा दी जाय तो अनुचित नहीं होगा । पर फिर भी जब से रियासतों का विघटन हुआ है, राजस्थान में सहकारी विकास की ओर गतिशील कदम उठाया गया है । सहकारिता की, तीन पंचवर्षीय योजनाओं का राज्य के लोगों को समाजवादी समाज की ओर अग्रसर करने को बहुत योगदान रहा है । प्रथम योजना ने पृष्ठ-भूमि का निर्माण किया तथा सहकारिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता पहुँचाई । द्वितीय योजना में सहकारिता का कार्य-

करना । इसकी नींव पारस्परिक सहायता की पवित्र भावना पर स्थापित है । सहकारिता एक प्रकार का सगठन है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए मनुष्यता के नाते समानता के आधार पर स्वेच्छा से सम्मिलित होता है । इसकी अर्थ-प्रणाली जनतान्त्रिक है । नियोजन को लोकतन्त्रीय बनाने के लिए सहकारी सगठन को उपयुक्त तथा सर्वोत्तम माधन माना गया है ।

आज तो ससार के सभी देशों में, सभी प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाओं में सहकारी आन्दोलन का महत्व स्वीकार किया जाने लगा है । भारतीय लोकतन्त्र में इस आन्दोलन का महत्व कई दृष्टियों से बहुत अधिक है । हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उद्देश्य अपने सामने रखा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहकारी व्यवस्था को बहुत बड़ा योग-दान देना होगा ।

भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश के आर्थिक संयोजन को स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के मूल्यों पर आधारित किया गया है और उनका प्राण है न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक । हमारी इन योजनाओं का मूल उद्देश्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें अवश्य पूरी हों । भारतीय ममद ने घोषित किया है कि हमारी आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य होगा—“समाजवादी नमूने पर नये समाज की रचना करना ।” इस समाज की स्थापना तभी हो सकेगी जब बेरोज़गारी और उद्योगों में हम सहकारिता को अपनाएँ । अभी हम उत्पादन को काफी बढ़ा सकेंगे तथा बनी और निचन दोनों ही की आय का भी न्यायपूर्वक वितरण हो सकेगा । पहली और दूसरी योजना में देश के विभिन्न भागों में छोटे-बड़े कार्यक्रमों द्वारा उन उद्देश्यों को पूरा करने का यत्न किया गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना का भी मुख्य उद्देश्य सहकारिता पर आधारित समाजवादी समाज की रचना है । दूसरे शब्दों में हम कहें तो भाग्य ऐसे सहकारी नए राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें हर व्यक्ति को पचासों और सहकारी समस्याओं

से सहायता मिल सके तभी वह अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा हर प्रकार की उन्नति करने का समान अवसर पा सकेगा ।

समाजवादी समाज-रचना नगरों और गाँवों के क्षेत्रों में भी सम्पत्ति और आय की विषमताओं को दूर करने में जरूरी मदद करेगा । राष्ट्र-जीवन के तमाम अंगों में सहकारिता लागू करने से कुछ हद तक यह हो सकता है । अब तक सहकारिता को अधिकतर केवल खेती में ही आजमाने का यत्न किया गया है लेकिन आवश्यक है कि अब यह पद्धति बड़े-बड़े उद्योगों में भी लागू की जाय और फिर व्यापार, व्यवसाय, मजदूरी के ठेके और मकान बनाने के क्षेत्र आदि भी इसमें क्यों छूटे रहें । माराण यह है कि हम इस अच्छी पद्धति को जितने भी अधिक क्षेत्रों पर लागू कर सकें अवश्य करें, जिससे छोटे-छोटे उत्पादक और निर्धन उपभोक्ताओं का विशाल समाज शोषण से बच सके ।

देश को मजबूत नींव पर खड़ा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर अंग—अर्थात् हरिजन और आदिवासियों—का ध्यान रखा जाय और यह सहकारिता से ही सम्भव है ।

भारतवर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य में सहकारिता को शिशु रूप की मजा दी जाय तो अनुचित नहीं होगा । पर फिर भी जब में रियासतों का विघटन हुआ है, राजस्थान में सहकारी विकास की ओर गतिशील कदम उठाया गया है । सहकारिता की, तीन पंचवर्षीय योजनाओं का राज्य के लोगों को समाजवादी समाज की ओर अग्रसर करने को बहुत योगदान रहा है । प्रथम योजना ने पृष्ठ-भूमि का निर्माण किया तथा सहकारिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता पहुँचाई । द्वितीय योजना में सहकारिता का कार्य-

करना । इसकी नीव पारस्परिक सहायता की पवित्र भावना पर स्थापित है । सहकारिता एक प्रकार का सगठन है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए मनुष्यता के नाते समानता के आधार पर स्वेच्छा से सम्मिलित होता है । इसकी अर्थ-प्रणाली जनतान्त्रिक है । नियोजन को लोकतन्त्रीय बनाने के लिए सहकारी सगठन को उपयुक्त तथा सर्वोत्तम साधन माना गया है ।

आज तो ससार के सभी देशों में, सभी प्रकार की राजनैतिक व्यवस्थाओं में सहकारी आन्दोलन का महत्व स्वीकार किया जाने लगा है । भारतीय लोकतन्त्र में इस आन्दोलन का महत्व कई दृष्टियों से वर्धन अधिक है । हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उद्देश्य अपने सामने रखा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहकारी व्यवस्था को बहुत बड़ा योग-दान देना होगा ।

भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश के आर्थिक संयोजन को स्वतन्त्रता और लोक-तन्त्र के मूल्यों पर आधारित किया गया है और उनका प्राण है न्याय—सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक । हमारी इन योजनाओं का मूल उद्देश्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें अवश्य पूरी हों । भारतीय समद ने घोषित किया है कि हमारी आर्थिक नीति का मुख्य लक्ष्य होगा—“समाजवादी नमूने पर नये समाज की रचना करना ।” इस समाज की स्थापना तभी हो सकेगी जब गरीबी और उद्योगों में हम सहकारिता को अपनाएँ । सभी हम उत्पादन को काफी बढ़ा सकेंगे तथा घनी और निधन दोनों ही की आय का भी न्यायपूर्वक वितरण हो सकेगा । पहली और दूसरी योजना में देश के विभिन्न भागों में छोटे-बड़े कार्यक्रमों द्वारा इन उद्देश्यों को पूरा करने का यत्न किया गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना का भी मुख्य उद्देश्य सहकारिता पर आश्रित समाजवादी समाज की रचना है । दूसरे शब्दों में हम उन्हें तो भाग्य ऐसे सहकारी लोक राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें हर व्यक्ति को पचासों और सहकारी संस्थाओं

से सहायता मिल सके तभी वह अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा हर प्रकार की उन्नति करने का समान अवसर पा सकेगा ।

समाजवादी समाज-रचना नगरो और गाँवों के क्षेत्रों में भी सम्पत्ति और आय की विषमताओं को दूर करने में जरूरी मदद करेगा । राष्ट्र-जीवन के तमाम अंगों में सहकारिता लागू करने से कुछ हद तक यह हो सकता है । अब तक सहकारिता को अधिकतर केवल खेती में ही आजमाने का यत्न किया गया है लेकिन आवश्यक है कि अब यह पद्धति बड़े-बड़े उद्योगों में भी लागू की जाय और फिर व्यापार, व्यवसाय, मजदूरी के ठेके और मकान बनाने के क्षेत्र आदि भी इसमें क्यों छूटे रहे । सारांश यह है कि हम इस अच्छी पद्धति को जितने भी अधिक क्षेत्रों पर लागू कर सकें अवश्य करें, जिससे छोटे-छोटे उत्पादक और निर्धन उपभोक्ताओं का विशाल समाज शोषण से बच सके ।

देश को मजबूत नींव पर खड़ा करने के लिए यह भी आवश्यक है कि समाज के गरीब से गरीब और कमजोर से कमजोर अंग—अर्थात् हरिजन और आदिवासियों—का ध्यान रखा जाय और यह सहकारिता से ही सम्भव है ।

भारतवर्ष के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान राज्य में सहकारिता को शिशु रूप की मजा दी जाय तो अनुचित नहीं होगा । पर फिर भी जब से रियासतों का विघटन हुआ है, राजस्थान में सहकारी विकास की ओर गतिशील कदम उठाया गया है । सहकारिता की, तीन पंचवर्षीय योजनाओं का राज्य के लोगों को समाजवादी समाज की ओर अग्रसर करने को बहुत योगदान रहा है । प्रथम योजना ने पृष्ठ-भूमि का निर्माण किया तथा सहकारिता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता पहुँचाई । द्वितीय योजना में सहकारिता का कार्य-

क्षेत्र बढ़ा, समितियों की संख्या में वृद्धि हुई । राज्य ने ऐसे कार्यक्रम बनाए जो उसे अखिल भारतीय सहकारी व्यवस्था में अन्य राज्यों के समक्ष लाकर खड़ा कर देते हैं । उसके पश्चात् तृतीय योजना में सहकारिता की ओर अधिक व्यापक महत्व दिया गया है । राज्य की सहकारी योजना में इस बात का प्रयास दृष्टिगोचर होता है कि राज्य की कृषि उद्योग, उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को सहकारी आधार पर वास्तविक रूप से शुरू करने का प्रयत्न चल रहा है । इस समय तक कुल सहकारी समितियों की संख्या 20,420 है । 26,03,200 ग्रामीण परिवारों में 8,30,412 परिवार इसके अन्तर्गत हैं ।

सहकारिता के विकास में कई समस्याएँ भी सामने आई हैं । यह निश्चय किया गया कि ग्राम स्तर के आर्थिक तथा सामाजिक विकास का दायित्व पूर्ण रूप में ग्राम की सहकारी समिति व ग्राम पंचायत का होना चाहिए, परन्तु एक ही स्तर पर जब दो सक्रिय संस्थाएँ काम करती हैं तो चाह लक्ष्य से सम्बन्धित न हो, व्यवहार से सम्बन्धित भेद-भाव आ ही जाता है । दोनों में होड़ भी शुरू हो जाती है । आवश्यकता है दोनों को ही अपने-को-गाड़ी के दो पहिए मानने की । जिस प्रकार पंचायत ग्राम-सभा के प्रति उत्तर्दायी है, उसी प्रकार सहकारी समिति को भी उसके प्रति उत्तर्दायी होना होगा ।

महाराष्ट्र हमारे राष्ट्रीय विकास का अनिवार्य, आवश्यक एवं अग्रिम व्यापक आग्रह होना जा रहा है । सहकारिता ने राजस्ഥान में न केवल आर्थिक अभ्युदय के कार्य किये हैं वरन् राज्य के नागरिकों को और अधिक योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान की है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- 1 सामुदायिक विकास योजना से तुम क्या समझते हो ? देश के बहु-मुखी विकास में इसका क्या महत्व है ?
- 2 अपने प्रदेश में श्रमदान एवं सहकारी आन्दोलन की प्रगति पर एक लेख लिखिए ।

क्षेत्र बढ़ा, समितियों की संख्या में वृद्धि हुई । राज्य ने ऐसे कार्यक्रम बनाए जो उसे अखिल भारतीय सहकारी व्यवस्था में अन्य राज्यों के समक्ष लाकर खड़ा कर देते हैं । उसके पश्चात् तृतीय योजना में सहकारिता की ओर अधिक व्यापक महत्व दिया गया है । राज्य की सहकारी योजना में इस बात का प्रयास दृष्टिगोचर होता है कि राज्य की कृषि उद्योग, उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था को सहकारी आधार पर वास्तविक रूप से शुरू करने का प्रयत्न चल रहा है । इस समय तक कुल सहकारी समितियों की संख्या 20,420 है । 26,03,200 ग्रामीण परिवारों में 8,30,412 परिवार इसके अन्तर्गत हैं ।

सहकारिता के विकास में कई समस्याएँ भी सामने आई हैं । यह निश्चय किया गया कि ग्राम स्तर के आर्थिक तथा सामाजिक विकास का दायित्व पूर्ण रूप में ग्राम की सहकारी समिति व ग्राम पंचायत का होना चाहिए, परन्तु एक ही स्तर पर जब दो सक्रिय संस्थाएँ काम करती हैं तो चाह लक्ष्य में सम्बन्धित न हों, व्यवहार से सम्बन्धित भेद-भाव आ ही जाता है । दोनों में होठ मी शुरू हो जाती है । आवश्यकता है दोनों को ही अपने-अपने गाँव के दो पहिए मानने की । जिस प्रकार पंचायत ग्राम-सभा के प्रति उत्तरदायी है, उसी प्रकार सहकारी समिति को भी उसके प्रति उत्तरदायी होना होगा ।

सहायता हमारे राष्ट्रीय विकास का अनिवार्य, आवश्यक एवं अविभाज्य व्यापक आधार होना जा रहा है । सहकारिता ने राजस्थान में न केवल आर्थिक अभ्युदय के कार्य किये हैं बल्कि राज्य के नागरिकों को और अधिक योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान की है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- 1 सामुदायिक विकास योजना से तुम क्या समझते हो ? देश के बहु-मुखी विकास में इसका क्या महत्व है ?
- 2 अपने प्रदेश में श्रमदान एवं सहकारी आन्दोलन की प्रगति पर एक लेख लिखिए ।